राष्ट्रीय संस्करण

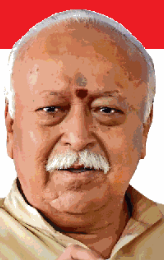

यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसहयोग जरूरी
>> 7

वर्ष 9 अंक 329

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 8 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

आपरेशन सिंदूर में पाक के 13 लड़ाकू विमान और 11 हवाई पट्टियां भारत ने की थीं तबाह

पाकिस्तान को गहरी चोट देने वाले इस आपरेशन के एक साल बाद पहली बार सामने आई यह जानकारी

आपरेशन सिंदूर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर तीनों सेनाओं का स्पष्ट संदेश - पाक में कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं
- एयर मार्शल भारती बोले- हमने पाक में नौ आतंकी कैंपों पर हमला किया था और उन्हें पूरी तरह तबाह किया
- पाक ने जब आतंकियों का साथ दिया तो हमारा जवाब बेह्द घातक था, मुंह की खाने के बाद उसने सीजफायर की मांग की

जयपुर में गुरुवार को आपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते (बाएं से) लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। आइएएनएस

पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत की ओर से सात मई से चलाए गए 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान और 11 हवाई पट्टियां तबाह की थीं। पाकिस्तान को गहरी चोट देने वाले इस आपरेशन के एक साल बाद पहली बार यह जानकारी सामने आई।

आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर वायुसेना, नौसेना व थलसेना ने गुरुवार को जयपुर में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर इस गौरवमयी उपलब्धि को देश से साझा किया। इस दौरान सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं है और यह मिशन तो बस एक शुरुआत है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा और अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा निर्णायक तरीके से करेगा।

जागरण संवाददाता के अनुसार, डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा,' सात मई को हमने पाकिस्तान में नौ आतंकी कैंपों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। इसका सुबूत सबके सामने है। हमने उनके 11 हवाई अड्डों पर हमला किया। कुल 13 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। 300 किलोमीटर से ज्यादा की रिकार्ड दूरी पर मौजूद एक हाई वैल्यू एयरबोर्न एसेट को भी नष्ट किया गया।' उन्होंने कहा-' पाकिस्तान हमे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। न तो किसी सैन्य ढांचे को और न ही लोगों को, वह चाहे कुछ भी दावा करें।'

प्रेट्र के अनुसार, एयर मार्शल ने कहा- " बार-बार सवाल उठता है कि हमने लड़ाई रोकने पर सहमति क्यों दी? असल में हमारी लड़ाई आतंकियों और उनके सहायक बुनियादी ढांचे से थी। हमने अपने सैन्य लक्ष्य को हासिल किया और हमारा मिशन पूरा हो चुका था। पर जब पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों का साथ देने का फैसला किया तो हमने भी उन्हें उन्हीं की भाषा में कड़ा जवाब दिया और वह बेहद घातक-निर्मम था। भारत ने कार्रवाई तब रोकी जब पाक की ओर से संघर्ष रोकने की मांग की गई। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा, भारतीय नौसेना की तैनाती के कारण पाक नौसेना-वायुसेना को अपने तटीय इलाकों तक सीमित रहना पड़ा।

आतंकवाद के विरुद्ध रक्षा का अधिकार हमारे पास : भारत पेज>>6

आपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरूआत : ले.जनरल घई

आपरेशन सिंदूर के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले सेना के तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरूआत है। हमारी कार्रवाई में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। रियल टाइम इंटेलिजेंस, साझा आपरेशन प्रणाली और मल्टी डोमेन रणनीति के जरिए सेना ने पीओके में नौ सटीक स्ट्राइकें कीं और 100 से अधिक आतंकवादी मार गिराए। कार्रवाई में 100 से अधिक पाकिस्तानी जवानों भी मारे गए।

आतंकवाद के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' दर्शाता है दृढ़ प्रतिक्रिया : मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'आपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर गुरुवार को कहा कि यह आपरेशन भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। (पेज-6)

ममता ने नहीं दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने भंग की विस

अनुच्छेद 174(2)(बी) के तहत राज्यपाल आरएन रवि का बड़ा कदम, गुरुवार आधी रात को समाप्त हुआ 17वीं विधानसभा का कार्यकाल

बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ, नौ मई को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण

शक्ति का प्रयोग

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

ममता बनर्जी। फाइल

आरएन रवि। फाइल

बंगाल की राजनीति में बीते 48 घंटों से जारी अभूतपूर्व संवैधानिक गतिरोध पर गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने विराम लगा दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की करारी शिकस्त और ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से स्पष्ट इन्कार के बीच, गुरुवार की शाम को राजभवन ने गजट अधिसूचना जारी कर वर्तमान विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसी के साथ नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। देश में यह संभवतः पहला मामला है जब चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद से किसी नेता ने इस्तीफा देने से साफ इन्कार किया हो और राज्यपाल को विधानसभा भंग करनी पड़ी हो।

अनुच्छेद 174 और 172 का मेल: क्या है इसके मायने? : राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा (2) के उप-खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सात मई, 2026 से विधानसभा को भंग किया जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार, अनुच्छेद 172 के तहत किसी भी विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से अधिकतम पांच वर्ष का होता है। 17 वीं बंगाल विधानसभा की मियाद सात मई की आधी रात को स्वतः समाप्त हो रही थी।

सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री हार के बाद इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के गठन होने तक 'केयरटेकर' (कार्यवाहक) के रूप में कार्य करते हैं। परंतु, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले ने राज्य को एक जटिल मोड़ पर खड़ा कर दिया था। ऐसे में राज्यपाल ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदन को भंग कर दिया, जिससे अब ममता तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक और कानूनी आधार खो चुकी हैं।

नौ मई को 'ब्रिगेड' में शपथ ग्रहण की तैयारी : विधानसभा भंग होने के साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, बहुमत प्राप्त दल के रूप में भाजपा नौ मई को रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने जा रही है। राज्यपाल जल्द ही बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देंगे। फिलहाल, बंगाल की सत्ता का केंद्र नवान्न (सचिवालय) से खिसक कर राजभवन की ओर बढ़ गया है, जहां अगले 48 घंटे राज्य की भविष्य की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे।

हावड़ा में तृणमूल-भाजपा समर्थकों में हिंसक झड़प, बमबाजी में एक दर्जन जख्मी पेज>>4

अखिलेश ने ममता से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं, हराई गई हैं पेज>>4

इस्तीफा नहीं देने पर अड़ी रहीं ममता

चुनाव नतीजों में भाजपा की 207 सीटों की ऐतिहासिक जीत और तृणमूल के दहाई अंकों में सिमटने को ममता बनर्जी ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। यह जनता का जनादेश नहीं बल्कि ईवीएम की लूट और केंद्रीय एजेंसियों की साजिश है। साफ किया कि वह इस लड़ाई को कानूनी रूप से कोर्ट और नैतिक रूप से सड़क पर लड़ेंगी।

शाह की मौजूदगी में आज विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा सीएम

कोलकाता : बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच रहे हैं। शाह की उपस्थिति में शुक्रवार को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। (पेज-4)

सुवेंदु के पीए की हत्या सुनियोजित थी, 50 सेकेंड में मारीं 10 गोलियां

कोलकाता: बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीएम चंद्रनाथ रथ की हत्या किए जाने की घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि इस आपरेशन को महज 50 सेकेंड में अंजाम दिया गया। हमलावरों ने आस्ट्रिया निर्मित पिस्तौल से 10 राउंड फायरिंग की थी। मौके से बरामद कारतूस की जांच से यह से यह बात पता चली है। (पेज-4)

लोकभवन से दूसरे दिन भी खाली हाथ लौटे विजय

- राज्यपाल ने टीवीके प्रमुख से मांगी समर्थन देने वाले विधायकों की सूची
- बुधवार को भी राज्यपाल से मिले थे, पर नहीं दे पाए थे बहुमत का आंकड़ा

विजय। फाइल

चेन्नई, एएनआइ : तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। टीवीके अध्यक्ष विजय गुरुवार को 24 घंटे में दूसरी बार लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिले, लेकिन उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अर्लेकर ने विजय से बहुमत दिखाने और समर्थक विधायकों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। राज्यपाल ने विजय को बताया कि उनकी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल अर्लेकर एक स्थिर सरकार चाहते हैं। ऐसे में विजय यह साबित करते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं कि उनके पास बहुमत है।

विजय बुधवार को भी राज्यपाल से मिले थे, लेकिन वह बहुमत का आंकड़ा नहीं दे पाए थे। कहा जाता है कि विजय भाजपा से समर्थन लेने के इच्छुक नहीं हैं। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया। वरिष्ठ नेताओं ने कथित तौर पर सुझाव दिया है कि पार्टी सरकार गठन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कानूनी विकल्प तलाशे। कुछ नेताओं ने पुनः चुनाव कराने की संभावना भी जताई है। टीवीके कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को लोकभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि राज्यपाल अर्लेकर पार्टी प्रमुख विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें।

बहुमत जुटाने की जद्दोजहद पेज>>4

नीतीश के बेटे निशांत समेत 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ

पटना : बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार ने सूबे की राजनीति में कई नए संकेत दिए हैं। गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ भव्य समारोह पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत समेत 32 मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न्हीं रहा। इसके जरिये भाजपा ने सहयोगी दलों को भी साधा। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक निष्ठा व नई पीढ़ी को अवसर देने की रणनीति इस विस्तार में साफ दिखाई दी। (पेज-5)

माओवादी हमला मामले में सभी बरी, 76 जवान हुए थे बलिदान

बिलासपुर : सुकमा के ताड़मेटला माओवादी हमले के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। 76 जवानों के बलिदान से जुड़े इस चर्चित केस में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सभी आरोपितों को बरी करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर के निर्णय को हाई कोर्ट ने कायम रखा। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की नाकामी पर कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि माओवादियों के क्रूर हमले में सीआरपीएफ के जवानों की मृत्यु के बावजूद अभियोजक एजेंसियां अपराधियों की पहचान करने में असफल रहीं। (पेज-6)

धार्मिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करने से धर्म और सभ्यता को होगा नुकसान : सुप्रीम कोर्ट

- शीर्ष अदालत ने सबरीमाला मामले में सुनवाई के दौरान की यह टिप्पणी
- सबरीमाला और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव के मुद्दे पर सुनवाई कर रही नौ जजों की संविधान पीठ

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग धार्मिक प्रथाओं या धर्म से जुड़े मामलों पर संवैधानिक अदालत में सवाल उठाने लगेंगे, तो सैकड़ों याचिकाएं अलग-अलग रीति-रिवाजों पर आने लगेंगी। इससे धर्म और सभ्यता दोनों को नुकसान होगा।

सुप्रीम कोर्ट के नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस समय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें धर्मस्थलों पर महिलाओं संग कथित भेदभाव का मुद्दा उठाया गया है। इनमें केरल के सबरीमाला मंदिर का मामला भी शामिल है। साथ ही विभिन्न धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा मुद्दा भी है। बोहरा समुदाय की केंद्रीय संस्था ने 1986 में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें 1962 के उस फैसले को निरस्त करने की मांग की गई थी, जिसमें बंबई बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1949 को रद कर दिया गया था। इस कानून के तहत किसी भी समुदाय के सदस्य को समाज से बाहर करने को अवैध माना गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन सुधारवादी दाऊदी बोहरा समूह की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई प्रथा किसी व्यक्ति के सामाजिक या गैर-धार्मिक आचरण के जवाब में अपनाई जाती है, तो उसे संविधान के तहत धार्मिक संरक्षण नहीं मिल सकता। यदि कोई प्रथा धार्मिक पहलू भी रखती है, पर वह मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव डालती है, तो उसे संवैधानिक संरक्षण से बाहर रखा जा सकता है।

इस दलील पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, यदि हर कोई अदालत के समक्ष कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों या धर्म से जुड़े मामलों पर सवाल उठाना शुरू कर दे, तो फिर उस सभ्यता का क्या होगा, जहां धर्म भारतीय समाज से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है? सैकड़ों याचिकाएं होंगी जो इस अधिकार, उस अधिकार, मंदिर के खुलने-बंद होने पर सवाल उठाएंगी। हम इससे अवगत हैं।

आमों के निर्यात में बड़ी भूमिका निभा रही परमाणु तकनीक

बार्क का कमाल

बार्क की विकिरण तकनीक से आम व लीची जैसे जल्दी खराब होने वाले फलों की भंडारण अवधि बढ़ रही, हर वर्ष 30 हजार टन उपचारित आम का होता है निर्यात

अरविंद शर्मा ● जागरण

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली: भारतीय फलों को दुनिया के बड़े बाजारों तक सुरक्षित पहुंचाने में अब परमाणु तकनीक बड़ी भूमिका निभा रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) द्वारा विकसित विकिरण तकनीक से आम व लीची जैसे जल्दी खराब होने वाले फलों की भंडारण अवधि बढ़ रही है। इससे अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया जैसे देशों को फलों का निर्यात बढ़ा है। लिहाजा किसानों की आय और कृषि निर्यात बढ़ रहा है।

दरअसल इन देशों के आयात नियम बेहद सख्त हैं। वहां ऐसे फलों को ही अनुमति मिलती है, जिनमें कीट या उनके अंडे न हों। इसी कारण भारतीय आम लंबे समय तक अमेरिकी बाजार से बाहर रहे। ऐसे में विकिरण तकनीक समाधान बनकर आई। बार्क में काम तो वर्ष 2000 में शुरू हो गया था, पर 2007 में अमेरिका ने भारतीय आमों के लिए रास्ता खोला।

हर वर्ष पैदा होता है 240 लाख टन आम : भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक है। यहां हर वर्ष 240 लाख टन से अधिक आम पैदा होता है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब आधा है। अल्फांसो, केसर, चौसा व लंगड़ा जैसी किस्मों की अमेरिका में भारी मांग है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) के अनुसार, भारत सालाना 30 हजार टन उपचारित आम निर्यात करता है। इसका सबसे अधिक फायदा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के आम उत्पादकों को मिला है।

20 दिनों तक रहता है सुरक्षित : सामान्य स्थिति में आम करीब एक हफ्ते सुरक्षित रहता है। विकिरण उपचार के बाद अब यह 20 दिनों से अधिक सुरक्षित रह सकता है। इससे समुद्री मार्ग से निर्यात होने लगा है। हवाई मार्ग से फल दो दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन लागत बढ़ जाती है।

स्वाद, रंग या पोषण पर नहीं होता असर: बिहार के बिहटा समेत देश में 33 केंद्र हैं, जहां फलों का विकिरण उपचार किया जाता है। मुंबई, बेंगलुरु, नासिक, अहमदाबाद को अमेरिका से प्रमाणन मिला हुआ है। यहां आमों का उपचार गामा रेडिएशन से किया जाता है। यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। इससे फल रेडियोएक्टिव नहीं बनते। न ही स्वाद, रंग और पोषण पर कोई नकारात्मक असर पड़ता है।

लीची व अनार पर भी हो रहा तकनीक का प्रयोग: लीची व अनार समेत जल्दी खराब होने वाले अन्य फलों को सुरक्षित रखने में भी इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट और कटे फलों पर परीक्षण चल रहे हैं। लीची के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी नई तकनीकों पर काम हो रहा है।

विकिरण प्रक्रिया : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य और सुरक्षित

आम को पेड़ से कच्ची, लेकिन परिपक्व अवस्था में तोड़ा जाता है। फिर धोकर आकार और गुणवत्ता के आधार पर छांटने के बाद विशेष बाक्स में पैक कर विकिरण चैंबर में रखा जाता है। यहां नियंत्रित मात्रा में गामा किरणें, एक्स-रे या इलेक्ट्रान बीम दी जाती हैं। इससे कीट, लार्वा और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। फंगस और बैक्टीरिया की वृद्धि सुस्त हो जाती है। इससे फल जल्दी नहीं पकता और अधिक समय तक ताजा रहता है। इसके बाद फलों को नियंत्रित तापमान में रखकर निर्यात कर दिया जाता है। यह तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य और सुरक्षित है।

गुजरात के सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपित बरी

- बांबे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा विशेष सीबीआइ अदालत का 2018 का निर्णय
- सोहराबुद्दीन के दो भाइयों ने इस निर्णय को दी थी चुनौती

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बांबे हाई कोर्ट ने विशेष सीबीआइ अदालत के 2018 के निर्णय को बरकरार रखते हुए मामले के सभी 22 आरोपितों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सोहराबुद्दीन के भाइयों रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन की अपील खारिज करते हुए कहा, अभियोजन पक्ष साजिश और हत्या के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

यह था मामला : यह विवाद 23 नवंबर, 2005 को तब शुरू हुआ, जब गुजरात व राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने हैदराबाद से सांगली जा रही एक बस को रास्ते में रोका और सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम को हिरासत में लिया था। 26 नवंबर, 2005 को अहमदाबाद के पास विशाला सर्कल पर पुलिस ने सोहराबुद्दीन को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस का दावा था कि वह लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा था। एनकाउंटर के कुछ दिनों बाद कौसर बी की भी हत्या हो गई थी और उसका शव जला हुआ पाया गया था। इस घटना के चश्मदीद गवाह तुलसीराम प्रजापति की दिसंबर, 2006 में गुजरात-राजस्थान सीमा पर एक अन्य मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने जवाबी कार्रवाई बताया था।

अदालत के निर्देश पर 2010 में सीबीआइ को सौंप दी गई थी मामले की जांच पेज>>6

हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प सोमनाथ

सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, संस्कृति और एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। **पीएम मोदी** का विशेष आलेख। ● पेज-5

जागरण विशेष

हमारे विज्ञानियों ने मीथेन गैस पर दुनिया को दिखाया आईना

भोपाल: सेटेलाइट तकनीक व जमीनी आंकड़ों से साबित किया कि देश में मीथेन उत्सर्जन वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से है कम। ● पेज-7

संपादकीय

बंगाल के खोए गौरव को बहाल करने की चुनौती: बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ है और उसे सही करने के लिए भाजपा की नई सरकार को द्रुत गति के साथ अविलंब प्रयास करने होंगे। **कंचन गुप्ता** का आलेख।

आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार: पाकिस्तान के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया है। **डा. अर्जुन सुब्रमण्यम** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

पर्यटन स्थलों पर सुनिश्चित हो सुरक्षा: जबलपुर में हुई क्रूज दुर्घटना ने देश की पर्यटन नीति और सुरक्षा व्यवस्था के बीच असंतुलन को उजागर कर दिया है। **लालजी जायसवाल** का विश्लेषण।

जेनरेटिव एआइ और शिक्षा: भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व पहुंच में विषमता गंभीर समस्या है, इसलिए जेनरेटिव एआइ को समाधान के रूप में देखा जा रहा है। **आदित्य कुमार** का आलेख। ● पेज-9

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स

शाम 7:30 बजे स्थान: नई दिल्ली

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

सिनेमा के पास मां है

सबको पता है अपनी सच्चाई: पलक तिवारी

● पेज-13

38 डिग्री तक यानी 40 डिग्री से नीचे दिन का तापमान अभी बना रहेगा। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अभी अगले पांच दिन और राजधानी में गर्मी के तेवर हल्के ही बने रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान सुबह के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी और यह 26 डिग्री तक जाएगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 8 मई, 2026

आज का मौसम

शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूप भी निकली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
8 मई	34.0	23.0
9 मई	36.0	24.0
नोएडा		
8 मई	31.0	21.0
9 मई	32.0	22.0
गुरुग्राम		
8 मई	38.0	24.0
9 मई	38.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

नोएडा से पहले दिन चार शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को देश के चार शहरों के लिए यात्री विमान उड़ान भरेंगे। गुरुवार शाम चार बजे से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई। इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट लखनऊ से सुबह 7:05 बजे उड़ान भरकर सुबह 8:05 बजे यहां उतरेगी। इसके बाद यही फ्लाइट सुबह 8.35 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। पहले दिन नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और अमृतसर से विमान यात्रियों को लेकर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। वहीं, 16 जून से जम्मू के लिए भी यहां से प्रतिदिन विमान सेवा शुरू होगी।

इंडिगो एक जुलाई तक नोएडा एयरपोर्ट से चरणबद्ध तरीके से देश के 16 शहरों के लिए यात्री विमान सेवा शुरू करेगी। इससे नोएडा एयरपोर्ट कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक विमान सेवा से जुड़ जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के लिए इंडिगो ने शाम चार बजे से वेबसाइट, एप, ट्रैवल पार्टनर के जरिये टिकट की बुकिंग शुरू कर दी। इंडिगो के चीफ स्ट्रेटेजी आफिसर आलोक सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर का प्रवेश द्वार बनेगा। इंडिगो एनसीआर में संचालित हो रहे तीनों एयरपोर्ट से यात्री सेवा करने वाली एयरलाइंस कंपनी है। नेटवर्क का विस्तार जारी रखते हुए किफायती, समयनिष्ठ और आरामदेह यात्रा सेवा देने के लिए इंडिगो प्रतिबद्ध है।

- इंडिगो ने शुरू की टिकटों की बुकिंग, इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से सुबह 8:05 बजे यहां उतरेगी
- हैदराबाद, अमृतसर व बेंगलुरु के लिए भी शुरू होंगी उड़ानें, 16 जून से जम्मू के लिए सेवा उपलब्ध होगी

9 दिसंबर 2024 को नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी थी इंडिगो की वैलिडेशन फ्लाइट। जागरण आर्काइव

एक जुलाई से जुड़ेंगे 16 शहर : नोएडा एयरपोर्ट से एक जुलाई को देश के 16 शहरों के लिए सीधे विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें लखनऊ, बरेली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल, देहरादून, किशनगढ़, जयपुर, पंतनगर, चंडीगढ़ और जम्मू शामिल हैं।

आइजीआइ के मुकाबले नोएडा एयरपोर्ट से अधिक किराया

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- एक प्रतिशत वैट का भी नहीं मिला लाभ, दोनों एयरपोर्ट के लिए इंडिगो का यात्री किराये में 70 से 410 रुपये का अंतर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से लोगों को हवाई यात्रा करने के लिए एक ओर एयरपोर्ट का विकल्प मिल गया है, लेकिन किराये के तौर पर उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। इंडिगो की दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा के लिए यात्री किराया लगभग एक समान निर्धारित किया गया है। इससे दोनों एयरपोर्ट के बीच यात्री किराया को लेकर प्रतिस्पर्धा की संभावना भी समाप्त हो गई है। एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल एटीएफ पर दिल्ली में 25 प्रतिशत वैट की तुलना में उप्र में एक प्रतिशत वैट के कारण नोएडा एयरपोर्ट से किराया सस्ता होने की उम्मीद पूरी नहीं हुई है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को इंडिगो की कमर्शियल सेवा शुरू होने जा रही है। पहले दिन नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ, बेंगलूरू, हैदराबाद और अमृतसर के लिए विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए एयरलाइंस ने गुरुवार से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन किराये पर आइजीआइ एयरपोर्ट के सापेक्ष यात्रियों को फायदा नहीं हुआ है। आइजीआइ और नोएडा एयरपोर्ट से चारों शहरों के लिए इंडिगो का तय किराया लगभग समान है। दिल्ली में एटीएफ पर 25 प्रतिशत वैट लागू है, उप्र सरकार ने प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एटीएफ पर एक प्रतिशत वैट लागू कर रखा है। इससे उम्मीद थी कि ईंधन सस्ता होने से कंपनियां नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली की तुलना में किराया कम रख सकती हैं, लेकिन यात्रियों की उम्मीद पूरी नहीं हुई।

निजी कंपनियों के नाम से भी जाने जाएंगे नमो भारत के 21 स्टेशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: नमो भारत के स्टेशनों को अब निजी कंपनियों के नाम से भी जाना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर के 21 स्टेशनों पर विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है। इस योजना के तहत जो कंपनियां इन स्टेशनों के ब्रांडिंग अधिकार खरीदेंगी, वे स्टेशन के मूल नाम के साथ अपना नाम जोड़ सकेंगी। यह विज्ञापन सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्लेटफार्म, खंभों, एंट्री और एग्जिट गेट पर भी कंपनी का लोगो और नाम दिखाई देगा।

ट्रेन में घोषणाओं में भी उस कंपनी का नाम लिया जाएगा व नक्शों पर भी दिखेगा। इन 21 स्टेशनों में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नार्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, एमईएस कालोनी, दौरली, मेरठ नार्थ व मोदीपुरम शामिल हैं।

न्यूज गैलरी

जलाने के बाद भी महिला ने पति व ससुरालियों को किया माफ

नई दिल्ली : दहेज के लिए पत्नी को जलाने के लिए दोषी करार दिए गए पति की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कम कर दी कि पत्नी ने उसे माफ कर दिया है और वह उसके साथ रह रही है। न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि सचमुच, महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गंभीर रूप से जलने के बावजूद, ऐसा लगता है कि सविता ने अपने पति और ससुराल वालों को माफ कर दिया है। पीठ ने कहा कि 25 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद, अपीलकर्ताओं को वापस जेल भेजने से सुलह के माध्यम से बनाया गया पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाएगा। (जासं)

पूर्व एएसआइ की सजा को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

नई दिल्ली: फर्जी पासपोर्ट सत्यापन मामले में दिल्ली पुलिस के एक पूर्व सहायक उप-निरीक्षक (एएसआइ) सुबे सिंह को दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति चंद्राशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि भले ही किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि षड्यंत्र का अनुमान परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है। (जासं)

वाटर कूलर की मशीन का फटा कंप्रेशर, दो कामगारों की मौत

गाजियाबाद : लिंक रोड थाना क्षेत्र के साइट चार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक वाटर कूलर बनाने की फैक्ट्री में गुरुवार शाम टेस्टिंग के दौरान मशीन का कंप्रेशर फट गया। हादसे में तीन कामगार घायल हो गए। उपचार के दौरान दो कामगारों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनीं हुई है। (जासं)

द्वारका में बनेगा सुविधाओं से लैस मेडिकल कालेज

मिली मंजूरी ▶ हर साल तैयार किए जाएंगे 250 नए एमबीबीएस डाक्टर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ईएफसी की बैठक में परियोजना को मिली हरी झंडी

806 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में बनेगा मेडिकल कालेज

द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में एक मेडिकल कालेज और हास्टल का निर्माण किया जाएगा। करीब 806 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में हरी झंडी दी गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेडिकल कालेज का निर्माण राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मानकों के अनुसार होगा। यहां प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस सीटों की व्यवस्था होगी, जिससे दिल्ली में डाक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना के तहत एक बहुमंजिला अकादमिक ब्लाक, छात्र-छात्राओं के लिए हास्टल और शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। करीब 1,17,246 वर्ग मीटर क्षेत्र में होने वाले इस निर्माण में क्लासरूम, एडवांस लैब और शैक्षणिक सुविधाएं विकसित होंगी। लगभग 34 हजार वर्ग मीटर का बेसमेंट तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग पार्किंग व अन्य सेवाओं के लिए होगा। पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी, फायर अलार्म और अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश गहलोत और द्वारका के विभिन्न सेक्टरों की आरडब्ल्यूए के फेडरेशन द्वारका लोक कल्याण मंच के अध्यक्ष डीपी वाजपेयी ने भी इस कदम का स्वागत किया है।

ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप होगी परियोजना : यह पूरी परियोजना ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप होगी। इसके तहत बिल्डिंग परिसर में सोलर पावर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व वाटर रिसाइकिलिंग का उपयोग होगा। इमारत को भूकंप सुरक्षित बनाया जाएगा और इसे दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट के साथ डिजाइन किया जाएगा।

खरे नहीं उतरे 15 एसटीपी, डीजेबी और आपरेटरों पर 2.89 करोड़ रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मानकों पर खरा न उतरने वाले 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और आपरेटरों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई है। डीपीसीसी ने गुरुवार को एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि 13 अप्रैल को 15 एसटीपी संचालकों पर 2.89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से सात एसटीपी का संचालन डीजेबी द्वारा किया जा रहा है, अन्य का संचालन विभिन्न एजेंसियों और निजी फर्मों के माध्यम से किया जा रहा है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा कि नमूनों से संबंधित लैब रिपोर्ट के आधार पर जुलाई से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच मानकों को पूरा नहीं करने वाले 14 एसटीपी को लेकर 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली जल बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वहीं, सेन नर्सिंग होम एसटीपी को भी अगस्त 2025 में मानकों पर खरा नहीं उतरने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

डीपीसीसी ने कहा कि प्रति माह के स्तर पर एसटीपी के संचालन की निगरानी की जा रही है और डीजेबी को पत्र जारी किया जाता है। मानकों पर काम नहीं करने वाले 75 प्रतिशत एसटीपी को लेकर प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेकर एनजीटी मामले पर सुनवाई कर रही है।

कैंसर, डायबिटीज सहित कई नकली दवा खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- राजधानी के मुखर्जी नगर में चल रही थी फैक्ट्री, चार गिरफ्तार
- छह करोड़ की दवाएं बरामद, पूर्वोत्तर राज्यों में कर रहे थे दवाओं की सप्लाई

राष्ट्रीय राजधानी में नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से बढ़ रहा है। हाल के महीनों में दिल्ली से नकली दवाएं बनाने में शामिल कई गिरोह पकड़े जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब कैंसर, अस्थमा, एनिमल बाइट, लिवर, डायबिटीज और थायरायड की नकली और सरकारी सप्लाई की दवाओं को रीपैकेजिंग कर देशभर में खपाने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ कर सरगना समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह करीब तीन साल से सक्रिय था।

मुखर्जी नगर इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्री पर छापे में करीब छह करोड़ रुपये कीमत की नकली, री-लेबल की गई और सरकारी अस्पतालों की दवाएं बरामद की हैं। बरामद दवाओं में रेबीज वैक्सीन, इंसुलिन, ह्यूमन एल्ब्यूमिन, हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन, स्नेक वेनम एंटीसीरम और अन्य दवाएं व इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी शामिल है। फैक्ट्री में छोटे-छोटे पार्सल बनाकर ट्रेन व बस से नकली दवाओं को असम भेजा जाता था। वहां से बंगाल के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में थोक विक्रेताओं को सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मुखर्जी नगर के मनोज कुमार जैन, पंचकूला के राजू कुमार, प्रयागराज के विक्रम सिंह उर्फ सन्नी और वतन के रूप में हुई।

पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को 22 अप्रैल को नकली दवाओं के निर्माण और सरकारी सप्लाई की दवाओं के अवैध धंधे से जुड़ी सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि एक संगठित गिरोह प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरी के लिए निर्धारित दवाओं को अवैध तरीके से बाहर निकालकर लेबल बदल देता और फिर उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देता था। सूचना पुख्ता होने के बाद इस अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा गया।

फैक्ट्री से बरामद की गई नकली दवाएं। सौजन्य : दिल्ली पुलिस

मरीज को छोड़कर लौट रही सफदरजंग अस्पताल की एंबुलेंस में लगी आग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एक मरीज को छोड़ने के बाद लौट रही सफदरजंग अस्पताल की एंबुलेंस में मोतीबाग फ्लाईओवर के पास बृहस्पतिवार की शाम आग लग गई। एम्बुलेंस में चालक के अतिरिक्त कोई नहीं था। वह एंबुलेंस को किनारे खड़ी करके तुरंत नीचे उतर गया। देखते ही देखते आग एंबुलेंस के भीतर तेजी से फैल गई। अंदर रखा आक्सीजन सिलिंडर फटने से पास खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई।

दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल की कैट्स (सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रामा सर्विस) एंबुलेंस समालखा में एक मरीज को छोड़ने के बाद अस्पताल लौट रही थी। शाम करीब 7:20 बजे जब एंबुलेंस धौला कुआं से मोती बाग फ्लाईओवर के पास पहुंची, तो शार्ट सर्किट के कारण कंडक्टर की तरफ वाली सीट पर आग लग गई। कुछ ही देर में मौके पर दमकल की दो गाड़ियां पहुंचीं। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि तब तक एंबुलेंस का काफी नुकसान हो चुका था।

नेहरू प्लेस में देश के पहले अपग्रेडेड पोस्ट आफिस का लोकार्पण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- ज्योतिरादित्य बोले, इंडिया पोस्ट देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक

जिस तरह खून ले जाने वाली आर्टरी इंसान के शरीर को बनाए रखती हैं, वैसे ही डाक विभाग अपने बेमिसाल नेटवर्क और समर्पित कर्मचारियों के माध्यम से देश के हर कोने में सेवा करता है और उन्हें जोड़ता है। इसमें डाकिया भी शामिल हैं, जो हर घर से गहराई से जुड़े रहते हैं। इंडिया पोस्ट देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक है और फाइनेंशियल इनक्लूजन, सर्विस डिलीवरी और नेशनल कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभा रहा है। यह बात गुरुवार को नेहरू प्लेस में देश के पहले अपग्रेडेड पोस्ट आफिस जनता को समर्पित करने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहीं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि विभाग ने आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में लगभग 5,000 करोड़ का निवेश किया है और पिछले वर्ष एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलाजी शुरू की है। इस बदलाव में कई नागरिक-केंद्रित सुधार शुरू किए हैं, जिनमें यूपीआइ-इनेबल्ड सेवाएं, ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी, 24 घंटे चलने वाले पोस्ट आफिस, बड़े मेट्रो शहरों में 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट जैसी गारंटीड टाइम-बाउंड डिलीवरी सेवाएं शामिल हैं। देशभर में 1.65 लाख से ज्यादा पोस्ट आफिस हर साल लगभग 90 करोड़ चिट्ठियां और 7.5 करोड़ पार्सल डिलीवर करते हैं।

नेहरू प्लेस में पहले अपग्रेडेड पोस्ट आफिस के लोकार्पण के बाद डाक कर्मी से जानकारी लेते केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौ. विभाग

एनएसडी में आज से सजेगा रंग महोत्सव का मंच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गर्मी की छुट्टियां थियेटर प्रेमियों के लिए खास होने वाली है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का मंच सजा रहा है। खास बात है कि यह महोत्सव 38 दिनों तक चलेगा, जिसका शुभारंभ आठ मई से होगा।

इस महोत्सव का उद्घाटन रंगमंडल की प्रस्तुति 'अक्स तमाशा' के साथ होगा। इस नाटक का निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानू भारती ने किया है। महोत्सव में विविधता का विशेष ध्यान रखा गया है। अगले माह 14 जून तक विभिन्न शैलियों और रंग-रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में क्लासिक नाटकों में अंधा युग, आधे अधूरे और तमस, व्यंग्य और संवेदना से जुड़े ताजमहल का टेंडर, बायेन और बाबूजी नाटकों की प्रस्तुति होगी। बंदी गली का आखिरी मकान, माई री मैं का से कहूं और समुद्र मंथन नाटक सहित अन्य नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। रेपर्टरी के कलाकार जयपुर का भी दौरा करेंगे।

'40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को मिलेगी निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने बसई दारापुर में ईएसआइसी मेडिकल कालेज से इस योजना का किया शुभारंभ

देश के श्रमिकों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। नई श्रम संहिता के तहत अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए निश्शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को बसई दारापुर स्थित ईएसआइसी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल से योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद रहे।

डा. मनसुख मांडविया ने कहा कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस गारंटी को दर्शाते हैं, जो देश के हर श्रमिक के लिए गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि दस वर्ष में देश की सामाजिक सुरक्षा का दायरा 19 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है। ईएसआइसी के लाभार्थियों की संख्या भी सात करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच गई है। डा. मांडविया ने घोषणा की कि अब ईएसआइसी के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की मुफ्त जांच के साथ ही गंभीर बीमारियों का इलाज व दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नई संहिता के तहत मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

बसई दारापुर स्थित ईएसआइसी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच से जुड़ी योजना का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री डा. मनसुख मांडविया। सौ- इंटरनेट मीडिया

टिप्पणी

कोर्ट ने कहा, टैरिफ निर्धारण केवल गणितीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि नियामकीय संतुलन का विषय, डीईआरसी की अपील पर एपीटीईएल का आदेश रद, उपभोक्ता हितों की रक्षा को बताया जरूरी

बिना सेवा नहीं वसूला जा सकता शुल्क : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ताओं से उस सेवा का शुल्क नहीं वसूला जा सकता, जो उन्हें अब उपलब्ध ही नहीं कराई जा रही है। टैरिफ निर्धारण केवल गणितीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि नियामकीय संतुलन का विषय है, जिसमें कंपनियों की लागत वसूली और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन जरूरी है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की अपील स्वीकार करते हुए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के फरवरी 2025 के आदेश को रद कर दिया और डीईआरसी का 2019 का आदेश बहाल कर दिया।

मामला रिठाला स्थित 108 मेगावाट गैस आधारित अस्थायी बिजली संयंत्र से जुड़ा था, जिसे टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने राष्ट्रमंडल खेल-2010 से पहले बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए स्थापित किया था। संयंत्र की अवधि केवल पांच से छह वर्ष तय थी और मार्च 2018 के बाद इससे बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में उपभोक्ताओं से उस सेवा का भुगतान नहीं कराया जा सकता, जो उन्हें मिल ही नहीं रही। अदालत ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(डी) का हवाला देते हुए कहा कि शुल्क निर्धारण करते समय आयोग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बिजली लागत की उचित वसूली, दोनों बातों को ध्यान में रखना होता है। यह उपभोक्ता हितों को गौण नहीं, बल्कि केंद्रीय वैधानिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

डीईआरसी ने नवंबर 2019 में संयंत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 तक छह प्रतिशत वार्षिक दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी थी, जिससे 83.34 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। हालांकि लगभग 94.59 करोड़ रुपये की शेष पूंजी लागत और रखरखाव व्यय को टैरिफ में शामिल करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि संयंत्र ने मार्च 2018 के बाद बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी। एपीटीईएल ने फरवरी 2025 में कहा था कि डीईआरसी ने संयंत्र की उपयोगी आयु 15 वर्ष मानी थी, इसलिए मूल्यह्रास भी उसी अवधि के आधार पर होना चाहिए। न्यायाधिकरण ने डीईआरसी का आदेश रद कर मामले को दोबारा आयोग को भेज दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिजली खरीद समझौता केवल मार्च 2018 तक के लिए था और टीपीडीडीएल ने इसे चुनौती नहीं दी।

आरएमएल अस्पताल ने जिंदा मरीज को बता दिया मृत, जारी किया डेथ सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी के प्रतिष्ठित सरकारी डा. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल ने उपचारत मरीज जितेंद्र कुकरेती को मृत घोषित करते हुए उनकी डेथ समरी और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि वह जीवित थे। अस्पताल प्रशासन व उसकी दस्तावेजी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

आरएमएल के अनुसार अशोक विहार निवासी 51 वर्षीय जितेंद्र कुकरेती पर अप्रैल 2026 में कुत्तों ने हमला कर दिया था। इसके बाद उन्हें 18 अप्रैल को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के दस्तावेजों में उन्हें जनरल सर्जरी विभाग में भर्ती दिखाया गया है। जारी ''डेथ समरी'' में 23 अप्रैल 2026 को उनकी मृत्यु दर्ज कर दी गई।

वीरेंद्र सचदेवा बने रहेंगे अध्यक्ष या किसी और को मिलेगी दिल्ली की कमान

संतोष कुमार सिंह • जागरण

- हर्ष मल्होत्रा, राजीव बब्बर, योगेंद्र चांदोलिया, कुलजीत दौड़ में शामिल

नई दिल्ली : पिछले कई महीनों से दिल्ली भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा जोरों पर है। पिछले वर्ष जुलाई में ही इसको लेकर दिल्ली के नेताओं से सुझाव लिए गए थे, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनावों के कारण दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला टल गया था। अब शीघ्र ही यह तय हो जाएगा कि वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या यह पद किसी अन्य नेता को मिलेगा।

राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने पिछले वर्ष जुलाई में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली के भाजपा सांसदों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से राय ली थी।

अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों की चर्चा है। वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में भाजपा 27 वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी करने में सफल रही है। पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा तथा राजीव बब्बर के नाम की भी चर्चा है।

यदि अनुसूचित जाति के किसी नेता को यह जिम्मेदारी मिलती है तो उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चांदोलिया मजबूत दावेदार हैं। वहीं, ओबीसी नेताओं में कुलजीत चहल का नाम चर्चा में है। मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय, लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा व पूर्व महापौर जय प्रकाश भी दौड़ में शामिल हैं।

अवैध प्रवासियों की वापसी पर तेजी दिखाए बांग्लादेश

कहा- अपने नागरिकों की राष्ट्रीयता के सत्यापन में लाए तेजी

पड़ोसी देश को भेजे गए हैं 2862 मामले, अभी तक नहीं मिला है जवाब

जयप्रकाश रंजन • जागरण

रणधीर जायसवाल। फाइल

नई दिल्ली : बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश को लेकर भारत की नीति में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अवैध घुसपैठ रोकने व सीमा सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया था। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र-राज्य स्तर पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के विरुद्ध रुख और सख्त हो सकता है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मुद्दे को फिर मजबूती से उठाया और कहा, वह इनकी वापसी में तेजी दिखाए। यह पहल बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की हालिया टिप्पणियों के जवाब में हुई है, जिनमें बंगाल चुनाव के बाद 'पुशबैक' की आशंका जताई गई थी। वैसे बांग्लादेश में फरवरी, 2026 में बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत द्विपक्षीय संबंधों में गर्मजोशी की कोशिश कर रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'इन टिप्पणियों को भारत से गैरकानूनी बांग्लादेशियों को वापस भेजने के मुख्य मुद्दे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसके लिए बांग्लादेश से सहयोग की जरूरत है। बांग्लादेश में राष्ट्रीयता सत्यापन के 2862 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ तो पांच वर्ष से भी अधिक समय से हैं। हमारी नीति है कि भारत में रह रहे सभी गैरकानूनी विदेशी नागरिकों को हमारे कानूनों, प्रक्रिया व तय द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश अपने नागरिकों की राष्ट्रीयता सत्यापन में तेजी लाएगा ताकि अवैध तरीके से रहने वालों को आसानी से वापस भेजा जा सके।'

विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार का रवैया हमेशा से काफी ढीला रहा है। पूर्व पीएम शेख हसीना के कार्यकाल में भी भारत अवैध आव्रजन से जुड़े मामले भेजता था, पर कोई जवाब नहीं आता था। गत पांच वर्षों में भारत ने जितने भी मामले सत्यापन के लिए भेजे, वहां से जवाब नहीं आया। कई मामलों में अवैध बांग्लादेशी नागरिक जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, पर राष्ट्रीयता सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। यह मुद्दा लंबे समय से भारत-बांग्लादेश संबंधों का संवेदनशील पहलू रहा है। भारत-बांग्लादेश की 4096 किमी लंबी सीमा पर कई जगहों पर घुसपैठ की शिकायतें आती रहती हैं, खासकर बंगाल व असम में। बंगाल चुनाव में भाजपा ने अवैध घुसपैठ पर सख्त रुख अपनाया। एनआरसी तथा सीएए जैसे मुद्दे आगे बढ़ाने का वादा किया। गृह मंत्रालय ने हाल ही में अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत व निर्वासन के लिए नई नीति जारी की है, जिसमें हर जिले में एसटीएफ बनाने और मासिक रिपोर्टिंग का प्रविधान है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के तहत ही निर्वासन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीस्ता नदी के मुद्दे पर बांग्लादेश के चीन से बात करने से जुड़े सवाल पर जायसवाल ने कहा, भारत और बांग्लादेश 54 नदियां साझा करते हैं। हमारे पास पानी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए व्यवस्थित द्विपक्षीय तंत्र हैं। ये तंत्र नियमित अंतराल पर बैठक करते रहते हैं।

बांग्लादेश ने तीस्ता परियोजना पर चीन से समर्थन मांगा

- रहमान सरकार के इस कदम से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर पड़ सकता है असर

बीजिंग, प्रेट्र: बांग्लादेश की नई सरकार चीन से नजदीकियां बढ़ा रही है। उसने तीस्ता नदी पुनर्स्थापन परियोजना के लिए चीन से समर्थन मांगा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर डाल सकता है।

बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस के अनुसार, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बुधवार को बीजिंग में हुई बैठक में तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्री वांग ने बांग्लादेश की नई सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि चीन उच्च गुणवत्ता वाली "बेल्ट एंड रोड" सहयोग परियोजना को बांग्लादेश की राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के साथ जोड़ने और अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे व लोगों के बीच संपर्क जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग को

खलीलुर रहमान। फाइल

गहरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चीनी कंपनियों को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। चीन कई वर्षों से टीआरसीएमआरपी के विकास में रुचि दिखाता रहा है, जो भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे के पास है, जो इसकी मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां यह सिंचाई और लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है।

'भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे कनाडा'

- कनाडाई खुफिया एजेंसी की हालिया रिपोर्ट पर भारत ने की है यह अपील
- रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने गुरुवार को कनाडा से कहा कि वह अपने यहां भारत विरोधी चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। नई दिल्ली ने ओटावा से यह अपील कनाडाई खुफिया एजेंसी की उस हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में की है, जिसमें खालिस्तान समर्थकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है।

कैनेडियन सिक्योरिटी इंजेलिजेंस सर्विस (सीएसआइएस) ने 2025 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा में स्थित खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की हिंसक चरमपंथी गतिविधियों में संलिप्तता कनाडा के हितों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बनी हुई है। खुफिया एजेंसी की यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "भारत ने बार-बार कनाडाई सरकार से अपील की है कि वह अपनी धरती पर सक्रिय भारत विरोधी चरमपंथी तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे। इसमें हिंसा के महिमामंडन, भारतीय नेताओं व राजनयिकों के खिलाफ धमकियां, पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और तथाकथित 'जनमत संग्रह' के जरिये अलगाववाद को बढ़ावा देने के प्रयास जैसे मुद्दों का समाधान करना शामिल है।" जायसवाल ने सीएसआइएस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही।

ब्रिक्स बैठक पर उचित समय पर मिलेगी जानकारी

एएनआइ के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आगामी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में नेताओं की भागीदारी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा के संबंध में जानकारी उचित समय पर साझा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है।

होर्मुज से 11 भारतीय जहाज निकले, 13 अब भी फंसे हैं : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान के साथ कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप अब तक 11 भारतीय जहाज होर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकल चुके हैं। जबकि 13 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हैं। उन्होंने कहा, हम लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि शेष जहाज भी होर्मुज से सुरक्षित रूप से निकलकर भारत लौट सकें।

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश

- पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की बैठक में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर हुई चर्चा
- एनएचएआइ की प्रस्तावित परियोजना का एक हिस्सा बाघों के प्राकृतिक आवास से होकर गुजरेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने वाराणसी और कोलकाता को जोड़ने के लिए 235 किमी लंबे 'ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' बनाने की पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस योजना में बंगाल के 103 हेक्टेयर से अधिक आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्र के भू उपयोग में बदलाव की जरूरत है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की प्रस्तावित परियोजना का एक हिस्सा बाघों के प्राकृतिक आवास से भी होकर गुजरेगा। इसमें चार से छह लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है और जिसकी लागत 9,250 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को लेकर मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की 444वीं बैठक में चर्चा की गई, जो 23-24 अप्रैल के बीच हुई थी। यह परियोजना पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा जिलों से होकर गुजरेगी। इसके लिए गैर-वन क्षेत्रों में 40 हजार पेड़ों और वन क्षेत्रों में 10 हजार पेड़ों की कटाई की जरूरत होगी। प्रस्तावित परियोजना से 7.75 किमी की दूरी पर जंगल महल हाथी गलियारा भी स्थित है। मौजूदा

समय में हाथी गलियारे के कई हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची-I में सूचीबद्ध 17 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे सियार, सांभर हिरण, धारीदार लकड़बग्घा, लोमड़ी, हाथी व तेंदुआ। वन्यजीवों की आवाजाही को नियंत्रित करने को एनएचएआइ ने 20 हाथी-सह-वन्यजीव अंडरपास का प्रस्ताव रखा है।

आरक्षण प्रणाली का अपग्रेडेशन हो, मगर यात्रियों को न हो कोई असुविधा : वैष्णव

- अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
- देश की कुल टिकट मांग का लगभग 88 फीसद हिस्सा आनलाइन माध्यमों से पूरा हो रहा है

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रेलवे अपनी चार दशक पुरानी आरक्षण प्रणाली को अलविदा कहकर एक नए, आधुनिक युग में कदम रख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस ऐतिहासिक बदलाव के दौरान यात्रियों को रत्ती भर भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम का अपग्रेडेशन जितना तकनीकी रूप से उन्नत हो, यात्रियों के लिए उतना ही सरल और सुगम भी होना चाहिए।

40 साल पुराना सिस्टम व अत्याधुनिक तकनीक का मेल : 1986 में शुरू हुई पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की यात्रा ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। पिछले 40 वर्षों में इसमें कई छोटे-बड़े बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे पूरी तरह से 'ओवरहाल' कर दिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इस सिस्टम की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है, ताकि टिकट बुकिंग के

दौरान होने वाली तकनीकी खामियों और देरी को समाप्त किया जा सके। 2002 में इंटरनेट टिकटिंग की शुरुआत के साथ शुरू हुआ यह सफर आज उस मुकाम पर है, जहां देश की कुल टिकट मांग का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा आनलाइन माध्यमों से पूरा हो रहा है।

'रेल-वन' ऐप बना करोड़ों यात्रियों का नया साथी

इस डिजिटल क्रांति की सबसे चमकती कड़ी 'रेल-वन' मोबाइल ऐप बनकर उभरी है। पिछले साल जुलाई में लांच हुए इस ऐप ने एक साल से भी कम समय में लोकप्रियता के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप की सफलता का सबसे बड़ा कारण इसकी बहुआयामी उपयोगिता है। यह न केवल टिकट बुकिंग की सुविधा देता है, बल्कि यात्रियों की शिकायतों का त्वरित निवारण भी करता है। वर्तमान में इस ऐप के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 9.29 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं, जिनमें 7.2 लाख अनारक्षित और 2.09 लाख आरक्षित टिकट शामिल हैं। गूगल प्ले स्टोर और एपल स्टोर पर इसकी बढ़ती रेटिंग इस बात का प्रमाण है कि भारतीय रेल अब वास्तव में 'स्मार्ट रेल' बनने की दिशा में अग्रसर है।

कार्यपालिका को सार्वजनिक रोजगार में अस्थायी उपाय खत्म करने चाहिए

- कोर्ट ने कहा-शिक्षा की मजबूती वर्तमान आवश्यकता, अस्थायी उपायों से सब्सिडी देना नहीं
- झारखंड को संविदा शिक्षकों की 50 प्रतिशत रिक्तियां चार हफ्ते में अधिसूचित करने का निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में सहायक शिक्षकों व सहायक आचार्यों की कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत सिर्फ संविदा शिक्षक (पैराटीचर्स) के लिए चार सप्ताह के भीतर अधिसूचित करे। साथ ही कहा, शिक्षा को मजबूत करना वर्तमान की जरूरत है, ना कि अस्थायी उपायों के माध्यम से इसे सब्सिडी देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कार्यपालिका के लिए यह समय आ गया है कि वह नियमित रूप से शैक्षणिक प्रदर्शन का आडिट करे और सार्वजनिक रोजगार में अस्थायी उपायों को खत्म करे। पैराटीचर्स को शिक्षक की कमी को जल्दी से दूर करने के लिए सरकार की योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत निश्चित अवधि के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है।

जस्टिस पंकज मिथल व एसवीएन भट्टी की पीठ ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह सहायक शिक्षकों व आचार्यों के लिए चिह्नित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत के लिए सिर्फ पैराटीचर्स से आवेदन आमंत्रित करने को अधिसूचना जारी करे। कहा, वर्तमान में जरूरत यह है कि शिक्षा को मजबूत किया जाए, विशेष रूप से प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर, न कि अस्थायी उपायों के माध्यम से इसे सब्सिडी दी जाए। शिक्षा प्रदान करना स्वयं में उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यापक, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है...। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले पैराटीचर्स की अपीलों पर विचार किया, जिसने उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सेवाएं नियमित करने से इन्कार करते हुए कहा, इस संबंध में कोई राहत देना नए भर्ती के तरीके को जन्म देगा, जो कानून द्वारा अनुमोदित नहीं है। यदि पैराटीचर्स को अनुच्छेद 226 या 142 के तहत नियमित किया जाता है, तो यह नियुक्ति के स्रोत को बदल देगा।

'सीईसी नियुक्ति में सीजेआइ को शामिल करना कानून बनने तक ही था'

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-संसद चुनाव आयुक्त नियुक्ति पर अपने तरीके से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र

नई दिल्ली, एएनआइ: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) को शामिल करने संबंधी उसका 2023 का फैसला केवल तब तक के लिए था, जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बना देती। अदालत ने स्पष्ट किया कि उस फैसले में संसद को किसी विशेष ढांचे में कानून बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। विवाद का मुख्य मुद्दा चयन समिति से सीजेआइ को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल करना है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने दलील दी कि न्यायिक नियुक्तियों में अपनाए जाने वाले सिद्धांत चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर भी लागू होने चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की कि वर्षों तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून नहीं बनाना "निर्वाचितों की तानाशाही" जैसा था। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले ने केवल संवैधानिक शून्य को भरा था।

एडीआर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सभी सरकारों ने लंबे समय तक कानून न होने का फायदा उठाया और नियुक्तियों में मनमानी की गुंजाइश बनी रही।

याचिकाओं में कहा गया है कि नए कानून में सीजेआइ को चयन समिति से बाहर करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना के खिलाफ है। मौजूदा चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

दो दशकों में सरकारी स्कूलों में दाखिले में आई 22 प्रतिशत गिरावट

नीति आयोग की रिपोर्ट
- 2005 में 71 प्रतिशत दाखिले होते थे सरकारी स्कूलों में
- 2024-25 में दाखिला घटकर रह गया 49.24 प्रतिशत
- प्राइवेट स्कूलों की ओर झुकाव बताया गया प्रमुख कारण

नई दिल्ली, एएनआइ: प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध में सरकारी स्कूलों की पूछ कम होती जा रही है। बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता में माता-पिता सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूलों को महत्व दे रहे हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट से कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गत दो दशकों में सरकारी स्कूलों में दाखिले में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2005 में जहां 71 प्रतिशत दाखिले सरकारी स्कूलों में होते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49.24 प्रतिशत रह गया।

नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अब सभी माध्यमिक संस्थानों में प्राइवेट स्कूलों की हिस्सेदारी 44.01 प्रतिशत हो गई है, जो निजी शिक्षा की ओर अभिभावकों के झुकाव को दर्शाता है। यह बदलाव उस धारणा से प्रेरित है कि प्राइवेट स्कूल में बेहतर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, कड़ा अनुशासन और भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं। रिपोर्ट इस बात से आगाह भी करती है कि इस तरह की उम्मीदें हमेशा जमीनी परिणामों से मेल नहीं खाती हैं। आयोग ने कहा, "भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में, खासतौर पर माध्यमिक स्तर पर, निजी संस्थानों की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। यह बेहतर नतीजों के लिए अभिभावकों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, पर शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की इस तेज बढ़ोतरी ने गुणवत्ता, समानता और नियमन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।"

पांचवीं के 35% छात्र नहीं पढ़ पाते किताब: रिपोर्ट बताती है कि कम शुल्क वाले प्राइवेट (एलएफपी) स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। यहां पांचवीं कक्षा के 35 प्रतिशत छात्र कक्षा दो की किताब भी पढ़ नहीं पाते। 60 प्रतिशत छात्र बुनियादी भाग का सवाल हल नहीं कर पाते, जो कई निजी संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा करता है।

एक लाख स्कूल एक शिक्षक के भरोसे : देशभर में 14 लाख स्कूलों में 1.01 करोड़ शिक्षक हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के बावजूद कई ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में शिक्षकों की कमी है। एक लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं, जो सिर्फ एक-एक शिक्षक के भरोसे हैं।

प्राइवेट स्कूलों का ऐसा है हाल

रिपोर्ट के अनुसार, कई एलएफपी स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत बुनियादी मानकों को पूरा नहीं करते। वहां शौचालय, खेल के मैदान और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अक्सर अनौपचारिक होती है। उन्हें कम वेतन और नौकरी की सुरक्षा के बगैर काम करना पड़ता है, जिसका सीधा असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ता है।

नए शैक्षणिक सत्र के लिए एनसीईआरटी की केवल आधी पुस्तकें अब तक छपीं

- पाठ्यपुस्तकों की कमी पूरा करने को तेजी से प्रयास कर रहा एनसीईआरटी
- सत्र शुरू हुए एक माह से अधिक समय बीतने पर भी मांग- आपूर्ति में अंतर

नई दिल्ली, एएनआइ : शैक्षणिक सत्र शुरू हुए एक महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए संघर्ष कर रही है। अब तक केवल आधी से कुछ अधिक पुस्तकें ही छपी हैं। एनसीईआरटी ने नए पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कक्षा तीन से नौ तक की संशोधित पाठ्यपुस्तकें जारी की हैं और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए 15 करोड़ पुस्तकें छापने की योजना बनाई थी। हालांकि, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अब तक केवल आठ करोड़ प्रतियां ही छपी हैं। मांग व आपूर्ति के अंतर के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि मई में हम निर्धारित संख्या में पुस्तकें छाप पाएंगे।"

इस देरी के कारण कई छात्र नई पाठ्यपुस्तकों से वंचित हैं, जबकि शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। किताबों की उपलब्धता में देरी

के अलावा निजी स्कूलों की निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूंगो ने आरोप लगाया कि एक "शिक्षा माफिया" सस्ती स्कूली पुस्तकों के लिए सरकार के प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीएसई ने निजी स्कूलों से एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है।

मंडी नगर निगम के वार्ड में चुनाव का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, मंडी

- बैहना में पंचायत बहाली की मांग, जनता के दबाव में सभी प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए
- प्रशासन ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी रिपोर्ट, छह माह में होगा निर्णय
- आरोप, बिना शहरी सुविधाएं दिए, लोगों पर हाउस टैक्स का भारी आर्थिक बोझ डाला

मंडी नगर निगम। फाइल

हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम के वार्ड-14 बैहना में चुनाव बहिष्कार के घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है। पंचायत बहाली की मांग के जनता के दबाव में बुधवार को सभी प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए थे। अब यहां 17 मई को मतदान नहीं होगा। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में विरोध के कारणों और राजनीतिक दलों की सहमति का ब्योरा शामिल है। नियमों के अनुसार इस वार्ड में चुनाव कराने या जनता की मांगों पर विचार करने का निर्णय छह माह में लिया जा सकेगा। सामूहिक नामांकन वापसी से पैदा हुए संवैधानिक गतिरोध के बाद गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है।

बैहना वार्ड के लोगों ने पंचायत बहाली को मुख्य एजेंडा बनाया है। आरोप है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद पांच वर्ष में बुनियादी ढांचे पर कोई काम नहीं हुआ। बिना शहरी सुविधाएं दिए, लोगों पर हाउस टैक्स का भारी आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन संघर्ष समिति की विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी के बाद बुधवार को भाजपा के गुरबचन सिंह, कांग्रेस के धनदेव और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिए।

निकाय चुनाव के सामूहिक बहिष्कार का यह पहला मामला नहीं है। 2021 में हुए चुनावों में नगर परिषद नेरचौक और नगर पंचायत करसोग में लोग सामूहिक बहिष्कार कर चुके हैं।

> बैहना वार्ड से सभी प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई है। इसकी अधिकारिक रिपोर्ट सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। आगामी निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। **-अपूर्व देवगन, उपायुक्त मंडी।**

हिमाचल में सरकारी जमीन पर सास-ससुर का कब्जा तो बहू भी नहीं लड़ पाएगी चुनाव

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

- पंचायत चुनाव के लिए नियम लागू करने की राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राज्य सरकार ने और सख्त कदम उठाया है। यदि किसी महिला के सास-ससुर ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगी। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले नियम को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

बुधवार देर सायं राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल में पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी। अधिनियम की धारा 122 में संशोधन के निर्णय से प्रदेश में चुनाव लड़ने की इच्छुक कई महिला प्रत्याशियों को झटका लगा है। कई महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थीं और आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थीं, लेकिन अधिसूचना के बाद उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा पर पानी फिर गया है।

पहले क्या थी व्यवस्था : पहले की व्यवस्था के अनुसार, पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 122 में परिवार की परिभाषा में दादा-दादी, माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बेटी और अविवाहित बेटी का उल्लेख था। बहू का इसमें जिक्र नहीं था। इस कारण बहू चुनाव लड़ने के लिए योग्य मानी जाती थी।

1.60 लाख लोगों ने किए हैं कब्जे : अवैध कब्जों के मामले में 1.60 लाख लोग और उनके परिवार शामिल हैं। नियमों के अनुसार, ये पहले से ही चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माने जाते हैं। वर्ष 2003 में अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए इन परिवारों ने सरकार को स्वघोषणा के साथ दस्तावेज दिए थे।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

27943 वोटों से नाउदा में तृणमूल की साहिना मुमताज व रेजीनगर में अताउर रहमान को 58,876 मतों हराया हुमायूं कबीर ने। हुमायूं ने रेजीनगर सीट छोड़ने का एलान किया है। साथ ही उपचुनाव के लिए बेटे को उम्मीदवार भी बनाया है।

सुनियोजित थी हत्या, 50 सेकेंड में मारीं 10 गोलियां

सुवेंदु के निजी सचिव की हत्या का मामला, एसआइटी गठित

हत्या में इस्तेमाल एक बाइक भी बरामद, घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना की सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि इस आपरेशन को महज 50 सेकेंड में अंजाम दिया गया। चंद्रनाथ की कार के आसपास 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलीबारी अत्याधुनिक स्वचालित हथियार से की गई थी। पुलिस का अनुमान है कि चंद्रनाथ की कार को रोकने वाली कार में एक शार्प शूटर सवार था। दो बाइक सवार पीछे से पीछा कर रहे थे। कार चालक ने बाइक सवारों से सूचना का आदान-प्रदान किया। हत्या के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। तीनों घटना के छह घंटे पहले से इलाके में ही थे। घटनास्थल से बरामद कारतूस की जांच से पता चला है कि अपराध में आस्ट्रिया निर्मित पिस्तौल इस्तेमाल की गई है।

बता दें कि बुधवार रात 10:30 बजे मध्यमग्राम के दोहारिया में दो बाइक व कार से आए बदमाशों ने प्वाइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ को कार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना में चालक बुद्धदेव बेरा को भी गोली लगी थी। हालांकि अस्पताल में आपरेशन के बाद उसके शरीर में लगी गोली निकाल ली गई है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। जांच दल में राज्य पुलिस के अधिकारियों के साथ-साथ सीआइडी के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार, पहले कार के शीशे पर गोलियां चलाई गईं। जब शीशे में छेद हो गया, तो हमलावरों ने चंद्रनाथ की मौत सुनिश्चित करने के लिए वहीं से और गोलियां चलाईं।

बरामद बाइक आसनसोल के निवासी के नाम पर पंजीकृत : पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल की गई एक बाइक बरामद कर ली है। हत्या में इस्तेमाल किया गया वाहन बुधवार रात को जब्त किया गया था। चारपहिया वाहन का इस्तेमाल चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोकने के लिए किया गया था। पता चला है कि बदमाश बाइक को छोड़कर भाग गए। दूसरी बाइक की तलाश अभी जारी है। पता चला है कि बरामद बाइक आसनसोल निवासी बिभास भट्टाचार्य के नाम पर पंजीकृत है। लेकिन अब उस पते पर बिभास नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है।

<< पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर में गुरुवार को चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के भावुक होने पर सहारा देते लोग। आइएएनएस

कार के मालिक से पूछताछ

जांच में पता चला है कि अपराधियों द्वारा हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार पर जो नंबर प्लेट लगी है वह सिलीगुड़ी निवासी जेम्स विलियम्स के नाम पर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। उसने बताया कि अपनी कार को बेचने के लिए उसने विज्ञापन भी दिया था। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है।

तृणमूल का भड़काऊ भाषण घटना के लिए जिम्मेदार : चंद्रनाथ की मां

चंद्रनाथ मूल रूप से पूर्व मेदिनीपुर के चांदीपुर के रहने वाले थे, फिलहाल मध्यमग्राम के दोहारिया स्थित आवास में रह रहे थे। चंद्रनाथ की मां हासिरानी रथ ने अपने बेटे के हत्यारों के लिए फांसी नहीं, बल्कि उम्रकैद चाहती हैं। वह घटना के लिए तृणमूल के भड़काऊ भाषण को जिम्मेदार ठहराती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े होने के कारण चंद्रनाथ की यह परिणति हुई। हत्या के विरोध में इस दिन भाजपा समर्थकों ने जिले के शालबनी में सड़क जाम की। गुरुवार को बारासात अस्पताल में चंद्रनाथ के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया। पार्थिव शरीर को उनके चांदीपुर स्थित घर ले जाया गया। पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, चंद्रनाथ के करीबी उपस्थित थे।

मेरा सहयोगी होने और ममता को हराने की वजह से हुआ कत्ल

सुवेंदु ने गुरुवार को दावा किया कि चंद्रनाथ की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि वह उनके सहयोगी थे और भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। अधिकारी ने घटना को एक सुनियोजित हत्या करार दिया। नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि हत्या की साजिश बांग्लादेश से लोगों को बुलाकर रची गई हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने घटना को सुनियोजित राजनीतिक हत्या करार दिया और दावा किया कि इसका उद्देश्य राज्य में अस्थिरता पैदा करना है।

हावड़ा में तृणमूल-भाजपा समर्थकों में हिंसक झड़प, बमबाजी में एक दर्जन जख्मी

हावड़ा में गुरुवार को तृणमूल-भाजपा समर्थकों में हिंसक झड़प के बाद जमीन पर पड़े पत्थर। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- भाजपा की चुनावी जीत के जश्न दौरान बम फेंकने व गोलियां चलाने का आरोप
- हमलावरों ने गाली-गलौज की और फिर ईंट, कांच की बोतलें व बम फेंके

बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद तोड़फोड़ और राजनीतिक झड़पों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और हिंसा में बदल गया। इस दौरान फायरिंग व बमबाजी की गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। बाद में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और हालात पर काबू पाया। हावड़ा सिटी पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

भाजपा के हावड़ा जिला अध्यक्ष गौरांग भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि शमी अहम उर्फ बोरे और उसके समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उनका दावा है कि भाजपा की चुनावी जीत का जश्न मनाने के दौरान 12 से 15 बम फेंके गए और सात से आठ राउंड गोलियां चलाई गईं। उन्होंने कहा कि हमले में हावड़ा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने पहले गाली-गलौज की और फिर ईंट, कांच की बोतलें तथा बम फेंकने शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायरिंग और बमबाजी के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों का दावा है कि घटना में 12 से 15 लोग घायल हुए हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद शिवपुर इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

बमबाजी में पांच भाजपा कार्यकर्ता घायल : उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में बुधवार रात सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या की घटना के कुछ घंटे बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बमबाजी किए जाने का आरोप लगा है। घटना में पांच भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता को गोली मारी

बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके में भाजपा के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण प्राप्त बदमाशों ने गोली मार दी। भाजपा ने यह दावा किया। भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय को पेट में गोली लगने के कारण बशीरहाट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक वीडियो फुटेज में राय को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब वह कुछ अन्य लोगों के साथ अपने इलाके में भाजपा के झंडे लगा रहे थे, तभी तृणमूल के आठ से 10 कार्यकर्ताओं के एक समूह में से तीन बदमाशों ने उन पर गोली चलाई। उत्तर कोलकाता के बारानगर क्षेत्र में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किए जाने की घटना घटी है।

शाह की मौजूदगी में आज विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- मुख्यमंत्री पद की रेस में सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे
- कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शाम चार बजे से होगी विधायक दल की बैठक

बंगाल चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सबकी नजर राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर टिकी है कि पार्टी किसको यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है। शुक्रवार को इस पर से पर्दा हट जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोलकाता में रहेंगे। उनकी उपस्थिति में कोलकाता में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी।

बैठक कोलकाता के न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शाम चार बजे से होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में 2021 में नंदीग्राम के बाद इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता को उनके घर भवानीपुर में हराने वाले नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। अगले दिन नौ मई, शनिवार को कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के दिन नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व शाह सहित भाजपा शासित करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे।

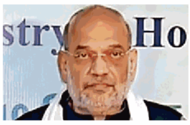

अमित शाह। फाइल

अखिलेश ने ममता से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं, हराई गई हैं

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- सपा प्रमुख ने बंगाल चुनाव में तृणमूल की करारी हार के बाद कोलकाता पहुंचकर ममता से मिलकर बांटा दुख

कोलकाता में गुरुवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एएनआइ >>

बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के तीन दिन बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कोलकाता पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर उनसे मुलाकात की। अखिलेश ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता को शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया और कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। बैठक के दौरान अखिलेश ने कहा कि दीदी आप जनता की नेता हैं। आरोप लगाया कि भाजपा ने मैनेज करके बंगाल चुनाव जीता है।

अखिलेश ने ममता के सांसद भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को गले लगाया और प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने भाजपा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम था कि निष्पक्ष चुनाव कराना, उन तमाम संस्थाओं ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। आरोप लगाया कि भाजपा ने लोगों को डराकर व बुलेट दिखाकर वोट कराया है। अखिलेश ने कहा कि ममता दीदी सदैव ही भाजपा की आंखों में खटकती हैं, क्योंकि इनकी सोच सामंती है। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जो तरीका अपनाया गया था, उसी माडल को बंगाल में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया। कहा कि जब भी ईमानदारी से चुनाव हुआ, दीदी जीतीं। आरोप लगाया कि अधिकारियों और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया।

अखिलेश के ममता से मुलाकात के सवाल पर सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि ममता से जो भी मिलेगा उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा।

केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर रविवार तक हो सकता है फैसला

- कांग्रेस विधानमंडल दल ने प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष को दिया मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार
- पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री चयन को लेकर सुने विधायकों के विचार, हाई कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला संभवतः रविवार तक हो जाएगा। एआइसीसी पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन ने अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर गुरुवार को विधायकों के विचार सुने। उन्होंने यूडीएफ सहयोगियों के भी विचार सुने। पर्यवेक्षक पार्टी हाई कमान को जल्द रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय लेंगे।

राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सीटों में से 102 सीटें हासिल कीं। इनमें से 63 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं।

फिलहाल मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार नजर आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं। खबरें हैं कि अधिकांश विधायक सांसद केसी. वेणुगोपाल का समर्थन कर रहे हैं।

रमेश चेन्नीथला, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल (बाएं से)। फाइल

कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि बैठक में एआइसीसी पर्यवेक्षकों और राज्य प्रभारी दीपा दासमुंसी के साथ कांग्रेस के सभी 63 नवनिर्वाचित विधायक मौजूद थे। प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को मुख्यमंत्री चयन का अधिकार दिया गया है।

पर्यवेक्षकों ने विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की और उनके विचार सुने। वे नई दिल्ली लौटकर हाई कमान को जानकारी देंगे, जिसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। विधायक के. मुरलीधरन ने बताया, रविवार तक पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा।

वासनिक ने कहा, विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल के अगले नेता का चयन करने का अधिकार दिया है। यह प्रस्ताव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश किया और विधायक दल के मौजूदा नेता वीडी सतीशन ने इसका समर्थन किया।

बंगाल में चुनाव आचार संहिता समाप्त, फलता में पाबंदी बरकरार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल से आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। 15 मार्च को चुनावी बिगुल बजने के साथ ही लागू हुई यह पाबंदियां चार मई को परिणाम घोषित होने के बाद समाप्त कर दी गई हैं। आयोग ने इस संबंध में बंगाल के मुख्य सचिव को औपचारिक अधिसूचना भेज दी है, जिससे अब इन राज्यों में विकास कार्य और प्रशासनिक नियुक्तियां सामान्य रूप से सुचारू हो सकेंगी।

भले ही पूरे राज्य से आचार संहिता हट गई हो, लेकिन दक्षिण 24 परगना जिले की 'फलता' विधानसभा सीट पर यह अभी भी प्रभावी रहेगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी और चुनावी अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए फलता में हुए पिछले मतदान को रद कर दिया है। अब यहां 21 मई को नए सिरे से मतदान कराया जाएगा, जिसके नतीजे 24 मई को घोषित होंगे।

असम में 12 को शपथ लेगी राजग सरकार

गुवाहाटी, प्रेट्र : नई निर्वाचित भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार की शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री और उद्योगों के प्रतिनिधियों के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पशु चिकित्सा क्षेत्र, खानापारा में किया जाएगा।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया, "असम के डीजीपी के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की, ताकि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारी का आकलन किया जा सके, जो नई निर्वाचित मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए होगी।"

उन्होंने कहा कि सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्थल की तैयारी, प्रोटोकाल और अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संपूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता, स्थापित प्रोटोकाल का सख्त पालन और सभी हितधारकों के बीच निकट समन्वय पर जोर दिया गया।

विगत बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा, जिन्होंने उन्हें देखरेख सरकार के प्रमुख के रूप में जारी रखने के लिए कहा।

रंगासामी का सीएम पद से इस्तीफा

पुडुचेरी, प्रेट्र : एआइएनआरसी के प्रमुख एन.रंगासामी ने गुरुवार को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपना त्यागपत्र उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन को लोकभवन में सौंप दिया है। रंगासामी ने गुरुवार को पत्रकार से कहा कि वह जल्द ही उप राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनकी अपनी पार्टी एआइएनआरसी के नेतृत्व वाले राजग के साथ पुडुचेरी का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसने इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों में शानदार अंतर से जीत हासिल की है। रंगासामी सरकार गठन के लिए एक शुभ दिन और समय पर विचार कर रहे हैं।

आल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 16 में से 12 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि भाजपा ने 10 में से चार सीटें जीती हैं। एआइएडीएमके और लाचिया जननायक काची (एलजेके) और अन्य एनडीए घटक ने एक-एक सीट पर सफलता प्राप्त की है और इस गठबंधन के पास 30 सदस्यीय सदन में 18 सीटें हैं।

एन.रंगासामी। फाइल

बंगाल में 'भगवा' लहर, नवान्न के बाद अब 'नगर निगम' पर कब्जे की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- नगर निगम के 144 में से 101 वार्डों में भाजपा को बढ़त, 'छोटा लालबाड़ी' में भी परिवर्तन के संकेत
- भ्रष्टाचार और 'सिंडिकेट राज' ने शहरी मतदाताओं को पूरी तरह नाराज कर दिया

बंगाल की सत्ता संरचना में ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब सबकी नजरें कोलकाता और उसके 'नगर निकाय' पर टिकी हैं। भाजपा की 'लुक ईस्ट' नीति की सफलता ने तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग 'छोटा लालबाड़ी' (कोलकाता नगर निगम) की नींव हिला दी है। विस चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जिस कोलकाता को तृणमूल अपना अभेद्य किला मानती थी, वहां अब कमल खिलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में से भाजपा ने 101 वार्डों में भारी बढ़त हासिल की है, जबकि तृणमूल महज 43 वार्डों तक सिमट गई है।

दिसंबर में होने वाले निगम चुनावों को लेकर अभी से राज्य की राजनीति गरमा गई है। तृणमूल के भीतर गहरा असंतोष और हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब कोलकाता नगर निगम को बचा पाना लगभग असंभव है। कसबा, तिलजला और राजाबाजार जैसे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को छोड़कर पार्टी के पास कोई सुरक्षित गलियारा नहीं बचा है। स्थानीय पार्षदों के खिलाफ जनता का आक्रोश और भ्रष्टाचार के आरोपों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर हुए भ्रष्टाचार और 'सिंडिकेट राज' ने शहरी मतदाताओं को पूरी तरह नाराज कर दिया है। पिछले 15 वर्षों में जिस तरह से जलाशयों को भरकर अवैध निर्माण किए गए, उसने मध्यमवर्गीय समाज में गहरा रोष पैदा किया।

हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान 1,445 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : हाल ही में चार राज्यों- बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 1,445 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और प्रलोभन के लिए इस्तेमाल की जानी वाली वस्तुएं जब्त की हैं। यह 2021 के चुनावों की तुलना में लगभग 40.14 प्रतिशत अधिक है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु में सर्वाधिक नकदी जब्त की गई है, वहीं सर्वाधिक शराब और मादक पदार्थ बंगाल में जब्त किए गए। बंगाल में 2021 के चुनावों की तुलना में जब्ती में सबसे अधिक 68.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तमिलनाडु में 2021 के चुनावों के दौरान के आंकड़ों की तुलना में 2026 में ज्बती में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लगभग 155 करोड़ रुपये की अवैध नकदी बरामद की गई, वहीं 183.33 करोड़ रुपये (लगभग 70 लाख लीटर) मूल्य की शराब भी जब्त की गई। गौरतलब है कि मतदाताओं को किसी विशेष पार्टी के लिए वोट देने के लिए लुभाने हेतु नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य प्रलोभन जैसे कि साड़ियां, कपड़े, प्रेशर कुकर, बर्तन और यहां तक कि टीवी भी बांटे जाते हैं। हिंसा-मुक्त, डर-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 376 पर्यवेक्षकों, 7,470 उड़न दस्ते और 7,470 निगरानी टीमों को तैनात किया गया था। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का क्रियान्वयन समाप्त हो गया है। हालांकि, यह बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में लागू है, जहां मतदान होना है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए दिशानिर्देश जारी करता है इसे एमसीसी कहते हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अप्रैल में मतदान हुआ था। मतगणना चार मई को हुई थी।

2021 के चुनावों की तुलना में लगभग 40.14 प्रतिशत अधिक की वृद्धि

- बंगाल में सबसे अधिक शराब जब्त, तमिलनाडु में सर्वाधिक नकदी बरामद

अन्नाद्रमुक ने 28 विधायक पुडुचेरी भेजे

प्रथम पृष्ठ से आगे

द्रमुक सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने एक बैठक में वामपंथी दलों सहित गठबंधन दलों के नेताओं के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा बने रहें। इस बीच, द्रविड़ विधायकों की एक अन्य बैठक में प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस द्वारा टीवीके को समर्थन देने की कड़ी निंदा की गई। इस बैठक में द्रमुक ने औपचारिक रूप से अपने दीर्घकालिक सहयोगी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। द्रमुक के प्रस्ताव में कांग्रेस की हालिया गतिविधियों को विश्वासघात करार दिया गया।

राजनीतिक गहमागहमी के बीच अन्नाद्रमुक ने अपने 28 विधायकों को पुडुचेरी भेज दिया है, जहां वे एक रिसार्ट में ठहरे हुए हैं। अन्नाद्रमुक महासचिव के पलानीस्वामी ने विधायकों से एकजुट रहने और धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया। सूत्रों का कहना है कि पलानीस्वामी टीवीके को समर्थन देने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं, जिससे पार्टी के एक वर्ग में मतभेद पैदा हो गया है।

बहुमत जुटाने की जद्दोजहद : 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 108 सीटें जीती। इस तरह वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों के जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। पांच सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दिया है। सरकार बनाने के लिए टीवीके को पांच और विधायकों के समर्थन की दरकार है। बहुमत जुटाने की जद्दोजहद में टीवीके ने वामपंथी दलों, वीसीके और आइयूएमएल को अपने साथ शामिल करने का प्रयास तेज कर दिया है।

टीवीके विधायक कीर्तना बोलीं-हिंदी से फैलाना चाहती हूं पार्टी का संदेश

चेन्नई, एएनआइ : शिवकाशी से टीवीके की विधायक एस. कीर्तना ने कहा कि उनकी पार्टी का संदेश परिवर्तन के लिए व्यापक दर्शकों तक पहुंचना चाहिए और हिंदी बोलने से इस उद्देश्य में मदद मिलती है। उन्होंने कहा, मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में, यहां तक कि अन्य देशों में भी फैलाना चाहती हूं। इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूं। सभी को मेरे नेता के बारे में जानना चाहिए।

हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प सोमनाथ

नरेन्द्र मोदी

सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, संस्कृति और एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता

वर्ष 2026 की शुरुआत में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। यह सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को मुझे एक बार फिर सोमनाथ जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस बार यह यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। मैं उस क्षण को फिर जीने जा रहा हूं, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। छह महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन दो महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।

सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हों, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है: प्रभासं च परिक्रम्य पृथिवीक्रमसंभवम्। अर्थात दिव्य प्रभास (सोमनाथ) की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है! जब लोग यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं, तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है, जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकी। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार-चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा।

यह समय उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी है, जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहीं। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे मनीषियों ने प्रभास को शैव दर्शन का महान केंद्र बनाया। चक्रवर्ती महाराज धारसेन चतुर्थ ने सदियों पहले वहां दूसरा मंदिर बनवाया। समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। कर्णदेव सोलंकी और जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। भाव बृहस्पति, कुमारपाल सोलंकी और पाशुपताचार्यों ने इस तीर्थ को आराधना और ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। विशालदेव वाघेला और त्रिपुरांतक ने इसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं की रक्षा की। महिपाल चूड़ासमा और राव खंगार चूड़ासमा ने विध्वंस के बाद पूजा-पाठ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी भक्ति की परंपरा को जीवंत रखा। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने तीर्थयात्रियों के अधिकारों की रक्षा की। इसके साथ ही हमारी यह धरती वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेगड़ाजी भील जैसे पराक्रमियों से धन्य हुई। उनके साहस और बलिदान को आज भी याद किया जाता है।

1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। उन्हें सोमनाथ मंदिर की दुर्दशा बहुत व्यथित करती थी। 13 नवंबर 1947 को दीवाली के समय उन्होंने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर, समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, ''इस (गुजराती) नववर्ष पर हमारा निश्चय है कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। सौराष्ट्र के लोगों को इसके लिए हर तरह से अपना योगदान देना होगा। यह एक पावन कार्य है, जिसमें हर किसी को भागीदारी निभानी होगी।'' उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया।

सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन सुनाता है सोमनाथ मंदिर। फाइल

दुर्भाग्यवश सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था। इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बावजूद प्रभास पाटन की पावन धरती पर उनका प्रभाव निरंतर महसूस किया जाता रहा। उनके विजन को केएम मुंशी ने आगे बढ़ाया, जिन्हें नवानगर के जामसाहेब का समर्थन मिला। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने पर राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद डा. प्रसाद ने समारोह में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

मुझे अक्टूबर 2001 का वह समय अच्छे से याद है, जब मैंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था। 31 अक्टूबर 2001 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 50वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया। उसी समय सरदार पटेल की 125वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी ने इसे और भी गरिमापूर्ण बना दिया।

11 मई 1951 को अपने भाषण में डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को यह संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह मंदिर सदैव लोगों के हृदय में बसा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है और उनकी भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसे लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे। पिछले एक दशक से हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं। 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र से प्रेरित होकर सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक, हमने अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। साथ ही उनकी पारंपरिक पहचान को भी बनाए रखा है। आज बेहतर कनेक्टिविटी से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ पा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है, आजीविका सुरक्षित हो रही है, साथ ही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना और सशक्त हो रही है।

सोमनाथ की रक्षा और इसके पुनर्निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनका संघर्ष हम कभी नहीं भुला सकते। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने इसकी भव्यता और दिव्यता को लौटाने में अपना अद्भुत योगदान दिया। उनकी ऐसी ही आस्था पूरे भारतवर्ष को लेकर भी थी। वे एकता की ऐसी अद्भुत डोर से बंधे थे, जिसे जमीनी सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता। आज की विभाजित दुनिया में सोमनाथ से मिलने वाली एकता की यह सीख पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। इसी गौरव को नमन करते हुए बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में और दानवीरों की उदारता को याद करते हुए अगले एक हजार दिनों तक यहां विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस पुनीत कार्य में योगदान दे रहे हैं।

सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि जब कोई समाज अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी एकता से जुड़ा रहता है, तब उसे लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही साझा चेतना है, यही एकात्म भाव है। यही भावना हमें विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में साथ चलने की प्रेरणा देती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस पावन अवसर पर पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करें और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करें। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे, तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी, जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। सोमनाथ में आप भारत के उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे, जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा, जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

खाएंगे-रहेंगे भारत में और गीत गाएंगे दुश्मन के, यह नहीं चलेगा

- देवबंद में जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अब तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण
- बोले, जनभावना का सम्मान करने वाली सरकार ही सत्ता में लौटेगी

सहारनपुर के गांव जड़ौदा जट्ट में आयोजित रैली को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनभावना का सम्मान करने वाली सरकार ही दोबारा सत्ता में लौटेगी। हालिया चुनाव परिणामों को विभाजनकारी ताकतों के लिए आईना बताते हुए कहा कि अब समाज बंटने वाला नहीं है। चेताया कि अगर कोई भी अब भारत के प्रतीकों का अपमान करेगा तो उसे सजा होगी।

यह नहीं चलेगा कि खाएंगे-रहेंगे भारत में और दुश्मन के गीत गाएंगे। मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि पहले खाना कैसे खाना है, इसके लिए भी देवबंद से फतवा जारी होता था। कुछ लोग इसका ठेका ले चुके थे। आज जो पैसा माता शाकंभरी कारिडोर पर खर्च हो रहा है, पहले वही पैसा तुष्टीकरण के नाम पर कब्रिस्तान की चारदिवारी के लिए खर्च होता था। अब वह सड़क, शिक्षा और विकास पर खर्च हो रहा है। आज यह पैसा तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर खर्च हो रहा है।

गुरुवार को देवबंद के गांव जड़ौदा जट में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में तीसरी बार, पुडुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर उन सभी राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया जो विभाजनकारी सोच रखते हैं। विकास में बाधक तत्व जाति के नाम पर बांटने का काम करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। आगे कहा कि ऐसे लोग समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। माफिया को संरक्षण देकर युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा करते हैं।

कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम-तमाम होना तय : योगी ने कहा कि फतवे की कुसंस्कृति से मुक्त होकर सहारनपुर खुद को गति-प्रगति देकर देश की समृद्धि में सहयोग कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी पर रोक नहीं लगा सकता। अब कोई कांवड़ यात्रा नहीं रोक सकता है, अब कोई बहन-बेटी को छेड़ नहीं सकता, व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता।

अगर कोई ऐसा करता है तो उसे उसका अंजाम भी पता है। हमने एटीएस का सेंटर यहां दिया। अब एटीएस के कमांडो निगरानी करते हैं। कोई भी देशद्रोही सिर उठाएगा तो उसका काम-तमाम होना तय है। डबल इंजन सरकार बनने से स्थिति बदल गई है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के लिए 2,131 करोड़ रुपये की 325 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही 1,651 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया।

सम्राट की टीम में डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के अलावा कई उद्यमी भी

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- अनुभवी बुजुर्ग के साथ युवा जोश का भी समन्वय

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में समाज के हर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को जगह मिली है। अनुभवी बुजुर्ग हैं तो युवा भी हैं। इनमें डाक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और उद्यमी शामिल हैं। पहली बार मंत्री बने कुमार शैलेंद्र और निशांत कुमार इंजीनियर हैं। दूसरी बार मंत्री बने दीपक प्रकाश भी इंजीनियर हैं। डा. दिलीप कुमार जायसवाल, डा. अशोक चौधरी, डा. प्रमोद कुमार और डा. रामचंद्र प्रसाद के पास पीएचडी की उपाधि है। डा. अशोक चौधरी पटना के एएन कालेज में प्राध्यापक हैं। विजय सिन्हा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।

सम्राट की टीम में सफल उद्यमी भी हैं। डा. दिलीप कुमार जायसवाल निजी मेडिकल कालेज का संचालन करते हैं। लोजपा (रा) कोटे के मंत्री संजय कुमार सिंह की पहचान एक बिल्डर की है। नीतीश मिश्रा एमबीए हैं। कुछ ऐसे भी मंत्री हैं, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई है। लेकिन, उनका सामाजिक सरोकार लंबा रहा है। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार इन्हीं में शामिल हैं। उनकी पढ़ाई 12 वीं तक हुई है। वह छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। लेशी सिंह भी 12 वीं पास हैं। वह पूणिया जिले के धमदाहा से पांच बार विधायक चुनी गई हैं। संजय सिंह टाइगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। रामकृपाल यादव, दामोदर रावत, श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, केदार गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, शैलेश कुमार ऊर्फ बुलो मंडल की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है।

सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल

मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। चार महिलाएं मंत्री बनी हैं। 35 में नौ मंत्री सामान्य वर्ग के हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की संख्या नौ-नौ है। अनुसूचित जाति के सात विधायक मंत्री बने हैं। जदयू के जमा खान को भी जगह मिली है। वह मुस्लिम समुदाय के इकलौते मंत्री हैं। सम्राट का मंत्रिमंडल इस लिहाज से अलग है कि इसमें राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र शामिल हैं। ये हैं- पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन और डा. जगन्नाथ मिश्र के पुत्र नीतीश मिश्रा।

बिहार में नीतीश के बेटे निशांत समेत 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
- गत 15 अप्रैल को सीएम सम्राट के साथ दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव ने ली थी शपथ
- मंत्रिमंडल में भाजपा के 15, जदयू के 13, लोजपा (रा) के दो और हम व रालोमो के एक-एक मंत्री शामिल

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार ने राज्य की राजनीति में कई नए संकेत दिए हैं। गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ भव्य समारोह 32 मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके माध्यम से भाजपा ने सहयोगी दलों को भी साधने की कोशिश की है। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक निष्ठा एवं नई पीढ़ी को अवसर देने की रणनीति इस विस्तार में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अब सम्राट मंत्रिमंडल की संख्या 35 हो गई है। फिर भी एक मंत्री के लिए संभावना शेष है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बिहार एनडीए के चार घटक दल के प्रमुख शपथ ग्रहण के साक्षी बने। समारोह में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, लोजपा (रा) प्रमुख चिराग पासवान, हम (सेक्युलर) के संतोष सुमन एवं रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सम्मिलित हुए। मंत्रिमंडल गठन में एनडीए दलों ने अत्यंत सावधानी से जातीय एवं क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। पिछड़ा, अति-पिछड़ा, दलित, सवर्ण, युवा एवं महिला प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाकर व्यापक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। खासकर वैश्य, अति-पिछड़ा एवं युवा चेहरों को प्राथमिकता देकर भाजपा ने अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समूहों को भी साधने का संकेत दिया है।

पटना में गुरुवार को मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ ग्रहण करते (बाएं से) श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेशी सिंह। एएनआइ

पटना में गुरुवार को नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ (बाएं से) बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा। प्रेट्र

संगठन में लंबे समय से सक्रिय लोगों को जगह : राजनीतिक रूप से यह विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाजपा अब बिहार में केवल सहयोगी दल की भूमिका में नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। मंत्रिमंडल में ऐसे नेताओं को जगह दी गई है, जो संगठन के प्रति लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और जिनकी क्षेत्रीय पकड़ मजबूत मानी जाती है। इससे कार्यकर्ताओं में यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि संगठन के प्रति निष्ठा का राजनीतिक प्रतिफल मिलता है।

पीढ़ीगत बदलाव का संदेश: मंत्रिमंडल विस्तार का एक बड़ा संदेश पीढ़ीगत बदलाव को लेकर भी माना जा रहा है। पार्टी ने कई नए एवं युवा चेहरों को अवसर देकर यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में भाजपा बिहार की राजनीति में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करेगी। वहीं, मंगल पांडेय जैसे वरिष्ठ नेताओं को बाहर रखकर संगठनात्मक दायित्व देने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में तेज है।

भाजपा की 'टीम यूपी' तैयार, अब हाईकमान की मुहर का इंतजार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- योगी मंत्रिमंडल में बदलाव से बच कर खाली पदों को ही भरने का विचार
- संगठन के जरिये ही जातीय समीकरण साधेगी, अगले सप्ताह होगी घोषणा

बंगाल और असम में प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा अब उत्तर प्रदेश का मैदान मारने के लिए कमर कस कर तैयार है। 2027 के इस चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी 'टीम यूपी' लगभग बना ली है। प्रदेश नेतृत्व ने योगी मंत्रिमंडल के नए प्रस्तावित चेहरों और प्रदेश संगठन की टीम के लिए नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। अब असम और बंगाल का शपथ ग्रहण समारोह पूरा होते ही अगले सप्ताह की शुरुआत में इनकी घोषणा कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि योगी मंत्रिमंडल में किसी तरह के बदलाव से बचते हुए सिर्फ रिक्त पदों को ही भरते हुए सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का विचार है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। तभी से नई प्रदेश कार्यकारिणी की प्रतीक्षा चल रही है। इसी तरह से योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कुछ मंत्रियों को हटाने और नए चेहरों को शामिल करने की अटकलें चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता सरकार और संगठन को विधानसभा चुनाव के समीकरणों के अनुरूप तैयार करने की कसरत में जुटे भी हुए हैं, बस प्रतीक्षा थी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने की। चुनाव परिणाम आ चुके हैं।

प्रतीकात्मक

बंगाल में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस का किला ढहाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। पुडुचेरी में भी राजग को बहुमत मिला है। अब सभी की नजरें सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर हैं। यहां भी भाजपा के सामने तीसरी बार सरकार बनाने के अवसर के साथ ही सत्ता बचाने की चुनौती भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित वोटों वाले पीडीए फार्मूले से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका दे चुकी है। ऐसे में सरकार और संगठन के स्वरूप को जातीय समीकरणों के अनुरूप ही तैयार किया जाना तय है। बताया गया है कि योगी मंत्रिमंडल में वर्तमान मंत्रियों को हटाए जाने जैसा कोई विचार फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व का नहीं है। उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री बन सकते हैं और वर्तमान में 54 हैं। इस तरह छह नए मंत्री बनाए जाने की गुंजाइश है। अधिक संभावना यही है कि जातीय समीकरणों का संतुलन साधते हुए नए चेहरे शामिल होंगे। वहीं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कहना है कि प्रदेश संगठन के प्रस्तावित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है। योगी मंत्रिमंडल में भी सामाजिक संतुलन रहेगा। उन्होंने बताया कि संभवतः अगले सप्ताह की शुरुआत में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन की टीम की घोषणा हो जाएगी।

पेंशन में देरी पर रक्षा सचिव व थल सेना प्रमुख के वेतन से कटेंगे तीन लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़: आदेश के बावजूद पूर्व सैन्य अधिकारी को दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं देने और 21 साल की देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने इस देरी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए राशि की कटौती रक्षा सचिव व थल सेना प्रमुख के वेतन से करने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़ निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल शंजीत सिंह भुल्लर ने हाई कोर्ट को बताया कि वह 1981 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वर्ष 1991 में वह बाबीना में कैप्टन के पद पर तैनात थे, जहां ड्यूटी के दौरान उनके बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी। बाद में उन्हें लखनऊ के सैन्य अस्पताल भेजा गया। मेडिकल बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता को सैन्य सेवा से संबंधित माना था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्हें दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। वहां से राहत नहीं मिलने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2025 को आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को चार सप्ताह के भीतर फैसला लागू करने के निर्देश दिए थे। फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ।

भाजपा ने मान को कानूनी नोटिस भेज बयान वापस लेने को कहा

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- मुख्यमंत्री ने पंजाब में धमाकों के पीछे भाजपा का हाथ होने का लगाया था आरोप

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से जालंधर व अमृतसर में हुए धमाकों के पीछे भाजपा का हाथ होने के आरोप के बाद भाजपा ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान अपने डीजीपी के बयान के विपरीत है। यदि सात दिन के भीतर मुख्यमंत्री अपना बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पंजाब की जनता भी जानना चाहती है कि साक्ष्य कहां हैं?

चुग ने कहा कि पंजाब आज नशे, बम धमाकों, गैंगस्टर नेटवर्क और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन मान सरकार अपनी हर विफलता को छिपाने के लिए भाजपा पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश आपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर अपनी वीर सेना के साहस और शौर्य का जश्न मना रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा जैसे एक लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी दल को आतंकवादी घटनाओं से जोड़ना सिर्फ एक राजनीतिक झूठ नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों के जनादेश और विश्वास का अपमान है।

भगवंत मान। फाइल

राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने सात दिन के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की

धमाके भाजपा के 'मिशन पंजाब' का हिस्सा : संजय सिंह

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव वाले राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने के लिए अमृतसर व जालंधर में हुए दोहरे धमाकों के जरिये अपना 'मिशन पंजाब' शुरू किया है। उन्होंने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि बंगाल में भी भाजपा की जीत के बाद चुनावोत्तर हिंसा देखने को मिल रही है। कहा, भाजपा व आइएसआइ के बीच सीधा संबंध है। हमने इसे पठानकोट कांड में भी देखा है।

फर्जी आइएएस विप्रा और बहन शिखा पर नौ और एफआइआर

जागरण संवाददाता, बरेली : फर्जी आइएएस विप्रा शर्मा और उसकी बहन शिखा पाठक का ठगी का जाल कालोनियों से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक फैला था। गुरुवार को उनके विरुद्ध दो भाइयों समेत 10 पीड़ितों ने नौ प्राथमिकी दर्ज कराईं। उनमें किसी को सहायक विकास अधिकारी, क्लर्क, लेखपाल या वाहन चालक की नौकरी दिलाने के नाम पर 56.4 लाख रुपये ठगे गए। सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी डाक से भेजे गए थे। वे लोग विभाग में ज्वाइन करने पहुंची तो फर्जीवाड़ा के बारे में जानकारी हुई। अब तक ठग बहनों पर 13 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।

सिविल सेवा की परीक्षा में असफल रहने के बाद विप्रा शर्मा खुद को आइएएस बताकर हनक दिखाने लगी। बीते दिनों विप्रा, उसकी बहन शिखा व रिश्तेदार दीक्षा को जेल भेजा जा चुका। गुरुवार को मो. कफील ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि वर्ष 2021 में खुद को एसडीएम बताने वाली विप्रा शर्मा ने सचिवालय में अच्छी पैठ का झांसा देकर नौकरी का वादा किया। इस बहाने 5.25 लाख रुपये लेकर बदायूं के इस्लाम नगर ब्लाक में सहायक विकास अधिकारी के पद का फर्जी नियुक्ति पत्र भेज दिया।

4.5 करोड़ रुपये की संपत्ति श्रीनगर और अनंतनाग पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अटैच की। श्रीनगर पुलिस ने चनपोरा और कमरवाड़ी क्षेत्रों में ड्रग तस्करों की दो करोड़ और अनंतनाग पुलिस ने भी लगभग 2.5 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति अटैच की।

आपरेशन सिंदूर का एक साल

भारत के प्रतिशोध का प्रतीक बनी 7 मई की रात

आज से ठीक एक वर्ष पहले 7 मई की रात भारत के प्रतिशोध का प्रतीक बनी थी। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार सीमा पार स्थित आतंकी ढांचे का समूल नाश करने के लिए भारत ने आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रात 1:44 बजे सशस्त्र सेनाओं ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से आतंकी ढांचे पर जबरदस्त प्रहार किए। 22 मिनट में कुल 9 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया। आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर पेश हैं, 6 स्तंभ जो एक नए भारत को दर्शाते हैं,जो स्पष्ट सोचता है, मजबूत योजना बनाता है और सही समय पर निर्णायक कार्रवाई करता है।

1 भारत की नियंत्रित युद्धनीति

भारत ने सिर्फ 88 घंटों में दुश्मन को अधिकतम नुकसान पहुंचाते हुए चार दिनों के अंदर अपनी शर्तों पर अभियान समाप्त किया।

आंतकियों पर सटीक हमला, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं।

पाकिस्तान की वायुसेना की 20% क्षमता ध्वस्त कर दी।

2 आतंकी ढांचे पर प्रहार

लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।

100 से अधिक आतंकी मारे गए, इसमें आइसी 814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल आतंकी भी शामिल थे।

परमाणु हमले की धमकी से डराने की पाकिस्तान की रणनीति को खोखला साबित किया।

3 अधिकतम नुकसान

एक ही आपरेशन में परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस पर सटीक प्रहार करने वाला भारत पहला देश बना।

9 आतंकी ठिकानों का चयन बेहद सटीक रणनीति के तहत किया गया, जिससे अधिकतम आतंकियों को निशाना बनाया जा सके।

4 दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति

पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने सिर्फ डोजियर सौंपने की नीति से आगे बढ़ कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता चुना।

सशस्त्र बलों को पूर्ण आपरेशनल स्वतंत्रता दी गई।

सिंधु जल संधि को स्थगित करके भारत ने साफ कर दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते।

संदेश बिल्कुल स्पष्ट था : **पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।**

5 एकजुट हुआ राष्ट्र

इसरो ने अंतरिक्ष को रणनीतिक बढ़त में बदल दिया। 10 उपग्रहों के जरिये जल, थल, नभ में लगातार खुफिया निगरानी सुनिश्चित की गई।

भारतीय सांसदों ने 32 देशों में जाकर पाकिस्तानी दुष्प्रचार का मजबूती से जवाब दिया।

ये है नया भारत 6

दुनिया ने भारत की कार्रवाई को देखा- स्टीक, निडर, स्वदेशी और एकजुट

आपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत युद्ध के लिए तैयार है।

न्यूज गैलरी

अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार

जयपुर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिये को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी घुसपैठिया बाड़मेर जिले में बीएसएफ की अशोक पोस्ट तक पहुंच गया था। यह स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब आठ सौ मीटर भारतीय सीमा में है। सोमवार को बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिये को पकड़कर धनाऊ थाना पुलिस को सौंप दिया है। (जासं)

खतरनाक जहर से गुजरात में नरसंहार की रची थी साजिश

अहमदाबाद : अरंडी के तेल से बनने वाले खतरनाक जहर राइसिन से हैदराबाद के डा. सैयद अहमद मोहिउद्दीन ने गुजरात में नरसंहार की साजिश रची थी। एटीएस ने डाक्टर और उसके दो अन्य साथियों को नवंबर 2025 में गिरफ्तार कर लिया था। एनआइए की ओर से विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र में बताया गया है कि विदेश में बैठे आतंकियों के इशारे पर हैदराबाद और राजस्थान के तीन युवकों ने गुजरात में राइसिन नामक रासायनिक जहर के जरिये नरसंहार करने की साजिश रची थी। (राब्यू)

एनएसए को चुनौती देने वाली अमृतपाल की याचिका खारिज

चंडीगढ़: खडूर साहिब से सांसद और 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख अमृतपाल सिंह की दूसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस दूसरे एनएसए आदेश को चुनौती दी गई थी, उसकी अवधि अप्रैल 2025 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद तीसरा एनएसए भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अब इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य या कानूनी आधार शेष नहीं रह जाता। (राब्यू)

मणिपुर में उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगाई

इंफाल, भारत-म्यांमार सीमा के पास मणिपुर के कामजोंग जिले के गांवों पर हथियारों से लैस उग्रवादियों ने गुरुवार तड़के हमला किया और घरों में आग लगा दी। स्थानीय निवासियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। पुलिस के अनुसार, उग्रवादियों ने तड़के करीब चार बजे कसोम खुल्लेन पुलिस थाना क्षेत्र के तांगखुल न्गा गांवों नामली, वांगली और चोरो पर हमला किया, जिसके कारण सीमावर्ती बस्तियों के निवासियों को पास के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। ये गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं। हमले के दौरान भागने की कोशिश में एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, नामली में दो घर, वांगली में तीन-चार घर और चोरो में एक चर्च को छोड़कर कई घर जलकर खाक हो गए। फुंग्यार के विधायक एल. कीशिंग ने आरोप लगाया कि यह हमला सीमा पार से म्यांमार स्थित उग्रवादी समूहों कुकी नेशनल आर्मी (बर्मा) और पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) द्वारा किया गया। (प्रेट्र)

आतंकवाद के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' दर्शाता है दृढ़ प्रतिक्रिया : मोदी

हम आतंकवाद व उसके इको सिस्टम को खत्म करने के संकल्प पर अडिग

शाह बोले- 'आपरेशन सिंदूर' दुश्मनों को हमारी सशस्त्र सेनाओं की सटीक प्रहार शक्ति की याद दिलाता रहेगा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'आपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर गुरुवार को कहा कि यह आपरेशन भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ प्रतिक्रिया को दर्शाता है। आपरेशन सिंदूर में भारत को मिली असाधारण विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और देशभक्ति की प्रेरक मिसाल है। उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पर हर देशवासी को गर्व है। एएनआइ के अनुसार, एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा- "एक वर्ष पहले, हमारे सशस्त्र बलों ने आपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने उन लोगों को उचित जवाब दिया जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिमाकत की थी। पूरा देश हमारे बलों को उनके साहस के लिए सलाम करता है। आपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाया।" मोदी ने आगे कहा कि इसने हमारे सशस्त्र बलों की पेशेवरता, तैयारी और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। साथ ही, इसने हमारे बलों के बीच बढ़ती संयुक्तता को भी प्रदर्शित किया। इसने यह भी दर्शाया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना मजबूत किया है। आज, एक वर्ष बाद भी हम आतंकवाद को खत्म करने और उसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने के अपने संकल्प पर हम पहले की तरह ही अडिग हैं।

आइएएनएस के अनुसार, गृह मंत्री शाह ने एक पोस्ट में कहा- "आपरेशन सिंदूर भारत का एक ऐतिहासिक मिशन है जो हमेशा हमारे दुश्मनों को हमारी सशस्त्र सेनाओं की सटीक प्रहार शक्ति की याद दिलाएगा। यह दिन हमारे दुश्मनों को साफ संदेश देता रहेगा कि चाहे वे कहीं भी छिपें, वे बच नहीं सकते। वे हमेशा हमारी नजर में हैं। मैं आज के दिन हमारी सेनाओं की अद्वितीय वीरता को सलाम करता हूं।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदानों को सलाम करते हैं। उनका साहस और समर्पण अतुलनीय है और यह राष्ट्र की रक्षा करता है। हमारे सशस्त्र बल हमेशा निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं।

मोदी, शाह समेत भाजपा नेताओं ने बदली डीपी

प्रेट्र के अनुसार, आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत अनेक भाजपा नेताओं ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर (डीपी) को बदल लिया। नई डीपी में भारतीय तिरंगे के साथ आपरेशन सिंदूर का आधिकारिक लोगो प्रमुखता से दिखाया गया है। इस तस्वीर में तिरंगा है, जिसमें 'सिंदूर' के 'ओ' को लाल रंग से भरा गया है, जो विवाहित हिंदू महिलाओं का प्रतीक है। पीएम ने सभी से अनुरोध किया कि वे भी सशस्त्र बलों और उनकी सफलता के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में ऐसा करें।

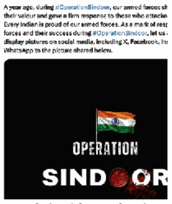

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी आपरेशन सिंदूर के लोगो की एक्स पोस्ट। इंटरनेट मीडिया

आतंकवाद के विरुद्ध रक्षा का अधिकार हमारे पास : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत का स्पष्ट संदेश
- कहा, सिंधु जल बंटवारे पर भी जारी रहेगा भारत का कड़ा रुख

आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध उसकी जीरो टालरेंस की नीति बिना किसी समझौते के जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पास आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को और मजबूत करेगा। साथ ही सिंधु जल बंटवारे पर भी भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'आज हम आपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकी हमले को उसकी असली सूरत में देखा था। पाकिस्तान द्वारा पोषित सीमापार आतंकवाद के प्रायोजन के जवाब में हमने उचित प्रत्युत्तर दिया है।' उन्होंने आगे कहा, 'दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के लिए सीमापार आतंकवाद लंबे समय से वहां की सरकार की नीति का हिस्सा रहा है। भारत में हम आतंकवाद के विरुद्ध खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार रखते हैं। हम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे।' 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों (ज्यादातर पर्यटक) की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद भारत ने सात मई, 2025 को आपरेशन सिंदूर शुरू किया। 88 घंटे चले इस सटीक सैन्य अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने पाकिस्तान एवं गुलाम जम्मू-कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया था। आपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों और दूसरे कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार का हमेशा से रुख रहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।

रणधीर जायसवाल। फाइल

आपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर भी अपनी स्थिति सख्त कर ली थी। आपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर सरकार ने एक बार फिर संकेत दिया कि जल बंटवारे के मामले में भी भारत, पाकिस्तान के किसी भी गलत कदम का उचित जवाब देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना ने भी वर्षगांठ पर आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प दोहराया है। भारतीय वायुसेना ने आपरेशन के 88 सेकेंड के विशेष फुटेज जारी किए, जिसमें आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की तस्वीरें शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने विश्व समुदाय से भी अपील की है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया जाए और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं।

पाकिस्तान बोला, अपनी सैन्य क्षमताओं को उन्नत करते रहेंगे

इस्लामाबाद, प्रेट्र : 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत के हाथों बुरी तरह पिटने वाली पाकिस्तान सेना ने 'मार्का-ए-हक' (भारत के साथ पिछले वर्ष हुए चार दिवसीय संघर्ष) की पहली वर्षगांठ पर अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। रावलपिंडी से जारी एक आधिकारिक बयान में सेना ने कहा कि वह भविष्य की चुनौतियों से निपटने और किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करना जारी रखेगी।

सेना ने इस संघर्ष को देश के सैन्य इतिहास का एक "निर्णायक अध्याय" बताया। बयान के अनुसार, सशस्त्र बल बदलते भू-राजनीतिक परिवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं।

पाकिस्तान अब उन्नत तकनीकों और पेशेवर उत्कृष्टता में निवेश कर रहा है ताकि भविष्य के युद्धक्षेत्र के लिए तैयार रहा जा सके। पाक सेना ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि देश के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण योजना का जवाब पिछले वर्ष की तुलना में अधिक शक्ति, सटीकता और संकल्प के साथ दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत से कभी पीछे नहीं हटा है...हमने बार-बार बातचीत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। हालांकि, इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, और सार्थक वार्ता के लिए यह एकतरफा नहीं बल्कि वास्तविक बातचीत होनी चाहिए।" बता दें कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई थी।

छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला माओवादी हमला मामले में सभी आरोपित बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को किया खारिज
- कहा- यह अत्यंत पीड़ादायक है, अभियोजन एजेंसियां जांच में हुईं नाकाम, 76 जवान हुए थे बलिदान

सुकमा के ताड़मेटला माओवादी हमले के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। 76 जवानों के बलिदान से जुड़े इस चर्चित केस में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सभी आरोपितों को बरी करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर के निर्णय को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने जांच एजेंसियों की नाकामी पर कड़ी टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक है कि माओवादियों द्वारा किए गए क्रूर हमले में सीआरपीएफ के जवानों की मृत्यु के बावजूद अभियोजन एजेंसियां असली अपराधियों की पहचान करने में असफल रहीं।

बता दें कि इस हत्याकांड के आरोपितों को दक्षिण बस्तर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात जनवरी 2013 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था।

यह था मामला

यह मामला छह अप्रैल 2010 का है, जब सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन और पुलिस बल की संयुक्त टीम पर माओवादियों ने हमला किया था, जिसमें 76 जवान बलिदान हुए थे।

इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कोर्ट में जांच की कमियों को उजागर किया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों को समझने में विफलता दिखाई। हालांकि, साक्ष्यों की कमी के कारण हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने भविष्य के लिए निर्देश दिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में फोरेंसिक सबूत समय पर जुटाए जाएं।

विमान में सहयात्रियों ने महुआ को देख लगाए 'चोर-चोर' के नारे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जन-आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में कृष्णनगर की सांसद महुआ मोइत्रा को उस समय बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में उनके सहयात्रियों ने उन्हें देखते ही नारेबाजी शुरू कर दी। यात्रियों ने विमान के अंदर ही पीसी (बुआ) चोर, भाईपो (भतीजा) चोर, तृणमूल के सब चोर और जय श्रीराम के नारे लगाए।

महुआ ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि वह गुरुवार को संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली जा रही थीं। तभी यह घटना हुई। महुआ का आरोप है कि फ्लाइट लैंड होने के बाद और विमान का दरवाजा खुलने से पहले उन लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उसका वीडियो भी बनाया। हालांकि वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

सोहराबुद्दीन मामला : 2010 में सीबीआइ को सौंप दी गई थी जांच

प्रथम पृष्ठ से आगे

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जांच राज्य सीआइडी से लेकर सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ ने 38 लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी डीजी वंजारा समेत कई हाई-प्रोफाइल नाम शामिल थे। हालांकि, मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले ही साक्ष्यों के अभाव में अमित शाह और डीजी वंजारा समेत 16 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया गया था। शेष 22 आरोपितों, जिनमें से अधिकांश कनिष्ठ पुलिसकर्मी थे, के विरुद्ध मुंबई की विशेष सीबीआइ अदालत में मुकदमा चला।

मुकरे 92 गवाह : दिसंबर, 2018 में विशेष अदालत ने सभी 22 आरोपितों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष के 210 में से 92 गवाह 'होस्टाइल' (मुकर जाना) हो गए, जिससे साजिश और हत्या के आरोपों की कड़ी साबित नहीं हो सकी। इस फैसले को सोहराबुद्दीन के भाइयों रुबाबुद्दीन एवं नायबुद्दीन ने 'परिवार के सदस्यों को खोने वाले पीड़ितों की हैसियत से' बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में मुकदमे को मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा था कि यह मुकदमा इस तरह चलाया गया था, जिससे न्याय का उद्देश्य ही विफल हो गया। विशेष सीबीआइ जज ने अपना निर्णय निराधार मान्यताओं एवं साक्ष्यों के स्पष्ट रूप से गलत मूल्यांकन कर सुनाया था। बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले रुबाबुद्दीन ने गृह मंत्रालय, सीबीआइ निदेशक एवं कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से सीबीआइ अदालत के फैसले को चुनौती देने का आग्रह किया था। सरकार द्वारा फैसले को चुनौती नहीं देने पर रुबाबुद्दीन और नायबुद्दीन ने स्वयं याचिका दायर करने का फैसला किया था। हालांकि अभियोजन पक्ष सीबीआइ ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है और वह इसके विरुद्ध कोई याचिका नहीं दायर करेगी।

भाजपा कार्यालय पर हमले के लिए ग्रेनेड पहुंचाने वाला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालंधर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के बाहर मंगलवार रात को हुए धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने जमशेर इलाके से आतंकी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। नवांशहर के रहने वाले दविंदर ने ही चंडीगढ़ स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर धमाके के लिए हैंड ग्रेनेड पहुंचाया था। वह आतंकी संगठन खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ) और खालिस्तान लिब्रेशन आर्मी (केएलए) के लिए ग्रेनेड व आइईडी पहुंचाने के लिए कुरियर का काम करता था। शक है कि जालंधर और अमृतसर में धमाके के लिए उसने ही आइईडी पहुंचाई थी। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में डस्टबिन में आइईडी रखने वाला आतंकी नजर आया है। फिर वह बस स्टैंड की ओर भाग गया था। आशंका है कि वह बस में बैठकर जालंधर से निकल गया। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आतंकी दविंदर ने अमृतसर में आइईडी की डिलीवरी की थी।

राजस्थान

रात्रि विश्राम और रात्रि चौपाल के माध्यम से राजस्थान के सीएम शर्मा जुड़ रहे हैं ग्रामीणों से,आदिवासी जिले प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव से शुरुआत

सीएम शर्मा ग्रामीणों से कर रहे सीधा संवाद

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल में संवाद और गांव में रात्रि विश्राम का सिलसिला प्रारम्भ किया है । गांव में रात्रि विश्राम और रात्रि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संपर्क क़ायम करने की सीएम शर्मा की पहल से एक और जहाँ भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलेगा वहीं राज्य सरकार के कामकाज को लेकर ग्रामीणों से सीधा फीडबैक मिलेगा।

राज्य में पंचायत चुनाव से पहले सीएम के गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा रूबरू होने से भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, वहीं सरकारी मशीनरी भी सुविधाओं के विस्तार और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देगी। इसके तहत सीएम शर्मा बुधवार सर शाम राज्य के आदिवासी प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गाँव में पहुंचे। सीएम ने बंबोरी गांव में रात्रि चौपाल पर ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए गांव और ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्यों को जाना। सीएम ने रात्रि चौपाल में सड़क, पानी, बिजली, ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की ।

ग्राम विकास रथ यात्रा

ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के सभी दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम विकास रथ यात्रा शुरू की है । केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के साथ ही लोगों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के बंबोरी ग्राम में गुरुवार को ग्रामीणों से चर्चा करते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। एएनआइ

विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनेगा दो लेन का नया ब्रिज

जागरण टीम, पटना : बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाने की कवायद अंतिम चरण में है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने इसकी रिपोर्ट मोर्थ (सड़क एवं परिवहन मंत्रालय) के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को भेज दी है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही सेतु के समानांतर नए ट्रस ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। सेतु पर यातायात बहाली को लेकर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने गुरुवार को पटना में बीआरओ तथा आइआइटी, पटना के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। जिसमें बताया गया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक से दूसरे छोर तक ट्रस ब्रिज दो लेन में बनेगा। इस पर पैदल यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था होगी।

पाकिस्तानी गैंगस्टर ने आतंकियों को दिया था पुलिस पर हमले का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

- हैंड ग्रेनेड फेंकने का आनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया था
- शहजाद भट्टी ने पंजाब में भी तैयार किया था स्लीपर सेल

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों दानियाल अशरफ व कृष्णा मिश्रा को पुलिस पर हमले का लक्ष्य दिया था। इसके लिए पाक गैंगस्टर ने संदिग्ध आतंकियों को एक लाख रुपये देने का लालच भी दिया था। दोनों संदिग्ध आतंकियों ने उत्तर प्रदेश सहित पंजाब के कुछ पुलिस थानों व सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों की रेकी भी की थी। एटीएस की टीम ने दोनों आतंकियों से कई अहम जानकारियां उगलवाई हैं। एटीएस ने पिछली 23 अप्रैल को नोएडा से पाकिस्तान समर्थक समीर खान व तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला खान को गिरफ्तार किया था। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब के जरिये दोनों आतंकी पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में आए थे। इन्हें स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर ने इन्हें आनलाइन हैंड ग्रेनेड से हमले का प्रशिक्षण भी दिया था। एटीएस की टीम मंगलवार को दोनों को जांच के लिए नोएडा लेकर गई थी। पूछताछ में दोनों ने एटीएस को बताया था कि उन्होंने कुछ युवकों को अपने साथ जोड़कर स्लीपर सेल तैयार किया था। यह स्लीपर सेल पाकिस्तानी गैंगस्टर व उसके संपर्क वाले आइएसआइ एजेंटों के लिए काम कर रहा था। इनके द्वारा दिए गए आन लाइन लिंक की जांच के बाद एटीएस को कुछ और नाम मिले हैं।

2 महिलाओं सहित महाराष्ट्र में एक महीने के अभियान में 10 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें से अधिकांश मुंबई के हैं। इनके पास से 13.61 करोड़ रुपये मूल्य की मेफेड्रोन जब्त की गई है।

न्यूज गैलरी

डाल्फिन एंबुलेंस ने चार महीनों में आठ डाल्फिनों को बचाया

नई दिल्ली : स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने गुरुवार को बताया कि भारत की पहली डाल्फिन एंबुलेंस ने पिछले चार महीनों में आठ गंगा डाल्फिनों को बचाकर उन्हें वापस नदी में छोड़ा है। इस आपरेशन को विशेष बचाव सुविधा की एक और सफलता बताते हुए एनएमसीजी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में नमामि गंगे मिशन के तहत शुरू की गई डाल्फिन एंबुलेंस लुप्तप्राय गंगा नदी डाल्फिन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरी है। (प्रेट्र)

तरबूज में चूहे के जहर से मुंबई में चार परिजनों की हुई थी मौत

मुंबई : मुंबई में पिछले महीने एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत चूहे मारने की दवा खाने से हुई थी। यह जानकारी फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई है। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि परिवार के सभी सदस्यों ने बिरयानी के बाद तरबूज खाया था, जिसके कारण फूड प्वाइजनिंग हो गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में अब्दुल्ला डोकाड़िया, उनकी पत्नी नसरीन, बेटियों आयशा और जैनब के लिवर, किडनी, स्प्लीन, पेट, पित्त और पेट की चर्बी के नमूनों में जिंक फास्फाइड की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। (प्रेट्र)

चाची-भतीजे के खाते में आए पौने छह अरब रुपये

सीतापुर : यूपी में सीतापुर के बारेपारा गांव की रूपा पत्नी मूलचंद्र और उनके भतीजे गजराज का जियो पेमेंट बैंक में खाता है। रूपा के खाते में तीन अरब 97 करोड़ रुपये तथा गजराज के खाते में एक अरब 75 करोड़ रुपये आ गए हैं। दोनों के खाते फ्रीज हो गए हैं। पीड़ितों ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। रूपा का कहना है कि एक व्यक्ति ने उनकी पेंशन बनवाने के लिए आधार और पैन कार्ड लिया था। इसी के बाद से यह समस्या आई है। (जासं)

10 मई से शुरू होगी दिल्ली-शिमला हवाई सेवा

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद अलायंस एयर बंद पड़ी दिल्ली-शिमला हवाई सेवा को 10 मई से बहाल करने पर तैयार हो गया है। विमान शिमला से धर्मशाला भी जाएगा। 25 सितंबर, 2025 से बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल हो रही है। (राब्यू)

धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों व सियासी संरक्षण दिलाने वालों पर ईडी का शिकंजा

पीएमएलए के तहत जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ और मोहाली में 12 स्थानों पर मारे छापे

21 लाख रुपये घर से बाहर फेंके, ईडी ने किए जब्त

नीलू रंजन • जागरण

नई दिल्ली : मोहाली में किसानों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिलाने वालों बिचौलियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। इस सिलसिले में ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित बिल्डरों और बिचौलियों से जुड़े मोहाली और चंडीगढ़ स्थित 12 ठिकानों पर छापे मारे। छापे के दौरान एक आरोपित ने अपने घर से 21 लाख रुपये से भरे बैग बाहर फेंक दिए, जिसे बाद में ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया।

ईडी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (जीएमएडीए) में सनटेक सिटी और एलटस स्पेस बिल्डटेक पर जमीन मालिकों व घर खरीददारों से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप हैं और उनके विरुद्ध मोहाली में पंजाब पुलिस एफआइआर दर्ज करके जांच कर रही है। इन्हीं एफआइआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग की जांच शुरू की है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले के बावजूद इन बिल्डरों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही थी और उन्हें नितिन गोयल व प्रीतपाल सिंह धींधसा नामक दो बिचौलियों के जरिये पंजाब में राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। ईडी ने छापे में मनी लांड्रिंग से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है। इनमें डिजिटल रिकार्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात शामित हैं। ईडी ने बताया कि सनटेक सिटी के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने इंडियन कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी बनाकर 15 जमीन मालिकों से फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के सहारे 30.5 एकड़ जमीन हड़प ली थी। इसी फर्जीवाड़े के सहारे बाद में जमीन का लैंड यूज भी बदलने की पंजाब से सरकार से अनुमति लेकर बिना सेल डीड के घर खरीदारों से 150 करोड़ रुपये ले लिए। अजय सहगल ने इसी तरह से एक दूसरे प्रोजेक्ट ला कैनेला रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी कांप्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट7 कामर्शियल कांप्लेक्स में भी फर्जी दस्तावेज से लैंड यूज बदलवा लिया। बाद में जीएमएडीए ने इनका लाइसेंस रद कर दिया। इसी तरह एलटस स्पेस बिल्डटेक के मोहिंदर सिंह को जीएमएडीए में सशर्त लैंड यूज बदलने की अनुमति मिली, जो बाद में रद भी हो गई। इसमें भी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और पंजाब पुलिस ने मोहाली में एफआइआर दर्ज की थी।

मोहाली के खरड़ की एक सोसायटी में ईडी की दबिश के दौरान बाहर पड़ा मिला नोटों से भरा बैग। वीडियोग्रैब

नौवीं मंजिल से गिराए बैग हवा में खुले, बिखरीं नोटों की गड्डियां

चंडीगढ़ राज्य ब्यूरो के अनुसार, गुरुवार की सुबह करीब सात बजे पुलिस व ईडी के कुछ अधिकारी वेस्टर्न टावर्स सोसायटी पहुंचे थे। इसके बाद नौवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर-906 में तलाशी अभियान शुरू हुआ। सोसायटी के लोगों ने बताया की यह फ्लैट नीतिन गोयल का है। इसी बीच नौवीं मंजिल से दो बैग नीचे की ओर फेंके गए। बैग हवा में ही खुल गए और 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां परिसर में बिखरने लगीं। लोग इन नोटों को लेकर चर्चा कर रही रहे थे कि पुलिस कर्मचारी और ईडी अधिकारी वहां पहुंचे और दोनों बैग अपने कब्जे में ले लिए।

संजय कपूर के संपत्ति विवाद में पूर्व सीजेआइ चंद्रचूड़ मध्यस्थ नियुक्त

- देश में संभवतः पहली बार पूर्व सीजेआइ नियुक्त हुए मध्यस्थ
- सोना ग्रुप से संबंधित आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा है यह विवाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के बीच संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह विवाद आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसका संबंध सोना ग्रुप की संपत्तियों से है। यह संभवतः देश में पहला मामला है जिसमें किसी पूर्व सीजेआइ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब सभी पक्ष मध्यस्थता से समझौता करने पर सहमत हो गए। शीर्ष अदालत ने विवाद को पारिवारिक मामला बताते हुए सभी पक्षों से अनुरोध किया कि वे कोई भी सार्वजनिक बयान न दें और न ही इंटरनेट मीडिया पर कोई पोस्ट करें।

यह विवाद रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट के गठन और उस पर नियंत्रण से संबंधित है। इसे 80 वर्षीय रानी कपूर ने धोखाधड़ीपूर्ण और अवैध बताते हुए चुनौती दी है। रानी कपूर के पति उद्योगपति सुरिंदर कपूर का 2015 में निधन हो गया था। उन्होंने अपनी सभी संपत्तियां एक वसीयत के जरिये रानी कपूर के नाम कर दी थीं, जिसे 2016 में बांबे हाई कोर्ट ने प्रमाणित किया था।

पूर्व सीजेआइ डीवाई चंद्रचूड़। फाइल

इसके बावजूद सभी संपत्तियां उनकी जानकारी या सहमति के बिना एक ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गईं। रानी कपूर ने दावा किया कि उनके बेटे संजय की मृत्यु के बाद उनकी जानकारी के बिना समूह की प्रमुख कंपनियों पर नियंत्रण कर लिया गया। एक अन्य घटनाक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में संजय की पहली पत्नी व बालीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को अस्थायी संरक्षण देते हुए प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि जब तक विरासत विवाद पर फैसला नहीं हो जाता, वह संजय की संपत्तियों को न तो बेचें और न ही किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनने दें।

यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसहयोग जरूरी : भागवत

- कहा, समाज जाति को याद रखता है, इसलिए राजनेता उसका उठाते हैं लाभ
- आचरण के माध्यम से सामाजिक जीवन में समानता अपनाने का किया आग्रह

मैसूरु, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के लिए जन सहयोग आवश्यक है। जाति आधारित राजनीति तभी समाप्त होगी, जब समाज स्वयं जातिगत पहचान से ऊपर उठेगा।

उन्होंने उक्त बातें राष्ट्रीय विकास की उत्प्रेरक के रूप में सामाजिक समरसता विषय पर व्याख्यान देने के बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहीं।

भागवत ने कहा कि समाज जाति को याद रखता है, इसलिए राजनेता उसका लाभ उठाते हैं। उनका उद्देश्य वोट प्राप्त करना होता है। यदि उन्हें काम के आधार पर वोट नहीं मिलते तो वे जाति के आधार पर वोट हासिल करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक और समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस सरकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक संगठन है। कोई भी कानून तभी सफल हो सकता है, जब उसे जनता का सहयोग मिले। नीति आवश्यक है, लेकिन नीति तभी सफल होगी जब जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा।

मोहन भागवत। फाइल

तेज हवा में फंसा विमान, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लखनऊ में सुरक्षित उतारा

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- दिल्ली से पटना जा रहे विमान के कैप्टन थे रूडी, 181 यात्री थे सवार
- पटना और वाराणसी में खराब मौसम के चलते नहीं हो सकी थी लैंडिंग

दिल्ली से पटना जा रहा इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान बुधवार रात खराब मौसम और टर्बुलेंस (तेज हवा के झोंके) की चपेट में आकर संकट में फंस गया। विमान की कमान संभाल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रोफेशनल पायलट राजीव प्रताप रूडी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। विमान में 181 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे।

इंडिगो का विमान 6ई-6497 बुधवार रात 8:36 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुआ था। पटना पहुंचने से पहले ही विमान तेज हवाओं के झोंके में फंस गया। सुरक्षा के मद्देनजर विमान की लाइटें बंद कर दी गईं। कैप्टन रूडी ने पटना में उतरने का कई बार प्रयास किया, लेकिन मौसम ठीक न होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद विमान को वाराणसी डायवर्ट किया गया, वहां भी स्थिति सामान्य नहीं थी। अंततः पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया और रात 10:49 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। पायलट की वर्दी में राजीव प्रताप रूडी केबिन से बाहर आए। उन्होंने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, 'अब आप ताली बजा सकते हैं, आप सुरक्षित लैंड कर चुके हैं।' राजीव प्रताप रूडी चार बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वह इस समय बिहार की सारण सीट से लोकसभा सदस्य हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट पर स्टैंड में खड़ा इंडिगो एयरलाइन का विमान।

अविमुक्तेश्वरानंद मामले की सुनवाई से जस्टिस अग्रवाल अलग

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर सिविल अवमानना याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ने कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति से अनुमति लेकर प्रकरण नए सिरे से दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए। अवमानना अर्जी में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। दोनों के खिलाफ नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। याची के अनुसार विपक्षी जानबूझकर हाई कोर्ट की उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो पाक्सो केस में अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई थीं।

बिहार के सहरसा जिले के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन में मिला सांप का बच्चा, 250 बच्चे बीमार

जागरण संवाददाता, सहरसा

115 बच्चों में फूड प्वायजनिंग के लक्षण, अभिभावकों का हंगामा

बिहार में सहरसा जिले के मध्य विद्यालय बलुआहा में गुरुवार को एनजीओ द्वारा बच्चों के लिए भेजे गए मध्याह्न भोजन में सांप का बच्चा मिला। इसके बाद विद्यालय के लगभग 250 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंचे अभिभावक विद्यालय में हंगामा करने लगे। डीएम दीपेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने 115 बच्चों में फूड प्वाइजनिंग की पुष्टि की है। कुछ बच्चे डर और घबराहट के कारण भी बीमार हुए हैं। खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए एफएसएल और औषधि निरीक्षक की टीम को भेजा गया है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनुपमा कुमारी ने बताया कि रसोइया ने कक्षा एक से पांच तक के लगभग 250 छात्रों को भोजन परोसा। भोजन के कुछ समय बाद, कई छात्र बेहोश होकर गिर पड़े और अन्य छात्रों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। उसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिहार के सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन के बाद बीमार हुए बच्चों को महिषी स्थित सीएचसी में भर्ती कराया गया। (इंसेट में) भोजन में दिख रहा सांप का बच्चा। जागरण >>

मथुरा में डकैती डालने वाले दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर

जासं, मथुरा : व्यवसायी के घर डकैती डालने वाले गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस ने गुरुवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए 50-50 हजार के इनामी बदमाश अलवर और भरतपुर (राजस्थान) के रहने वाले थे। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में स्वाट टीम प्रभारी और हेड कांस्टेबल के हाथ में गोली लगी है।

बदमाशों के कब्जे से 90 हजार रुपये नकद और डेढ़ लाख रुपये के आभूषण बरामद हुए हैं। दोनों बदमाशों ने यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में लूट की वारदातें की थी। मारे गए राजेंद्र उर्फ पप्पू पर 11 और धर्मवीर उर्फ लंबू पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। राजेंद्र गिरोह का सरगना था। बरामद अपाचे बाइक डकैती के पैसों से खरीदी गई थी। सूचना दिए जाने के बाद भी दोनों के स्वजन नहीं पहुंचे हैं।

दुष्कर्म का आरोपित एक लाख का इनामी भाजपा कार्यकर्ता मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार हुआ

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

- फतेहपुर में 24 अप्रैल को साथियों संग मिलकर किया था युवती से दुष्कर्म
- बलवा, धमकी देने व दुष्कर्म के हैं पांच केस, रासुका लगाने की भी तैयारी

मंगेतर के सामने बाग में युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित एक लाख रुपये के इनामी भाजपा कार्यकर्ता बबलू सिंह को पुलिस टीम ने बुधवार रात तीन बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपित के पास से 315 बोर का तमंचा, चार खोखा, एक कारतूस, 1600 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आरोपित पर बलवा, धमकी देने व दुष्कर्म के हैं पांच केस दर्ज हैं। पुलिस अब गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

यहां एक गांव में रहने वाली युवती अपने मंगेतर के साथ 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे बाग में बैठी थी। तभी आरोपित युवराज सिंह, ललित सिंगरौर व भाजपा कार्यकर्ता बबलू सिंह सिंगरौर ने वहां पहुंचकर मंगेतर को बंधक बना पीटा था और 2500 रुपये यूपीआइ के जरिये ट्रांसफर करा लिए थे। इसके बाद युवती से दुष्कर्म कर धमकाया था। 26 अप्रैल को युवराज सिंह व ललित सिंह को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर रमेश कुमार पटेल व दारोगा अनीश कुमार सिंह निलंबित किए गए थे। फरार बबलू पर एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, फिर आइजी ने इनाम राशि बढ़ा कर 50 हजार और एडीजी ने एक लाख रुपये कर दी थी। बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बबलू अपने एक परिचित के यहां शरण लेने पहुंच रहा है। बरकतपुर-भादर गांव के बीच पुलिस को बबलू आता दिखा। पुलिस टीम ने रुकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस मुठभेड़ में गोली से घायल इनामी बबलू सिंह को अस्पताल ले जाती पुलिस। स्रोत पुलिस

हमारे विज्ञानियों ने मीथेन गैस उत्सर्जन पर दुनिया के दावे को दिखाया आईना

जागरण विशेष सेटेलाइट तकनीक व जमीनी आंकड़ों से साबित किया कि देश में मीथेन उत्सर्जन वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से काफी कम

अंजली राय • नईदुनिया

भोपाल: जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी के लिए जिम्मेदार मानी जाने वाली मीथेन गैस को लेकर लंबे समय से भारत पर बड़े उत्सर्जक होने का ठप्पा लगाया जाता रहा है। धान की खेती, पशुपालन आदि को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइसर), भोपाल के विज्ञानियों ने शोध से साबित किया है कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के दावे गलत हैं। सेटेलाइट तकनीक, वैज्ञानिक माडल और जमीनी आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययन में सामने आया है कि देश में मीथेन उत्सर्जन वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से काफी कम है। देश की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने वाला यह शोध भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु नीति तय करने में भी मददगार साबित होगा। यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल एटमास्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में प्रकाशित हुआ है। शोध करने वालों में डा. धन्यलेक्ष्मी के पिल्लै के अलावा शोधार्थी जितिन सुकुमारन, तारा अन्ना मात्यु, अद्वैत जे. विनोद शामिल रहे।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्थाएं भारत को तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक बताती हैं। उनका दावा है कि भारत प्रतिवर्ष 31 टेराग्राम (31 मिलियन टन) मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। आइसर के विज्ञानियों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि भारत का सालाना मीथेन उत्सर्जन केवल 21.9 से 24.9 टेराग्राम के बीच है। विज्ञानियों ने मीथेन उत्सर्जन का आकलन करने के लिए यूरोपीय सेटेलाइट सेंटिनेल-5पी के ट्रोपोमी सेंसर से वातावरण में मौजूद मीथेन की मात्रा मापी। इसके बाद डब्ल्यूआरएफ-जीएचसी माडल से यह समझा गया कि गैस वातावरण में कैसे फैलती है। अध्ययन में पाया गया कि भारत का सालाना मीथेन उत्सर्जन वैश्विक अनुमानों से 24 प्रतिशत तक कम है। सबसे ज्यादा उत्सर्जन पशुपालन, अपशिष्ट जल और धान की खेती से होता है। इंडो-गंगेटिक क्षेत्र मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख हाट स्पाट पाया गया।

इस अध्ययन में उत्सर्जन के हाटस्पाट क्षेत्रों की पहचान भी संभव है। शोध से जुड़े विज्ञानियों ने बताया कि बेहतर निगरानी प्रणाली से उत्सर्जन के स्त्रोतों को अधिक सटीकता से ट्रैक किया जा सकता है। इससे कृषि, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार के जरिये मीथेन गैस को कम करने की रणनीति तैयार की जा सकती है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

जितिन सुकुमारन, डा. धन्यलेक्ष्मी के पिल्लै, तारा अन्ना और विनोद (बाएं से दाएं) • पिल्लै

निगरानी प्रणाली से उत्सर्जन नियंत्रण में मदद

विज्ञानियों का मानना है कि बेहतर निगरानी प्रणाली से मीथेन गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मीथेन एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो कार्बन डाइआक्साइड की तुलना में कम समय में कई गुना अधिक गर्मी पैदा करती है। वैश्विक तापवृद्धि में इसका योगदान सबसे अधिक माना जाता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन का सटीक मापन और निगरानी बेहद जरूरी मानी जाती है। विज्ञानियों का कहना है कि यदि मीथेन गैस उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम किया जाए, तो अल्पकालिक रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा किया जा सकता है।

> मीथेन एक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस है। प्रभावी जलवायु क्रियान्वयन के लिए इसका सटीक मापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्षित जलवायु नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सहायता पहुंचाई जा सकती है।
> **डा. धन्यलेक्ष्मी के पिल्लै**, विज्ञानी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान विभाग, आइसर

ये भी हैं समाधान

- बेहतर प्रबंधन और सेटेलाइट निगरानी
- कृषि तकनीकों में सुधार
- कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना
- स्वच्छ ऊर्जा और गैस लीक पर नियंत्रण

यह इसलिए है खतरनाक

- मीथेन शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
- कार्बन डाइआक्साइड से कई गुना अधिक प्रभावी होती है।
- कम समय में अधिक गर्मी पैदा करती।
- जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ाने में इस गैस की भूमिका प्रभावी रहती है।

मीथेन फ्लक्स का सटीक अनुमान बहुत जरूरी

मीथेन गैस को नियंत्रित करने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस क्षेत्र से कितनी मीथेन निकल रही है। इसी दर को मीथेन फ्लक्स कहा जाता है। यदि फ्लक्स का सटीक अनुमान नहीं होगा तो बड़े उत्सर्जन स्रोतों की पहचान और नियंत्रण की प्रभावी योजना बनाना मुश्किल होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक और सरकारें मीथेन फ्लक्स के सही आकलन को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सके।

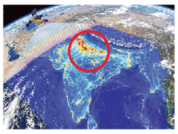
सेटेलाइट इमेज में मीथेन की उपस्थिति

भोजशाला : मस्जिद पक्ष के तर्कों को महाधिवक्ता ने किया खारिज

- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रखा शासन का पक्ष
- स्वतंत्रता पूर्व की अधिसूचना जस का तस नहीं कर सकते लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: धार की ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने शासन का पक्ष रखते हुए मस्जिद पक्ष के तर्कों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद पक्ष ने धार दरबार द्वारा वर्ष 1935 में जारी अधिसूचना को लेकर कोर्ट में अधूरी और भ्रामक जानकारी दी है। मस्जिद पक्ष ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि धार दरबार ने किन परिस्थितियों में भोजशाला को मस्जिद बताया था। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि संविधान की कसौटी पर जांचे बगैर किसी राज (धार) दरबार द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व जारी किसी अधिसूचना को जस का तस कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

महाधिवक्ता ने याद दिलाया कि अपीलकर्ता काजी जकुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन ने तर्क प्रस्तुत किया था कि धार दरबार ने वर्ष 1935 में अधिसूचना जारी कर भोजशाला को मस्जिद बताया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के जिस परिपत्र के आधार पर धार दरबार की अधिसूचना को वैध ठहराया जा रहा है, वह एक अप्रैल 1937 के बाद जारी अधिसूचनाओं पर लागू होता है, इसके पूर्व पर नहीं।

महाधिवक्ता ने गुरुवार को दोहराया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सर्वे में भोजशाला में जो मूर्तियां मिली हैं, वे बता रही हैं कि भोजशाला मंदिर ही है। शोभा मेनन ने धार दरबार के आदेश की अधूरी कहानी बताई। सच्चाई यह है कि भोजशाला पहले सरस्वती मंदिर और शिक्षा का केंद्र थी।

गुरुवार को जैन समाज की ओर से प्रस्तुत याचिका पर भी सुनवाई हुई। एडवोकेट दिनेश पी. राजभर ने कोर्ट से सर्वे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुरुवार को एडवोकेट राजभर के तर्क पूरे हो गए।

दैनिक जागरण

धैर्य की नैया ही संकट में बेड़ा पार लगाती है

बंगाल के खोए गौरव को बहाल करने की चुनौती

कंचन गुप्ता

बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ हैं और उसे सही करने के लिए भाजपा की नई सरकार को द्रुत गति के साथ अविलंब प्रयास करने होंगे

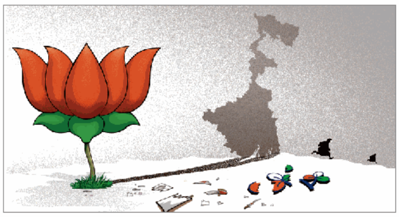

अवधेश राजपूत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसे याद रखने के कई कारण हैं। जिस भाजपा को एक समय राज्य में सत्ता की होड़ से बिल्कुल बाहर समझा जाता था, उसने न केवल ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि उस तृणमूल कांग्रेस को ऐसी करारी हार का सामना भी करना पड़ा, जो स्वयं को अपराजेय समझने लगी थी। हार को गरिमा के साथ स्वीकार करने के बजाय ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर और केंद्रीय सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती जैसे निर्वाचन आयोग के असाधारण कदमों का हवाला देकर भाजपा की जीत को अवैध ठहराने पर तुले हैं, लेकिन उनके इस रुख-रवैये को जनता के किसी कोने से न तो कोई समर्थन मिलता दिख रहा है और न ही उनके प्रति कोई सहानुभूति दिखती है।

दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो उसकी जीत के इस पैमाने की कल्पना भी कठिन है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जनता के असंतोष को पहले ही भांप लिया था और वह इस आक्रोश को व्यवस्थित तरीके से अपने पक्ष में भुनाने के लिए जुट गया। ममता बनर्जी की नाक के नीचे ही वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी और वे उसे अनदेखा करती रहीं। उनका कोई सहयोगी भी उन्हें यह समझा नहीं पाया। इसका ही परिणाम रहा कि भाजपा के विजयी रथ ने तृणमूल कांग्रेस के किले को कुचल दिया। इसके पीछे भाजपा के पक्ष में हिंदुओं के ध्रुवीकरण को एक वजह बताया जा रहा है, जिसके समक्ष ममता बनर्जी की मुस्लिम गोलबंदी बौनी साबित हुई। यह व्याख्या सतही तौर पर ही सही है, क्योंकि इसमें वे महत्वपूर्ण पहलू अनदेखे ही रह जाएंगे, जो बंगाल के राजनीतिक पटल पर तूफान की थाह लेने के लिए आवश्यक है। भाजपा के इस तूफान ने उन घेराबंदियों को ध्वस्त करने का काम किया, जिनकी व्यूह रचना उस पर बाहरी पार्टी का ठप्पा लगाते हुए उसे सुनियोजित तरीके से हमेशा के लिए राज्य की सत्ता से दूर रखने के लिए ही रची गई थी।

कुछ लोग यह दलील भी दे सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा और आपराधिक तत्वों का विरोध भी केवल सड़कों पर भीड़ को लामबंद करने तक ही सीमित होकर रह गया है। हालांकि बंगाल के नतीजे ऐसी धारणाओं को धता बताते हैं। बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके तृणमूल शासन के विरुद्ध अपने मतदान से आक्रोश प्रकट किया। लोगों के जेहन में ममता के बेहद करीबी मंत्री के यहां से जब्त हुई भारी नकदी की तस्वीरें ताजा रही हैं। उन हजारों शिक्षकों के साथ ही असंख्य बंगाली मध्यवर्ग की पीड़ा भी चुनाव परिणाम में अभिव्यक्त हुई, जो तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से छले गए थे, क्योंकि सरकार के कर्ताधर्ताओं ने रिश्वत लेकर उनके अवसरों पर डाका डालने का काम किया। इसी तरह असंवेदनशील या कहें उदासीन प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की मिलीभगत वाले आपराधिक रवैये को भी मतदाताओं ने सबक सिखाकर दंडित किया है। 'बंगाल में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं' जैसे दावों का तब कोई मूल्य-महत्व नहीं रह जाता, जब वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत दिखती हो। बंगाल इस मामले में कुख्यात होता गया कि अव्वल तो यहां पुलिस पीड़ित की शिकायत ही दर्ज नहीं करती और यदि किसी तरह वह दर्ज भी हो जाए तो यहां दोष सिद्धि एवं अपराध के लिए दंडित करने की दर सबसे कम है। जहां दूसरे राज्यों में बाल विवाह का चलन घटा है, वहीं बंगाल में यह बढ़ने पर है। इसी राज्य में महिलाओं को सरेआम कोड़े मारे जाते रहे और राजनीतिक नेतृत्व उस पर मौन साधे रहा और यह चुप्पी सीधे तौर पर वोटों के गणित से जुड़ी रही।

यदि ममता को लगता था कि उनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की चरम सांप्रदायिक राजनीति की कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं होगी तो शायद वे उतनी चतुर नेता नहीं हैं, जितना उन्हें माना जाता है। उनके शासन में ही बंगाल में उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। राज्य में हिंदुओं को दरकिनार करते हुए उनके राज में कट्टर इस्लामिक तत्वों और जिहादियों को मिलते संरक्षण से उपजी पीड़ा ने एक आक्रोश का जन्म दिया। बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम से इस आक्रोश की आग में और घी पड़ा, जहां हिंदुओं को चिह्नित कर प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश की भारत के साथ सटी सीमा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जमात-ए-इस्लामी की जीत के साथ बंगाली हिंदू घर की देहरी पर दस्तक दे रहे खतरे को लेकर जागृत हो गए। यह एक तरह से ममता बनर्जी और उनके सांप्रदायिक शासन के विरुद्ध हिंदुओं को लामबंद करने वाला निर्णायक पड़ाव बना।

बंगाल के नतीजों ने यह भी दर्शाया कि मुफ्तखोरी वाली योजनाएं भी एक सीमा तक ही उपयोगी होती हैं। आज बंगाल में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आजीविका के लिए पलायन ही विकल्प रह गया और घर में रह गए केवल उनके आश्रित। एक समय वह भी था जब बंगाल से विज्ञानी, तकनीशियन, कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, शिक्षक, डाक्टर और वकील जैसे प्रतिष्ठित बंगाली राज्य से बाहर जाते थे और जहां जाते, वहां के सम्मानित प्रबुद्ध वर्ग का हिस्सा बन जाते। अब बंगाल के पास ऐसी प्रतिभाओं का अकाल है। इसके बजाय वह घरेलू सहायिकाओं के लिए जाना जाने लगा है, जिन्हें लेकर चुनावों के दौरान तमाम मीम भी छाए रहे, क्योंकि मतदान के लिए उनमें से अधिकांश अपने राज्य गई थीं। यह मेरे जैसे तमाम बंगालियों के लिए बहुत अपमानजक और पीड़ादायक होने के साथ ही निराश करने वाला अनुभव भी रहा। बंगाल में बहुत कुछ गलत हुआ है और उसे सही करने के लिए भाजपा को द्रुत गति के साथ अविलंब प्रयास करने होंगे। एक 'नए बंगाल' का निर्माण और 'दूसरे पुनर्जागरण' का आविर्भाव संभव है। बंगाल के पास इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के पर्याप्त साधन और सामर्थ्य मौजूद हैं। कमी रही तो केवल नेतृत्व की। अब भाजपा को बंगाल के खोए उस गौरव को बहाल करना होगा, जिस पर कभी बंगाल और बंगाली दोनों गर्व करते थे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार हैं)
response@jagran.com

चुनाव बाद हिंसा का दुष्चक्र

चुनाव बाद हिंसा का दुष्चक्र पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान तो हिंसा से बच गया, लेकिन चुनाव बाद हिंसा से नहीं बच पा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी जिस तरह हिंसा जारी है, उससे पिछले विधानसभा चुनावों के बाद की भयावह हिंसा का स्मरण हो आया। तब ममता की सत्ता में वापसी हुई थी और उनके नेता-कार्यकर्ता निरंकुश होकर विरोधी दलों के समर्थकों पर टूट पड़े थे। उस समय ममता ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है। इस बार वे इस खोखले तर्क की आड़ में छिपती दिख रही हैं कि चूंकि जीत भाजपा को मिली है, इसलिए हिंसा रोकने की जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन यह ध्यान रहे कि अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बंगाल में हिंसा इसलिए हो रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ता हार की खीझ भाजपा समर्थकों पर निकाल रहे हैं। ममता ने यह कहकर एक तरह से अपने समर्थकों को उकसाया ही है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है और इसलिए वे त्यागपत्र नहीं देंगी। स्पष्ट है कि वे चुनाव बाद हिंसा भड़काने के आरोपों से बच नहीं सकतीं। स्पष्ट यह भी है कि तृणमूल समर्थक आतंकित करने वाली हिंसा का जो परिचय दे रहे हैं, वह उस हिंसक राजनीतिक संस्कृति की देन है, जिसे ममता ने पिछले 15 वर्षों में उसी तरह संरक्षित किया, जैसे एक समय वाम दलों ने किया था।

बंगाल में आतंक मचा रहे हिंसक तत्व कितने अधिक दुस्साहसी हैं, इसका खौफनाक प्रमाण है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की गोली मार कर हत्या। सुवेंदु का यह आरोप सच हो तो हैरानी नहीं कि रथ की टारगेट किलिंग इसलिए हुई कि उन्होंने ममता को चुनावी मात दी। इस हत्या के साथ भाजपा समर्थकों को निशाना बनाने वाली अन्य हिंसक घटनाओं के पीछे तृणमूल समर्थकों का हाथ होने की भरी-पूरी आशंका इसलिए है, क्योंकि अतीत में भी उन्होंने ऐसी हिंसा की है और सब जानते हैं कि ममता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। यह अच्छा हुआ कि इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ीं ममता को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जब तक भाजपा सत्ता नहीं संभालती, तब तक चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को यह देखना होगा कि मौजूदा हिंसा पर कैसे लगाम लगे। वैसे तो चुनाव बाद 60 दिनों तक केंद्रीय बलों को बनाए रखने का फैसला लिया गया था, पर शायद उनकी तैनाती और बढ़ानी पड़े। जो भी हो, भाजपा को यह समझ आ जाना चाहिए कि उसके सामने अन्य अनेक चुनौतियों के साथ कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे को ठीक करने की गंभीर चुनौती है। उसे इस चुनौती का सामना करना ही होगा, क्योंकि इससे ही राज्य को पटरी पर लाया जा सकता है।

दहेज-मुक्त हरियाणा

हरियाणा सरकार ने दहेज प्रथा के खिलाफ अब औपचारिकता से आगे बढ़कर निर्णायक कार्रवाई की ठोस रूपरेखा तैयार कर दी है। यह पहल केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक भागीदारी के समन्वय से इसे जनआंदोलन का रूप देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिला उपायुक्तों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अभियान का असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। सरकार की रणनीति दहेज को सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि दंडनीय अपराध के रूप में स्थापित करने की है। इसी दिशा में सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को 'दहेज निषेध अधिकारी' बनाना एक अहम कदम है। इससे जवाबदेही सीधे स्थानीय प्रशासन तक पहुंचेगी और पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी। यह व्यवस्था शिकायत निपटान, निगरानी और जागरूकता तीनों स्तरों पर काम करेगी। सरकार ने पारदर्शिता पर भी जोर दिया है। दहेज निषेध अधिकारियों के नाम, संपर्क नंबर और ईमेल सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ित बिना झिझक सीधे संपर्क कर सकें। इससे शिकायतों के दबने की संभावना कम होगी। दहेज देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है। यह परिवारों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। हर साल इसकी वजह से बहुत सी बेटियों का जीवन बर्बाद होता है। इस समस्या का उन्मूलन किया जाना समय की मांग है।

> प्रशासनिक नियुक्तियां और राज्यव्यापी जागरूकता अभियान से कुरीति पर प्रहार की तैयारी, मिलेगी त्वरित राहत

आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार

डा. अर्जुन सुब्रमण्यम

पाकिस्तान के विरुद्ध आपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया हैं

रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखने और पश्चिम एशिया के 'न युद्ध-न शांति' के दलदल में फंसे होने के बावजूद हाल के समय के दूसरे संघर्षों के मुकाबले आपरेशन सिंदूर को एक मानक अभियान के तौर पर देखना महत्वपूर्ण है। इस आपरेशन की सबसे खास बात थी-सैन्य ताकत का तीव्र और नियंत्रित तरीके से निर्णायक इस्तेमाल, ताकि संघर्ष-विस्तार में रहते हुए ऐसे रणनीतिक नतीजे हासिल किए जा सकें, जो सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। इसका उद्देश्य था, पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकी नेटवर्क के गढ़ पर सीधा हमला करना और अगर पाकिस्तानी सेना जवाब देती है, तो उसे भारी नुकसान पहुंचाना। यह एक जिम्मेदार ताकत द्वारा राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के बार-बार दोहराए जाने वाले कृत्यों को सजा देने के लिए चलाया गया एक सटीक और संयमित प्रतिरोधी अभियान था।

हालांकि भारत ने 2019 में बालाकोट में आतंकरोधी अभियान में आक्रामक हवाई शक्ति के इस्तेमाल का प्रयोग किया था, पर इस बार जैश और लश्कर के मुख्यालयों पर हमले की तत्परता ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जोखिम उठाने की नई प्रवृत्ति और संघर्ष बढ़ाने की इच्छाशक्ति को उजागर किया। इसमें यह सोच स्पष्ट थी कि एक व्यापक संघर्ष भारत के हित में नहीं है, भले ही पाकिस्तान को और अधिक नुकसान पहुंचाने का सैन्य प्रलोभन मौजूद हो। भारत ने आपरेशन सिंदूर के दौरान कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं होने दिया और सैन्य श्रेष्ठता के बावजूद पाकिस्तान के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चार दिनों के भीतर ही संघर्ष समाप्त करने से जो सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई, उसने पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौरान भारत की आर्थिक सहनीयता में योगदान दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका के 27 अरब डालर से भी ज्यादा खप चुके हैं, तनाव अभी भी कायम है।

आपरेशन सिंदूर की तैयारी के चरण में केंद्रीकृत नियंत्रण का एक स्पष्ट माडल देखने को मिला। इसके पहले स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षामंत्री थे, जबकि दूसरे पर सीडीएस और तीनों सैन्यप्रमुख। सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट और ठोस रणनीतिक परिणाम बताए गए थे। इससे उन्हें व्यावहारिक कार्ययोजना बनाने में मदद मिली।

आपरेशन सिंदूर में ध्वस्त जैश का आतंकी अड्डा। फाइल

भले ही हजारों सालों में युद्ध के स्वरूप में कई बदलाव आए हों, लेकिन कौटिल्य, सुन जू, क्लाजविट्ज, लिडेल हार्ट जैसे रणनीतिकारों द्वारा बताए गए युद्ध के अधिकांश मूल सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया। भारत ऐसा इसलिए कर पाया, क्योंकि इसने समय की कसौटी पर खरे उतरे युद्ध के कुछ सिद्धांतों और संकट के समय फैसले लेने के तरीकों का पालन किया। वायु सेना के इस्तेमाल का फैसला एक साहसी कदम था, जो आज के संघर्षों के बदलते स्वरूप को दिखाता है और जिस पर बारीकी से विश्लेषण करने की जरूरत है। चीन से मिली पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने और उन्हें जाम करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में मौजूद लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने अपने हमले का दायरा और बढ़ाया तथा नूर खान, सियालकोट, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी, जैकोबाबाद एयरबेस जैसे 11 प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को पहुंची क्षति 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई अड्डों को पहुंचाए गए कुल नुकसान से कहीं ज्यादा था।

आपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा प्रणाली की परिपक्वता को भी साबित कर दिया, जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन-केंद्रित रणनीति का मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि वायुसेना को भविष्य में अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ किसी भी सीमित संघर्ष की स्थिति में अपने प्लेटफार्म, हथियारों और प्रणालियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए तेज गति से सीखने की आवश्यकता होगी। भविष्य के युद्ध-क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों से मुकाबले के लिए एकीकरण और तालमेल की जरूरत होगी। वर्तमान में चल रहे सुधारों और ढांचागत पहलों पर शायद फिर से विचार करना पड़े, ताकि एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा सके, जो आपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए अनुभवों पर आधारित हो। हालांकि दुनिया भर में चल रहे संघर्षों से कई रणनीतिक सबक मिलते हैं, लेकिन भारत को दूसरी जगहों से युद्ध-लड़ाई के माडल अपने रणनीतिक और परिचालन वातावरण पर लागू करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। मिसाइल और ड्रोन पर ज्यादा जोर देने के समर्थकों को फिर से सोचना चाहिए। भारत के पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर जैसा हवाई माहौल है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, वहां सिर्फ बहुक्षेत्रीय परिचालन ही सफल होंगे।

(लेखक सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विचार और भाग्य

मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनने लगता है। जब हम किसी विचार पर गहरा विश्वास कर लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है और उसी दिशा में हमारे व्यवहार, निर्णय तथा परिस्थितियां आकार लेने लगती हैं। यही कारण है कि हम जिन विचारों को बार-बार दोहराते हैं, वे धीरे-धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। विचार कर्म का आधार बनते हैं, कर्म से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र अंततः हमारे भाग्य को दिशा देता है।

सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोजने की प्रेरणा देता है, जबकि नकारात्मक सोच उसे भय, भ्रम और निराशा में उलझा देता है। एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं-एक उसे चुनौती मानकर आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा उसे विपत्ति समझकर निष्क्रिय हो जाता है। हमारे विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, वे हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के माध्यम से एक प्रकार का परिवेश भी निर्मित करते हैं। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों की दिशा पर सतत निगरानी रखें। सकारात्मक विचारों को बार-बार दोहराना और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाना आत्मविश्वास को मजबूत करता है।

इसके लिए कुछ सरल उपाय अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं-नियमित ध्यान और साधना, सकारात्मक संगति, प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा प्रतिदिन जीवन की छोटी-छोटी उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। साथ ही स्वयं से सकारात्मक संवाद करना और नकारात्मक विचारों को चुनौती देना भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों के स्वामी बनें, क्योंकि वही हमारे भविष्य के बीज हैं।

एसएन दुबे 'स्नेही'

अमंगल करती हर्ष फायरिंग

रामबाबू सोनी

> रसूख और रुतबा दिखाने के लिए शादी-विवाह में की गई हर्ष फायरिंग पूरे माहौल को चीख-पुकार और करुण रुदन में बदल देती हैं

शगुन की मंगल बेलाएं जब मातम में बदल जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जिस परिवार में मंगल शहनाइयां बज रही हों, मिठाइयों और विभिन्न पकवानों का आनंद लिया जा रहा हो तथा परिजन गीत-संगीत और नृत्य के साथ अपनी खुशियां मना रहे हों, वहां अपना रसूख और रुतबा दिखाने के लिए की गई हर्ष फायरिंग पूरे वातावरण को चीख-पुकार और करुण रुदन में बदल देती है। हाल में वैवाहिक अवसर पर की गई हर्ष फायरिंग में बिहार और उत्तर प्रदेश में लोगों की मृत्यु की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस प्रकार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

ऐसी हृदयविदारक घटनाएं यह सोचने पर विवश करती हैं कि यह कैसी मानसिकता है, जिसमें अपनी 'प्रतिष्ठा' और 'शक्ति' के प्रदर्शन के लिए हथियारों का दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत किसी निर्दोष को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसके शिकार केवल समारोह में शामिल लोग ही नहीं होते, बल्कि राह चलते वे लोग भी होते हैं, जिनका इस हर्षोल्लास से कोई संबंध नहीं होता। राहगीर और दुकानदार भी भय के माहौल में रहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक, जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी थोड़ी-बहुत होती रहती हैं। यहां निकलने वाली बारातों में दो-तीन लोगों को हाथों में रायफल या तमंचा लेकर नृत्य करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। थोड़े-थोड़े अंतराल पर वे फायरिंग भी करते रहते हैं। इसे मानवीय भूल या लापरवाही नहीं माना जा सकता, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता को प्रकट करता है, जिसमें अपनी हैसियत और प्रभाव को समाज के सामने प्रदर्शित करने का अनुचित प्रयास किया जाता है। कुछ समाजों और परिवारों में वैवाहिक अवसरों पर हर्ष फायरिंग को पारिवारिक परंपरा मानकर निभाया जाता है। निश्चित ही यह एक गैर-जिम्मेदाराना प्रथा है। इस प्रकार के कृत्य पूरी तरह गैर-कानूनी हैं तथा भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय हैं, जिनके लिए सजा का प्रविधान भी है।

प्रशासन के लिए यह संभव नहीं कि वह प्रत्येक विवाह समारोह पर नजर रख सके, किंतु दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। कुछ क्षणों का रोमांच किसी परिवार का चिराग बुझा सकता है। माता-पिता अपने बच्चों को खो देते हैं या बच्चे अपने माता-पिता को। ड्रोन और पेट्रोलिंग के माध्यम से ऐसे आयोजनों की निगरानी के साथ-साथ आयोजकों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लोगों को स्वयं भी जागरूक होना होगा और अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। ऐसी प्रथा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आंतरिक सुरक्षा तंत्र भी हो मजबूत

'सामरिक तैयारी को देनी होगी और धार' शीर्षक से लिखे आलेख में हर्ष वी. पंत ने आपरेशन सिंदूर की सटीक विवेचना की है। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी और सैन्य ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवाद के प्रति कठोर और निर्णायक नीति अपनाने को तैयार है। आतंकवाद का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि देश अपनी सामरिक क्षमताओं और रणनीतिक तैयारी को और अधिक मजबूत बनाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका त्वरित और प्रभावी उपयोग किया जा सके। तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के लिए सरकार पहले ही चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था लागू कर चुकी है। अब तकनीकी आधुनिकीकरण के साथ-साथ संगठनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा, ताकि सामरिक बदलाव स्थायी रूप से स्थापित हो सकें। हालांकि बाहरी सुरक्षा के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी उतना ही मजबूत बनाना आवश्यक है। पहलगाम हमले जैसी घटनाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि गुप्तचर तंत्र, निगरानी व्यवस्था और आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सरकार को देश के भीतर सक्रिय आतंकी तत्वों, विदेशी फंडिंग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे नेटवर्क पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। आतंकवाद को आर्थिक सहायता पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी समय की मांग है। यदि आंतरिक सुरक्षा तंत्र को 24 घंटे सक्रिय, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए, तो भविष्य में आतंकी साजिशों और निर्दोष लोगों की हत्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर शांति, स्थिरता और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने से भी जुड़ी हुई है।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव, उप्र

एक वोट की ताकत

लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जन-जन की भागीदारी का जीवंत प्रतीक है। इसमें हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित। हाल में तमिलनाडु की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट का परिणाम इस सत्य को फिर से प्रमाणित करता है, जहां मात्र एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम तय हुआ। टीवीके के उम्मीदवार सीनिवसा सेतुपति आर ने डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केआर पेरियाकरुप्पन को केवल एक वोट से हराया। यह घटना केवल एक चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गहराई और उसकी शक्ति का सशक्त संदेश है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि एक वोट कितना निर्णायक हो सकता है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में विश्वास मत के दौरान केवल एक वोट से गिर गई थी। उस एक वोट ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। यह हमारे भविष्य, हमारे समाज और हमारे देश की दिशा तय करता है। एक वोट से सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, नीतियां बनती हैं और बदलती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर नागरिक अपने वोट की कीमत समझे और मतदान के दिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आज आवश्यकता है जागरूकता की, जिम्मेदारी की और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की। हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभा में नहीं, बल्कि मतदान केंद्र पर खड़े उस आम नागरिक के हाथ में होती है, जो अपने एक वोट से इतिहास लिख सकता है। अतः अगली बार जब मतदान का अवसर आए, तो इसे हल्के में न लें। यह केवल एक बटन दबाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने अधिकार, अपने भविष्य और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर है। याद रखिए आपका एक वोट, बहुत कुछ बदल सकता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

4.5 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 75 किलोमीटर लंबा है बरगी बांध का जलभराव क्षेत्र, जो एक विशाल झील का निर्माण करता है। यह बांध नर्मदा नदी पर बना है, जो लगभग 268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

आजकल

लालजी जायसवाल
लोकनीति विश्लेषक

पर्यटन स्थलों पर सुनिश्चित हो सुरक्षा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध में हुई क्रूज दुर्घटना ने एक बार फिर देश की पर्यटन नीति और सुरक्षा व्यवस्था के बीच गहरे असंतुलन को उजागर कर दिया है। गर्मियों के इस मौसम में जब जलाशयों, बांधों और घाटों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ती है, तब ऐसी घटनाएं केवल दुर्घटनाएं नहीं रह जातीं, बल्कि प्रशासनिक तैयारी और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न बनकर उभरती हैं। विडंबना यह है कि हर बार हादसे के बाद ही चेतना जागती है, मानो व्यवस्था का स्वभाव ही प्रतिक्रिया तक सीमित हो गया हो

जबलपुर के बरगी बांध में कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गई कई लोगों की जिंदगी। फाइल

जबलपुर के बरगी बांध में हुई दुर्घटना के बाद से अनेक विसंगतियां सामने आ रही हैं। यह भी कि क्रूज का एक इंजन ठीक से काम नहीं करता था और लगभग दो माह पहले ही इस बारे में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया गया था। लिहाजा यह बहुत ही चिंताजनक मामला है। वस्तुतः देश के लगभग हर राज्य में ऐसे अनेक पर्यटन स्थल हैं, जहां जोखिम पहले से चिन्हित है, तेज जल प्रवाह, गहराई का अंदाजा न होना, फिसलन भरे किनारे, या अनियंत्रित नौकायन। इसके बावजूद सुरक्षा प्रबंधन अक्सर प्रतीकात्मक ही रहता है। चेतावनी बोर्ड लगा देना, सीमित संख्या में स्थानीय कर्मियों की तैनाती या अस्थायी निगरानी- क्या इतने भर से पर्यटकों की जान सुरक्षित मानी जा सकती है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारें निवेश और प्रचार कर रही हैं, लेकिन उसी अनुपात में सुरक्षा ढांचे का विस्तार नहीं दिखता।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि जब इन स्थलों की संवेदनशीलता पहले से ज्ञात है, तो फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों की पूर्व तैनाती क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती? क्या यह मान लिया गया है कि इनकी जरूरत केवल तब होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए? यदि ऐसा है, तो यह दृष्टिकोण न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अस्वीकार्य है। आधुनिक आपदा प्रबंधन का मूल सिद्धांत 'पूर्व तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण' है, न कि हादसे के बाद राहत और बचाव।

दरअसल, समस्या केवल संसाधनों की कमी की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की है। पर्यटन को राजस्व और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत मानते हुए उसका आक्रामक विस्तार किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को उसी अनुपात में अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं जोड़ा गया। नतीजा यह है कि स्थानीय प्रशासन पर अचानक बढ़ती भीड़ का दबाव पड़ता है और वह सीमित साधनों के साथ हालात संभालने की कोशिश करता है। कई बार निजी संचालकों और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव भी स्थिति को और जटिल बना देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज का पर्यटक पहले की तुलना में अधिक जोखिम उठाने को तैयार है, जैसे एडवेंचर, रील्स और इंटरनेट मीडिया के आकर्षण में लोग खतरनाक जगहों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में केवल 'सावधानी बरतें' जैसे संदेश पर्याप्त नहीं हैं।

बरगी बांध जैसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम हर बार किसी अनहोनी के बाद ही सबक लेंगे, या फिर एक दीर्घकालिक और व्यवस्थित नीति की ओर बढ़ेंगे? क्या यह संभव नहीं कि संवेदनशील पर्यटन स्थलों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार कर वहां स्थायी सुरक्षा प्रोटोकाल लागू किए जाएं? क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ऐसा ढांचा विकसित नहीं कर सकतीं, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती मौसमी आधार पर सुनिश्चित हो? सच तो यह है कि किसी भी पर्यटन स्थल की वास्तविक सफलता उसकी लोकप्रियता से नहीं, बल्कि वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा से मापी जानी चाहिए। यदि पर्यटक स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो पर्यटन का विकास टिकाऊ नहीं रह सकता।

नो लाइफ जैकेट नो राइड : जल पर्यटन में लाइफ जैकेट की भूमिका अनिवार्य है, किंतु दुर्भाग्यवश या तो जैकेट की संख्या पर्याप्त नहीं थी या पर्यटकों ने उन्हें पहनना आवश्यक नहीं समझा। सुरक्षा नियमों की यह शिथिलता ही अक्सर जीवन पर भारी पड़ती है। चिंताजनक यह कि क्रूज स्टाफ उस समय लाइफ जैकेट निकाल रहा था, जब बोट डूबने लगा। कई यात्री बिना जैकेट के थे। जबकि इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 के अनुसार, हर यात्री को यात्रा शुरू होने से पहले लाइफ जैकेट देना और पहनाना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि क्रूज में 29 टिकट जारी किए गए थे, जबकि उस पर 40 से अधिक पर्यटक सवार थे। इसके अलावा, मौसम विभाग द्वारा आरेंज अलर्ट जारी किया गया था और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी की चेतावनी भी दी गई थी, फिर भी क्रूज को पानी में उतारा गया।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा ढांचा खड़ा करना समय की मांग है। प्रत्येक क्रूज स्टेशन पर रियल-टाइम मौसम मानिटरिंग सिस्टम स्थापित होना चाहिए, ताकि हवा की गति या दृश्यता कम होने की स्थिति में परिचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। 'नो लाइफ जैकेट, नो राइड' के सिद्धांत को लागू करना होगा और जलयानों की भार क्षमता की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसे कदम आवश्यक हैं। साथ ही, बांध स्थलों पर स्थानीय गोताखोरों और आपदा प्रबंधन दल की एक समर्पित इकाई आधुनिक उपकरणों के साथ सदैव तैनात रहनी चाहिए, जो किसी भी आपात स्थिति में 'गोल्डन आवर' के भीतर सहायता पहुंचा सके। क्रूज संचालकों और चालक दल को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और जलयानों का समय-समय पर सुरक्षा आडिट अनिवार्य रूप से हो। बरगी की लहरों ने जो घाव दिए हैं, वे लंबे समय तक नहीं भरेंगे। पर्यटन और मनोरंजन का उत्साह तभी सार्थक है जब वह सुरक्षा की गारंटी के साथ हो।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग पांच से छह प्रतिशत के बीच है। यह क्षेत्र लगभग 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार, भारत 2024 में 231.6 अरब डालर से अधिक के योगदान के साथ दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम पर्यटकों की सुरक्षा को विशेष स्थान दें। केंद्र-राज्य-स्थानीय समन्वय में कमियां सदैव चिंता का कारण रही हैं। उल्लेखनीय है कि पर्यटन राज्य का विषय है, लेकिन यह केंद्रीय मंत्रालयों, संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और शहरी स्थानीय निकायों पर काफी हद तक निर्भर करता है, जिससे समन्वय में विफलताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दिनों केरल के वर्कला में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित रिसार्ट में लगी आग के बाद अपर्याप्त सुरक्षा, बुनियादी अवसंरचना और नगरपालिका अधिकारियों, वन/पर्यावरण नियामकों एवं आपातकालीन सेवाओं के बीच अस्पष्ट जिम्मेदारी ने बचाव कार्य को बुरी तरह बाधित किया। लिहाजा तमाम खामियों को चिन्हित करके उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

इंटरनेट मीडिया और जोखिम भरा व्यवहार

डिजिटल दौर में पर्यटन का अर्थ केवल घूमना-फिरना नहीं रह गया है, बल्कि वह दिखावे और वर्चुअल पहचान का माध्यम भी बन चुका है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स- खासतौर पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने युवाओं के बीच 'परफेक्ट फोटो' और 'वायरल रील' की होड़ को इस हद तक बढ़ा दिया है कि कई बार वे अपनी सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर देते हैं। खतरनाक चट्टानों के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेना, गहरे पानी के पास जाकर वीडियो बनाना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना। चिंता की बात यह है कि यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत जोखिम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई बार दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। एक व्यक्ति की लापरवाही बचाव अभियान को जन्म देती है, जिसमें प्रशासनिक संसाधन और समय दोनों खर्च होते हैं। इस व्यवहार पर न तो पर्याप्त सामाजिक नियंत्रण दिखता है और न ही प्रशासनिक सख्ती।

सवाल यह है कि क्या केवल प्रशासन को दोष देकर समस्या का समाधान हो सकता है? स्पष्ट है कि नहीं। जब तक पर्यटक स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती। जरूरी है कि संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सख्त निगरानी और दंडात्मक प्रविधान भी लागू किए जाएं। साथ ही, इंटरनेट मीडिया कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे जोखिम भरे कंटेंट को बढ़ावा देने के बजाय जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। हिमाचल प्रदेश में मनाली और उत्तराखंड में ऋषिकेश-हरिद्वार जैसे लोकप्रिय स्थलों पर तेज बहाव वाली नदियों, ऊंचे पहाड़ों और संकरे रास्तों पर रील बनाने के दौरान हादसों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कई मामलों में सेल्फी या वीडियो शूट करते समय संतुलन बिगड़ने से लोग बहाव में बह गए या गहरी खाई में गिरने की नौबत आ गई।

रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का ट्रेंड भी बेहद खतरनाक रूप में उभरा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रेन के पास खड़े होकर वीडियो बनाने के प्रयासों में गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते भारतीय रेल निरंतर चेतावनी भी जारी करती है। इसके बावजूद वायरल होने की चाह कई लोगों पर भारी पड़ रही है। ये घटनाएं बताती हैं कि समस्या केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति बन चुकी है, जहां कुछ सेकेंड की लोकप्रियता के लिए लोग स्थायी जोखिम उठाने को तैयार हैं। यही वह स्थिति है जो बरगी बांध जैसी घटनाओं को और गंभीर बना देती है, क्योंकि जब लापरवाही और संवेदनशील स्थल एक साथ आते हैं, तो परिणाम दुखद ही होता है।

(लालजी जायसवाल)

खरी-खरी

आम हुए तो अचार बना दिए जाओगे

सूर्यदीप कुशवाहा

आम केवल फल नहीं, बल्कि उस आम आदमी की श्रेणी में आना है जिसकी पीठ पर लटक लोग खास बनते हैं। लोकतंत्र से लेकर दफ्तरों तक, आम होना किसी गाली से कम नहीं है। जैसे ही गर्मी आती है, बाजार में आमों की बाढ़ आ जाती है। जब संख्या बढ़ती है, तो कीमत गिरती है। यही नियम जनता पर भी लागू होता है। जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं, जब आपका अपना कोई अलग सोच या पहचान नहीं होती, तो समाज आपको दो कौड़ी का माल समझता है। चालाक बंदे को हमेशा ऐसे ही आमों की तलाश रहती है, जिन्हें काटकर, छीलकर और गुठली निकालकर मर्तबान में ठूंसा जा सके।

अचार बनाना दरअसल एक व्यवस्थित वध है। पहले आपको आम आदमी के नाम पर चुना जाता है, फिर आप पर टैक्स का नमक छिड़का जाता है, महंगाई की मिर्च डाली जाती है और नियमों की हल्दी में लपेटकर बंद कर दिया जाता है।

जो फल दुर्लभ होता है, वह चांदी की तश्तरी में सजकर किसी वातानुकूलित कमरे की मेज पर रखा जाता है। उसे काटने से पहले सौ बार सोचा जाता है। लेकिन आम के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती।

राजनीति के बाजार में तो आम होने का स्वाद ही निराला है। नेता चुनाव के समय इसी आम आदमी के गुण गाते हैं, लेकिन सत्ता की मेज पर बैठते ही वे उसी आम का अचार निकालकर परांठे के साथ मजे से खाते हैं। यदि आप अपनी मौलिकता को बचाकर नहीं रखेंगे, यदि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाए रखने के बजाय हां में हां मिलाने वाले आम बनेंगे, तो यकीन मानिए, समाज की कैंची तैयार खड़ी है। आपको काटकर आपकी पहचान का ऐसा अचार डाला जाएगा कि आने वाली नस्लें भी उसी स्वाद में खुद को भुला देंगी। आज के दौर में जो आम नहीं होता, उसका अचार नहीं बनता। लोग उसे चखने से डरते हैं। वरना मर्तबान का ढक्कन खुला है और समाज नमक हाथ में लिए आपकी बारी का इंतजार कर रहा है। सच में... आम हुए तो अचार बना दिए जाओगे!

पोस्ट

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इन्कार करके ममता बनर्जी एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही हैं, जो खेल हारने पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है।

मार्कण्डेय काटजू@mkatju

बंगाल में पराजित मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के निजी सहायक की सरेआम सुनियोजित हत्या कर दी जाती है। अगर इससे भी शेष भारत बंगाल में कायम शासन के ढांचे को नहीं समझ पाता तो फिर उसे कैसे समझाया जाए।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

ईश्वर करे कि द्रमुक और अन्नाद्रमुक में जुगलबंदी वाली बात सही न हो, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत बड़ी दगाबाजी और अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा होगी। द्रविड़ राजनीति करने वाले दोनों दलों को जनता ने नकार दिया है। अगर द्रमुक पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करेगी तो वह विश्वासघात ही होगा।

एस. गुरुमूर्ति@sgurumurthy

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कांग्रेस का द्रमुक से किनारा करना राजनीतिक अवसरवाद है?

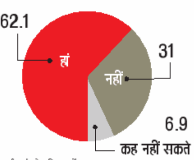

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या तमिलनाडु के राज्यपाल ने जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को ठुकरा कर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

राहुल का दल बन गया अब तो 'मुस्लिम लीग',
बालू में सिर गाड़ कर रहो हांकते डींग।
रहो हांकते डींग मिलेगी ना यूं सत्ता,
ले बस मुस्लिम वोट फोड़िए अपना मत्था।
हारें बारम्बार पार्टी की बत्ती गुल,
किंतु समझने हेतु न राजी दिखते राहुल!

-ओम प्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

कलह से त्रस्त कांग्रेस

केशव महतो कमलेश। फाइल

राधाकृष्ण किशोर। फाइल

झारखंड कांग्रेस एक बार फिर अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को लेकर चर्चा में है। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश कमेटी के गठन से जहां संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद थी, वहीं इसके उलट पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ दिल्ली तक तगड़ी लाबिंग की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

दरअसल, नई प्रदेश कमेटी के गठन के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर सरीखे कद्दावर नेता ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। संगठन में पदों के बंटवारे को लेकर नाराजगी धीरे-धीरे सार्वजनिक होती जा रही है। कई नेताओं का मानना है कि कमेटी गठन में अनुभव और जनाधार की जगह व्यक्तिगत नजदीकियों और गुटीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई। यही कारण है कि पार्टी के भीतर असंतोष का स्वर अब दबा हुआ नहीं रह गया है।

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को संगठन की कमान ऐसे समय मिली थी, जब कांग्रेस झारखंड में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी अंदर से ही कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के भीतर एक वर्ग का आरोप है कि प्रदेश नेतृत्व संवाद स्थापित करने में विफल रहा है। जिला और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। कई पुराने नेता स्वयं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली दरबार तक शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है।

झारखंड कांग्रेस में यह संकट अचानक नहीं पैदा हुआ है। राज्य गठन के बाद से ही पार्टी गुटों में बंटी रही है। कभी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी नेताओं का प्रभाव बढ़ा तो कभी स्थानीय क्षत्रपों ने संगठन पर पकड़ मजबूत की। लेकिन वर्तमान संकट इसलिए गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस सत्ता गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर पार्टी निरंतर कमजोर नजर आ रही है। सरकार में शामिल होने के बावजूद कांग्रेस अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने में संघर्ष कर रही है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस के मंत्री जरूर हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा। ऐसे में संगठनात्मक असंतोष और नेतृत्व विवाद कांग्रेस के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है। पार्टी के भीतर यह धारणा भी मजबूत हो रही है कि यदि समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो कई नेता अलग रास्ता चुन सकते हैं। राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड कांग्रेस टूट की ओर बढ़ रही है? फिलहाल खुलकर बगावत जैसी स्थिति नहीं दिखती, लेकिन परिस्थितियां संकेत जरूर दे रही हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है।

हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अक्सर ऐसे संकटों को बातचीत और समन्वय से नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन झारखंड में समस्या केवल व्यक्तियों की नहीं, बल्कि संगठनात्मक संरचना की भी है। यदि असंतुष्ट नेताओं को साधने में देरी हुई तो यह संकट और गहरा सकता है।

झारखंड कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर विपक्षी दल भी नजर बनाए हुए हैं। विशेषकर भाजपा इस स्थिति को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस को नेतृत्वविहीन और दिशाहीन पार्टी बताती रही है। यदि कांग्रेस के भीतर असंतोष और बढ़ता है तो विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय अन्य दल भी कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं पर नजर रखे हुए हैं। झारखंड की राजनीति में दल-बदल कोई नई बात नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर अस्थिरता बढ़ने पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस आलाकमान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि केंद्रीय नेतृत्व समय रहते हस्तक्षेप कर असंतुष्ट नेताओं से संवाद स्थापित करता है और संगठन में संतुलन बनाने की कोशिश करता है तो हालात संभल सकते हैं। लेकिन यदि असंतोष को केवल सामान्य नाराजगी मानकर नजरअंदाज किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने भी यह बड़ी परीक्षा है। उन्हें केवल संगठन चलाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि विभिन्न गुटों को साथ लेकर चलने की राजनीतिक क्षमता भी दिखानी होगी। झारखंड में कांग्रेस तभी मजबूत हो सकती है, जब संगठनात्मक एकता और राजनीतिक स्पष्टता दोनों साथ चलें। कांग्रेस में चल रही खींचतान का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक पार्टी की रणनीति संगठन की मजबूती पर निर्भर करती है। यदि पार्टी अंदरूनी संघर्ष में उलझी रही तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिलेगा।

मंथन

आदित्य कुमार
शिक्षा मामलों के जानकार

जेनरेटिव एआइ और शिक्षा

तमाम क्षेत्रों में एआइ का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता व पहुंच में विषमता गंभीर समस्या है, इसलिए जेनरेटिव एआइ को संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है

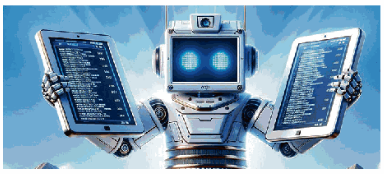

जटिल समीकरणों को मैनुअल तरीके से हल करना बहुत ही मुश्किल माना जाता रहा है। बहुत सारे छात्रों के लिए यह बहुत ही कठिन टापिक होता है। परंतु जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) इस कार्य में सक्षम साबित हो सकता है। वस्तुतः यह हमारे सीखने के तरीके को बदल देगा, लेकिन इससे एक बड़ी चिंता भी जताई जा रही है कि आने वाली पीढ़ियों में यह संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बन सकता है। हालांकि एक बात निश्चित है कि शिक्षा, जो समाजीकरण और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक है, वह अपरिहार्य बनी रहेगी।

वस्तुतः डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार ने मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। हाल के वर्षों में जेनरेटिव एआइ का उदय इस परिवर्तन को एक नए स्तर पर ले गया है। अब ऐसी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं जो न केवल जटिल समीकरण हल कर सकती हैं, बल्कि शोध-पत्र, लेख, रिपोर्ट और रचनात्मक सामग्री भी तैयार कर सकती हैं। इस परिघटना ने शिक्षा जगत में एक गहन बहस को जन्म दिया है कि क्या यह तकनीक सीखने की प्रक्रिया को सशक्त बनाएगी या भविष्य की पीढ़ियों की बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर देगी?

जेनरेटिव एआइ के समर्थक इसे शिक्षा में क्रांति का वाहक मानते हैं। उनका तर्क है कि यह तकनीक शिक्षा को अधिक सुलभ बना सकती है। एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों के छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराना लंबे समय से एक चुनौती रहा है, जिसे एआइ काफी हद तक हल कर सकता है। छात्र अपनी गति के हिसाब से सीख सकते हैं, कठिन विषयों को सरल भाषा में समझ सकते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और संसाधनों की कमी है, वहां एआइ आधारित प्लेटफार्म शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में असमानता एक गंभीर समस्या है, जेनरेटिव एआइ एक संभावित समाधान के रूप में उभरता है। यह न केवल डिजिटल विभाजन को कम कर सकता है, बल्कि बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकता है।

हालांकि, इस तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ कई गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह छात्रों के स्वतंत्र सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता को कमजोर न कर दे। जब हर प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकेंड में उपलब्ध हो, तो गहराई से सोचने, तर्क करने और समस्या को स्वयं हल करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। यदि यह प्रक्रिया बाधित होती है, तो दीर्घकालिक रूप से इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक ईमानदारी का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एआइ द्वारा तैयार किए गए उत्तरों और असाइनमेंट्स के कारण नकल और मौलिकता से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह शिक्षकों के लिए भी एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि पारंपरिक मूल्यांकन पद्धतियां अब पर्याप्त नहीं रह गई हैं। ऐसे में शिक्षा प्रणाली को अपनी मूल्यांकन पद्धतियों में बदलाव लाना होगा, ताकि छात्रों की वास्तविक समझ और कौशल का आकलन किया जा सके।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा का सामाजिक और मानवीय पक्ष। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे सामाजिक सहभागिता, संवाद, सहयोग और नैतिक मूल्यों के विकास के भी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। शिक्षक केवल जानकारी देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और मूल्य-निर्माता भी होते हैं। जेनरेटिव एआइ इन मानवीय पहलुओं को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और नीतियां तैयार करना आवश्यक है, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और इसके लाभों को अधिकतम किया जा सके।

सरकार, शिक्षण संस्थानों और नीति-निर्माताओं को मिलकर एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी होगी, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सके। शिक्षकों को भी नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे एआइ को अपने शिक्षण का हिस्सा बना सकें, न कि उससे प्रतिस्पर्धा करें। अंततः जेनरेटिव एआइ शिक्षा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली परिवर्तनकारी साधन है, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि इसे विवेकपूर्ण व संतुलित तरीके से अपनाया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और सुलभ बना सकता है। वहीं, यदि इसका अनियंत्रित उपयोग किया गया, तो यह शिक्षा के मूल उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है।

चालू वित्त वर्ष में 5-5.5% तक बढ़ेगी बिजली की मांग

नई दिल्ली: रेटिंग एजेंसी इक्रा ने गुरुवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में बिजली की मांग 5-5.5 प्रतिशत तक बढ़ेगी। इसको औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में जारी तेजी का सहारा मिलेगा। बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिजली की मांग सिर्फ एक प्रतिशत बढ़ी थी। इक्रा के वाइस प्रेसिडेंट अंकित जैन ने कहा कि भारत में थर्मल पावर क्षेत्र में निवेश पर फिर से जोर दिया जा रहा है। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। (प्रेट्र)

ऊर्जा की उच्च कीमतों और अनिश्चित मौसम के पैटर्न जैसे दोहरे झटके को देखते हुए आरबीआइ जून में होने वाली बैठक में ब्याज दर को स्थिर रख सकता है।
- प्रांजुल भंडारी, भारत में एचएसबीसी की प्रमुख

सेंसेक्स	77,844.52	▼ 114
निफ्टी	24,326.65	▼ 4.30
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,56,000	▲ ₹ 600
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,61,500	▲ ₹7,000
डालर	₹ 94.22	▼ ₹ 0.27
क्रूड प्रति बैरल	$ 99	

एक नजर में

बीती तिमाही में एमआरएफ का शुद्ध लाभ 38% बढ़ा

नई दिल्ली: टायर निर्माता एमआरएफ ने गुरुवार को बताया कि बीती तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के दौरान उसका शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 702.25 करोड़ रुपये रहा है। जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के दौरान कंपनी को 510.5 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बीती तिमाही में कंपनी का राजस्व 14 प्रतिशत बढ़कर 7,908 करोड़ रुपये रहा है। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 2,426.1 करोड़ रुपये रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1,873.29 करोड़ रुपये था। कंपनी बोर्ड ने 229 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की सिफारिश की है। (प्रेट्र)

15.95 लाख करोड़ रुपये हुआ एनपीएस का एयूएम

नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 15.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। गुरुवार को जारी डाटा के अनुसार, एनपीएस के तहत अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का एयूएम 51,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। एनपीएस से अब तक 2.17 करोड़ और एपीवाई से 8.96 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अप्रैल 2026 तक कर्मचारी पेंशन स्कीम में योगदान देने वालों की संख्या 7.98 करोड़ हो गई है। (आइएएनएस)

कोटक बैंक को दो बैंकों में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

नई दिल्ली: कोटक महिंद्रा बैंक ने गुरुवार को बताया कि उसे आरबीआइ से एयू स्माल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। एयू स्माल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक ने भी रेग्युलेटरी फाइलिंग के जरिये इसकी पुष्टि की है। एयू स्माल फाइनेंस बैंक ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों जिन्हें सामूहिक रूप से 'कोटक महिंद्रा ग्रुप' के जरिये यह हिस्सेदारी खरीदेगा। इससे कोटक महिंद्रा बैंक को वित्तीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। (प्रेट्र)

नई क्रेडिट योजना पर रहेगी सरकार की नजर

ईसीएलजीएस 5.0 को कैबिनेट से मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय ने प्रमुख बैंकों के साथ किया विमर्श

- बैंकों को बिना देरी योजना लागू करने का दिया गया निर्देश
- एयरलाइंस के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना काल में छोटे-मझोले उद्यमियों (एमएसएमई) को मजबूती देने के लिए सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की थी। अब पश्चिम एशिया के संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को फिर से सहारा देने के लिए हाल ही में मंजूर ईसीएलजीएस 5.0 को लागू करने को लेकर सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती।

योजना को कैबिनेट की मंजूरी के तुरंत बाद गुरुवार वित्त मंत्रालय ने देश के प्रमुख बैंकों और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आइबीए) के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में स्कीम के ड्राफ्ट गाइडलाइंस, पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसयू) और प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस बैंक बैठक में शामिल थे। बैंकों को कहा गया है कि इस स्कीम को बिना देरी के लागू किया जाए।

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न हर तरह की चुनौतियों से एमएसएमई सेक्टर को बचाने के लिए कोरोना जैसी तेजी से इस स्कीम को लागू किया जाए। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ईसीएलजीएस 5.0 को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस फैसले का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव से एमएसएमई और गैर-एमएसएमई क्षेत्रों पर पड़ रहे असर को रोकना है। स्कीम के तहत एयरलाइंस के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष राशि संकट से प्रभावित एमएसएमई और अन्य व्यवसायों को अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में मदद के रूप में दी जाएगी। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने बताया है कि बैंक ईसीएलजीएस 5.0 के तहत 70-80 हजार करोड़ रुपये तक का ऋण विस्तार करने को तैयार है। बैंक के पास पात्र ग्राहकों की सूची तैयार है। कुल मिलाकर एसबीआइ के ग्राहकों को 70,000-80,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी। एसबीआइ चेयरमैन ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का असर व्यापक है और कई उद्योगों पर इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है। हालांकि, सभी को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंकों को उम्मीद है कि अगले 8-10 दिनों में बोर्ड मंजूरी और जन समर्थ पोर्टल के जरिए डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इस योजना से 1.1 करोड़ एमएसएमई खाते होंगे लाभान्वित: एसबीआइ रिपोर्ट

एसबीआइ की रिसर्च रिपोर्ट में उक्त स्कीम की उपयोगिता को और मजबूती से रेखांकित करते हुए कहा गया है कि सही समय पर इसे लागू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि ईसीएलजीएस 5.0 के परिणामों के बारे में अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कोरोना काल के अनुभव से यह स्कीम विश्वसनीय, प्रोएक्टिव और पर्याप्त साबित होगी। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.1 करोड़ एमएसएमई खाते (कुल एमएसएमई पोर्टफोलियो का 45%) इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। प्रति खाते औसतन 2 से 2.3 लाख रुपये अतिरिक्त क्रेडिट प्रवाह की उम्मीद है। रिपोर्ट याद दिलाती है कि ईसीएलजीएस 1.0 से 4.0 ने कम से कम 13.5 लाख एमएसएमई खातों को बचाया था। इससे एमएसएमई क्रेडिट का करीब 14 प्रतिशत हिस्सा एनपीए बनने से बचा था। यदि ये इकाइयां एनपीए होतीं तो 1.5 करोड़ कामगार बेरोजगार हो जाते।

चार प्रतिशत महंगे होंगे डाबर के उत्पाद, पैकेट का आकार भी घटेगा

विश्लेषकों से बातचीत के दौरान एफएमसीजी कंपनी ने की घोषणा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कंपनी ने लिया फैसला

नई दिल्ली, आइएएनएस: घरेलू एफएमसीजी कंपनी अपने कुछ उत्पादों के मूल्य में चार प्रतिशत तक की बढ़ोतरी और छोटे पैकेट के आकार में कटौती की तैयारी कर रही है। कंपनी को पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी की तिमाही आय की घोषणा के बाद विश्लेषकों से बात करते हुए डाबर के वैश्विक सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा कि भारत में उनके कारोबार की ज्यादातर श्रेणियों में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से कंपनी ने कीमतों में सोच-समझकर बढ़ोतरी करके इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है।

मल्होत्रा ने कहा कि होम, पर्सनल और हेल्थकेयर को छोड़कर हम अपने सभी पोर्टफोलियो में 10 प्रतिशत की महंगाई का असर देख रहे हैं। इस असर को कम करने के लिए हमने अपने कारोबार के अलग-अलग हिस्सों में कीमतों में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का एलान किया है। इसके अलावा कंपनी 10-20 रुपये कीमत वाले अपने उत्पादों के पैकेट के आकार को छोटा करने जा रही है, ताकि महंगाई को प्रबंधित किया जा सके। कंपनी ने पिछले वर्ष जीएसटी दरों में कटौती के बाद पैकेट का आकार बढ़ाया था। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान डाबर का लाभ 15.75 प्रतिशत बढ़कर 362 करोड़ रुपये रहा है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस जैसी अन्य कंपनियां भी बढ़ती लागत को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती कर रही हैं और कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं।

ग्राहक शिकायतों के गलत निपटान पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना

दूरसंचार नियामक ट्राई ने पेश किया नया प्रस्ताव, शिकायत खारिज करने पर कंपनी पर एक हजार रुपये का दंड का प्रविधान

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार आपरेटरों के लिए ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक नए तंत्र का प्रस्ताव रखा है। इसमें शिकायतों के गलत निपटान पर दूरसंचार कंपनियों पर प्रति तिमाही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्तावित दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियमन, 2026 में कहा गया है कि सेवा प्रदाताओं के वेब पोर्टल, एप्स और चैटबाट्स पर स्पष्ट शिकायत पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही, पंजीकृत शिकायतों पर उठाए गए कदमों की नियमित अपडेट उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी। मसौदा पत्र में कहा गया है कि यदि शिकायत आडिट के दौरान किसी शिकायत के गलत तरीके से खारिज करने या असंतोषजनक तरीके से निपटान पाया जाता है तो सेवा प्रदाता को प्रत्येक गलत खारिज या निपटान के लिए 1,000 रुपये का वित्तीय दंड देना होगा।

यदि सेवा प्रदाता की ओर से अपील को गलत तरीके से खारिज या निपटान किया जाता है तो प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना 5,000 रुपये होगा। सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाला अधिकतम वित्तीय दंड प्रति तिमाही 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। सभी दूरसंचार आपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर 'उपभोक्ता कोना' स्थापित करना होगा, जिसमें शिकायत केंद्र, अपीलीय प्राधिकरण और तिमाही प्रदर्शन रिपोर्ट से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ट्राई ने इस प्रस्ताव पर पांच जून तक टिप्पणियां मांगी हैं।

पेटीएम की एनबीएफसी लाइसेंस लेने की कोई योजना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: पेटीएम ब्रांड नाम से डिजिटल प्लेटफार्म संचालित करने वाली फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट मधुर देवड़ा ने गुरुवार को कहा कि हम अभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लाइसेंस लेने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है।

तिमाही नतीजों की जानकारी देते हुए कंपनी के प्रेसिडेंट मधुर देवड़ा ने कहा कि हमारा पेमेंट्स बाजार बहुत बड़ा है और यह बढ़ रहा है। इसके साथ हमारी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। कम पैठ होने का मतलब है कि शार्ट से मीडियम टर्म में हमारे लिए मौके पहले से ही बहुत-बहुत ज्यादा है।

आरबीआइ ने पिछले महीने ही नियमों का पालन न करने के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जारी बैंकिंग लाइसेंस रद किया है। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान पेटीएम को 183 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है।

सोने के सुरक्षित निवेश का दर्जा दबाव में: मार्गन स्टेनली

- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौरान दूसरे परिसंपत्ति वर्ग के मुकाबले सोने ने किया खराब प्रदर्शन
- विशेषज्ञों ने कहा- सोने की सुरक्षित निवेश की अपील वास्तविक ब्याज दर की उम्मीदों से धीमी पड़ी

नई दिल्ली, एएनआइ: अब तक सोने में निवेश को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन ईरान में चल रहे संघर्ष के दौरान इस कीमती धातु की कीमतों में गिरावट ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। वित्तीय सेवाएं प्रदाता मार्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौरान दूसरे परिसंपत्ति वर्ग के मुकाबले सोने ने खराब प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से लगातार सालाना बेहतर रिटर्न देने के बाद ईरान संघर्ष के दौरान सोना लड़खड़ा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमती धातु के मूल्य में हालिया कमजोरी भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बजाय मौद्रिक नीति और ब्याज दरों पर निवेशकों के फोकस में बदलाव को दिखाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के पहले महीने यानी मार्च में सोना 14.50 प्रतिशत गिरा। इस दौरान वैश्विक शेयर बाजार अमेरिकी ट्रेजरी इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह कम रही। अप्रैल में शेयर बाजार में सुधार के बावजूद यह कीमती धातु ईरान संघर्ष के पहले स्तर से लगभग 10 प्रतिशत नीचे बनी हुई है। मार्गन स्टेनली रिसर्च की मेटल्स एंड माइनिंग कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट एमी गावर ने कहा, ''मौद्रिक नीति के प्रति सोने की संवेदनशीलता ने कीमत को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।'' उन्होंने कहा कि सोने की सुरक्षित निवेश की अपील वास्तविक ब्याज दर की उम्मीदों से धीमी पड़ गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल की बढ़ती कीमतों और संघर्ष से जुड़ी सप्लाई में रुकावटों ने अमेरिका में कम ब्याज दर की आशंका को खत्म किया है। इससे सोने में निवेश कम आकर्षक हो गया। विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) द्वारा कम खरीदारी से भी इस पर अतिरिक्त दबाव आया। ऐसा कहा जाता है कि तुर्किये के केंद्रीय बैंक ने फरवरी और मार्च के बीच 52 टन सोना बेचा, जबकि ईटीएफ ने पहले से जमा लगभग 90 टन होल्डिंग को लिक्विडेट कर दिया।

हालांकि, मार्गन स्टेनली को उम्मीद है कि साल के आखिर तक सोने में तेजी आएगी, क्योंकि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक और ईटीएफ फिर से खरीदारी शुरू करेंगे और बाजार भविष्य में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती को तय करना शुरू कर देंगे।

लगातार चौथे दिन बढ़ी चांदी, सोना भी चढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: औद्योगिक मांग में सुधार के चलते गुरुवार को चांदी की कीमतें लगातार चौथे दिन बढ़ीं और यह 7,000 रुपये मजबूत होकर 2,61,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में सफेद धातु में 3,500 रुपये की तेजी दर्ज की गई थी। उधर, डालर में गिरावट और अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद स्थानीय बाजार में सोना 600 रुपये बढ़कर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। बुधवार को इस कीमती धातु में 2,900 रुपये का उछाल दर्ज किया गया था।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

फल निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी सरकार: शिवराज

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- फ्रूट होराइजन 2026 में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री, फल निर्यात में भारत को नंबर वन बनाएंगे

शिवराज चौहान।

उप्र में बनेगा निर्यात क्लस्टर, सीआइएसएच लखनऊ में बनाया जाएगा आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर

भारत में बेहतर गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन करने और उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार कराने जा रही है। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के रहमानखेड़ा स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (सीआइएसएच) में आयोजित फ्रूट होराइजन-2026 में कहा कि टास्क फोर्स में आइसीएआर के वैज्ञानिक संस्थान, निर्यातक, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) आदि एजेंसियां शामिल होंगी। टास्क फोर्स बीज से फल उत्पादन, उसकी गुणवत्ता से लेकर निर्यात और उसमें आने वाली समस्याओं के समाधान को समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करेगी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर पट्टी की जलवायु फल के लिए उपयोगी है। हम आम और केले के निर्यात को पांच प्रतिशत और अंगूर के निर्यात को 15 प्रतिशत बढ़ाएंगे। निर्यात के लिहाज से सभी फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने को आइसीएआर की विशेष टीम बनाई गई है। आम की सेल्फ लाइफ कुछ दिन बढ़ाने में सफलता मिली है। निर्यातकों की समुद्री मार्ग प्रोटोकाल बढ़ाने की मांग पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उप्र प्रीमियम फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा हब बनेगा।

एफटीए से भारतीय फलों के लिए खुला विदेश का रास्ता

उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में दूसरे देशों से जो मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, उनसे भारत के फलों के लिए रास्ते खुल गए हैं। अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया आम मांग रहा है। जापान, न्यूजीलैंड आदि में भी फल निर्यात हो सकते हैं। विदेश में अंगूर, अनार, केला आदि की भी मांग है।

राजस्थान में कृषि मंत्री ने खुद पकड़ा पीएम फसल बीमा में फर्जीवाड़ा

जासं, जयपुर : राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के फर्जी किसानों के नाम पर करीब नौ करोड़ रुपये बैंक खातों में स्थानांतरित करने की तैयारी थी। दरअसल, फर्जीवाड़े की आशंका पर मीणा गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले में स्थित एसबीआइ की ब्रांच में पहुंचे। वहां पहुंचने पर मीणा को जानकारी मिली कि बैंक से 162 फर्जी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए नौ करोड़ स्वीकृत हुए हैं। यह रकम इन किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की तैयारी थी। इस पर मीणा ने बैंक कर्मियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीणा ने कहा कि फर्जीवाड़े के पक्के सुबूत मिले हैं।

गरीबों के खाते खुलवा कर 3200 करोड़ रुपये के लेनदेन का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर

- कोलकाता में साढ़ू के घर छिपा कारोबारी महफूज अली मामला निपटाने के लिए आया था कानपुर

आरोपित महफूज अली। जागरण

विभिन्न बैंकों में 68 खाते खुलवाकर लगभग 3200 करोड़ के लेनदेन का आरोपित टेनरी व स्क्रैप कारोबारी महफूज अली उर्फ पप्पू छूरी वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

12वीं पास महफूज मजदूरों, पेंटरों, सब्जी-फल विक्रेताओं को बीमा कराने और अन्य लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड समेत कागजात लेकर फर्जी फर्म बनाकर खाता खुलवाता था। 16 फरवरी को शहर में एक लूट की घटना के बाद महफूज का नाम सामने आया था। तबसे वह बेटे फैज के साथ एक करोड़ रुपये लेकर कोलकाता में अपने साढ़ू के घर छिपा हुआ था। उसने बताया कि उसे एनकाउंटर का डर था। एक दलाल के माध्यम से मामला खत्म कराने आया, तभी पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद वह बीमार भी हो गया। उर्सुला अस्पताल में इलाज के बाद गुरुवार दोपहर उसे डिस्चार्ज कर जेल भेज दिया गया। उसने जीएसटी चोरी व हवाला कारोबार करने वाले इस गिरोह का सरगना अधिवक्ता फिरोज खान को बताया है। महफूज ने पुलिस को 50 से ज्यादा स्क्रैप, स्लाटर व टेनरी कारोबारियों के नाम बताए हैं, जिनके रुपयों को म्यूल खातों में डलवाकर तीन से पांच प्रतिशत कमीशन लेकर उन लोगों को नकदी दे देता था। उसका बंगाल, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली तक नेटवर्क फैला है। जांच में उसके बैंकों में लगे तीन टीडीएस छूट प्रमाण पत्र (एपीएमसी) फर्जी निकले, जिससे पुलिस अब बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि महफूज अली मूलरूप से गाजीपुर का रहने वाला है। उसे सेंट जोसेफ स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसने पत्नी शायदा, बेटे फैज, बेटी एनम, भाई मिशब, साले मेहताब, उसका बेटा मासूम व अन्य के नाम पर बनी फर्मों के 12 बैंकों में 68 खाते खुलवाए थे।

गाय अभयारण्य में पहली बार आइवीएफ से जन्मे बछड़े-बछिया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

- मुजफ्फरनगर के गांव तुगलकपुर कम्हेड़ा में है गाय अभयारण्य

मुजफ्फरनगर : गाय अभयारण्य में जन्मे बछड़ों को दुलारते पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान। सौ. संस्था

देश के पहले केंद्र-वित्त पोषित गाय अभयारण्य ने पशुधन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आइवीएफ तकनीक से देश में पहली बार किसी गोशाला में बछड़े और बछिया का जन्म हुआ है। इनको हीरा, मोती, पद्मिनी व नंदिनी नाम दिया गया है। दावा किया गया है कि अभयारण्य में ये देश के सबसे अच्छी नस्ल में शामिल बछड़े-बछिया हैं। बड़े होने पर ये बछिया 20 से 21 लीटर प्रतिदिन दूध देंगी।

अभयारण्य का संचालन कर रही श्री गोवर्धन गोसेवा समिति के संरक्षक एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने गुरुवार बताया कि एंब्रोय ट्रांसफर (भ्रूण स्थानांतरण) तकनीक केवल शोध संस्थानों तक सीमित थी। इसे पहली बार गाय अभयारण्य में प्रयोग किया गया। देश की सबसे अच्छी नस्ल की गाय का अंडा और सांड़ के शुक्राणु को अभयारण्य में लाई गई बेसहारा गायों में ट्रांसफर किया गया। इस तकनीक से तीन माह पूर्व चार बछड़े और दो दिन पूर्व दो बछिया ने जन्म लिया।

मध्य प्रदेश में कैदी से हुआ महिला जेल अधीक्षक को प्यार, रिहाई होने के बाद किया विवाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना

- अच्छे आचरण के कारण आजीवन सजा काट रहे धर्मेंद्र की चार वर्ष पहले हो गई थी रिहाई
- जेल में रहने के दौरान हुआ था प्यार, विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया कन्या दान

सात फेरे लेने के बाद धर्मेंद्र व फिरोजा।
सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

मध्य प्रदेश के सतना केंद्रीय जेल में तैनात सहायक जेल अधीक्षक फिरोजा खातून को हत्या की सजा काट रहे धर्मेंद्र सिंह से प्यार हो गया। धर्मेंद्र ने 14 साल जेल में बिताए। अच्छे आचरण को देखते हुए शासन ने चार वर्ष पहले उसकी रिहाई कर दी थी। जेल में रहने और रिहा होने के बाद धर्मेंद्र और फिरोजा की मुलाकातें होती रहीं। पिछले दिनों फिरोजा ने हिंदू रीति-रिवाज से धर्मेंद्र के साथ विवाह कर लिया। कन्यादान की रस्म विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निभाई।

छतरपुर जिले के चंदला में तत्कालीन नगर परिषद उपाध्यक्ष कृष्ण दत्त दीक्षित की वर्ष 2007 में हत्या हो गई थी। हत्या के मामले में धर्मेंद्र सिंह को सजा सुनाई गई थी। तब वह 20 वर्ष का था। उसे सतना केंद्रीय जेल में रखा गया, जहां सहायक जेल अधीक्षक के रूप में फिरोजा खातून की तैनाती है। धर्मेंद्र जेल में रहने के दौरान फिरोजा के काम में हाथ बंटाता था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई। अच्छे आचरण को देखते हुए शासन ने जब चार वर्ष पहले धर्मेंद्र को रिहा कर दिया तब भी उनकी मुलाकातें होती रहीं। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। परिवार और समाज की परवाह किए बिना हिंदू रीति-रिवाज से पांच मई को छतरपुर में विवाह कर लिया।

फिरोजा के परिवार ने शादी से बनाई दूरी : जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो फिरोजा के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और शादी से दूरी बना ली। सतना में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष राजबहादुर मिश्रा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माता-पिता के रूप में फिरोजा का कन्यादान किया। जैसे ही इस शादी की खबर सतना जेल पहुंची, वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों और यहां तक कि कैदियों में भी खुशी जताई।

राजस्थान में जलजीवन मिशन घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर

- कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था 960 करोड़ रुपये का है जलजीवन मिशन घोटाला

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 960 करोड़ रुपये से अधिक के जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाला मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। जोशी को जयपुर स्थित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अनिधिनिम क्रम संख्या-एक में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 मई तक रिमांड पर भेजा गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक डा.रामेश्वर सिंह ने बताया कि एसीबी की एसआइटी सुबह महेश जोशी के जयपुर में सेन कालोनी स्थित आवास पर पहुंची। वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश होने के लिए जाते समय जोशी ने मीडिया से कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। सच परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। यदि मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका तो कुछ ऐसा करुंगा कि किसी को मुझसे शिकायत नहीं रहेगी। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने कहा कि जलजीवन मिशन घोटाले की जांच में आए तथ्यों के आधार पर महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। घोटाले में जोशी की अहम भूमिका थी। 50 करोड़ रुपये से अधिक के ठेकों में कार्यस्थल निरीक्षण की शर्त जोड़कर 20 हजार करोड़ रुपये के ठेकों में गड़बड़ी के प्रयास हुए थे। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। फर्जी प्रमाण-पत्रों के साथ ठेके दिए गए। मामले में जलदाय विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल सहित 11 आरोपितों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगभग 60 दिनों तक चला, जो 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ और मई 2026 की शुरुआत में एक युद्ध विराम के साथ समाप्त होने तक पहुंचा है।

ईरान से अस्थायी समझौता चाहता है अमेरिका, होर्मुज खोलने पर जोर

अमेरिका के 14 सूत्रीय समझौता मसौदे की ईरान में समीक्षा जारी, दोनों में तीन चरणों में होगी वार्ता

समझौते पर सकारात्मक रुख की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में उछाल, तेल के दाम 98 डालर पर आए

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान कथित रूप से 14 सूत्रीय अल्पकालिक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों देश व्यापक शांति समझौते के बजाय एक अस्थायी समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य फिलहाल लड़ाई रोकना और होर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता बहाल करना है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में उसकी क्षेत्रीय भूमिका जैसे प्रमुख विवादित मुद्दे फिलहाल अनसुलझे रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, यदि प्रारंभिक समझौते पर सहमति बनती है तो इसके बाद व्यापक समझौते के लिए 30 दिनों की विस्तृत वार्ता शुरू हो सकती है। संभावित समझौते और होर्मुज खुलने की उम्मीद में गुरुवार को वैश्विक शेयर बाजार रिकार्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गए, जबकि कच्चे तेल की कीमत गिरकर 98 डालर पर आ गई। वहीं, इजरायल-लेबनान युद्धविराम को आगे बढ़ाने को 14-15 मई को वाशिंगटन में बैठक करेंगे।

माना जा रहा है कि ईरान अमेरिकी शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के प्रति अपने अविश्वास को दूर नहीं कर पा रहा है। ईरान की ओर से अब तक जवाब न भेजने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। हालांकि, औपचारिक समयसीमा तय नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मध्यस्थों का कहना है कि जल्दी ही ईरान का जवाब आ सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तमाम मुद्दों पर पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से बात की। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना से कहा कि प्रस्ताव अभी समीक्षा के दौर में है और तेहरान सभी पहलुओं का आकलन कर रहा है।

अस्थायी समझौते में कई बड़े मुद्दे फिलहाल बाहर रहेंगे

अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के अनुसार, प्रस्तावित अस्थायी समझौते में ईरान कम से कम 12 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और परमाणु हथियार विकसित नहीं करने पर सहमत हो सकता है। इसके बदले अमेरिका ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने और विदेशी बैंकों में फ्रीज अरबों डालर के ईरानी फंड जारी करने को तैयार है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि दोनों देश हस्ताक्षर के 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में लागू अपनी-अपनी नाकेबंदी समाप्त करेंगे और इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को दोबारा खोलेंगे। इसके बाद व्यापक समझौते पर बातचीत शुरू होगी। अमेरिकी की तरफ से वार्ता का नेतृत्व ट्रंप के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। संभावित व्यापक समझौते में अमेरिका और ईरान द्वारा होर्मुज में लागू नाकेबंदी समाप्त करना, अमेरिकी प्रतिबंध हटाना और ईरानी फंड जारी करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी की निगरानी में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कुछ प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है। हालांकि मसौदे में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक,

पश्चिम एशिया में हिजबुल्ला जैसे सहयोगी गुटों को समर्थन समाप्त करने और ईरान के पास मौजूद करीब 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। मध्यस्थता में शामिल पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रस्तावित समझौते को तीन चरणों में लागू करने की योजना है। पहले चरण में औपचारिक युद्धविराम लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े संकट के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। तीसरे चरण में व्यापक समझौते के लिए 30 दिनों की विस्तृत वार्ता शुरू होगी।

सऊदी ने एयरस्पेस देने से किया इन्कार, इसलिए ट्रंप ने रोका 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'

- होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित अमेरिकी नौसैनिक अभियान पर लगी रोक
- सऊदी अरब के कदम से खाड़ी युद्ध में अमेरिका को समर्थन में कमी के संकेत

वाशिंगटन, एएनआइ : पश्चिम एशिया में कायम तनाव के बीच अमेरिका द्वारा होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को दो दिन के अंदर ही रोकना पड़ गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि यह फैसला पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। बताया गया कि ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत भी की, लेकिन किसी सहमति तक नहीं पहुंच सके। हालांकि सऊदी सूत्रों ने यह स्वीकार नहीं किया कि वे अमेरिकी योजना से नाराज थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड 'सेंटकाम' का दावा है कि दो दिन में तीन जहाज होर्मुज से निकले थे।

एनबीसी न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन ने होर्मुज से मालवाहक जहाजों को सैन्य सुरक्षा देने की योजना बनाई थी। इसके तहत अमेरिकी विमानों और नौसैनिक संसाधनों का इस्तेमाल होना था। हालांकि सऊदी अरब ने रियाद के दक्षिण-पूर्व में स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस के उपयोग और अमेरिकी विमानों को अपने एयरस्पेस से उड़ान भरने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद अभियान को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया।

दावे व खाड़ी देशों की अलग तस्वीर

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिकी अभियान की जानकारी क्षेत्रीय सहयोगी देशों को पहले ही दे दी गई थी। हालांकि पश्चिम एशिया के एक राजनयिक ने एनबीसी न्यूज से कहा कि अमेरिका ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' की सार्वजनिक घोषणा के बाद ही ओमान के साथ समन्वय किया। राजनयिक के मुताबिक, अमेरिका ने पहले घोषणा की और बाद में हमसे संपर्क किया।

ईरान ने जहाजों को सहायता देने की पेशकश की

उधर, ईरान ने भी होर्मुज स्ट्रेट में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन ने गुरुवार को घोषणा की कि वह होर्मुज और आसपास के क्षेत्र में संचालित व्यापारिक जहाजों को समुद्री, तकनीकी और चिकित्सीय सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए जहाजों को निकटतम ईरानी बंदरगाह के वेसल ट्रैफिक सर्विस (वीटीएस) केंद्र से संपर्क करना होगा। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, यह संदेश जहाजों के कप्तानों तक औपचारिक समुद्री संचार माध्यमों से पहुंचाया जा रहा है।

एआइ के लिए संविधान संशोधित करेगा ग्रीस, मानवता को देगा प्राथमिकता

- प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा रखी
- कहा-ये संशोधन भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक

एथेंस, एपी : ग्रीस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते खतरों के बीच मानवता को प्राथमिकता देने के लिए अपने संविधान में बड़ा ऐतिहासिक संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि इसमें एआइ को मानव समाज की सेवा करने के लिए अनिवार्य बनाने वाला संशोधन शामिल है।

प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोटाकिस ने गुरुवार को प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये संशोधन भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर एआइ से लोकतांत्रिक शासन और स्वयं मानवता को होने वाले जोखिमों के बारे में चिंताएं हैं।

उन्होंने सांसदों से कहा, "संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उस दुनिया का ध्यान रखें, जो हमारे बच्चों की मेजबानी करेगी।" प्रस्तावित बदलावों में एक प्रविधान शामिल होगा जिसमें कहा गया है, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की समृद्धि की सेवा करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि जोखिमों को कम किया जाए और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को पूरी तरह से साकार किया जाए।" दर्जनों अन्य बदलावों में पोस्टल वोटिंग का विस्तार, अनिवार्य स्कूली शिक्षा की आयु नौ से बढ़ाकर 11 वर्ष करना और पूर्वव्यापी कराधान पर प्रतिबंध लगाना शामिल होगा।

प्रतीकात्मक

चीन में भ्रष्टाचार के दोषी दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मिली मौत की सजा

- राकेट फोर्स के प्रमुख के तौर पर वेई फेंग और ली शांग्फू ने ली थी रिश्वत
- दोनों के सारे राजनीतिक अधिकार खत्म, सारी संपत्ति भी जब्त होगी

बीजिंग, प्रेट्र : चीन में दो पूर्व रक्षा मंत्रियों-वेई फेंग और ली शांग्फू को भ्रष्टाचार मामलों में दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। इस सजा पर क्रियान्वयन दो वर्ष बाद होगा, तब तक वे कारागार में रहेंगे। सैन्य अदालत ने दोनों पर अलग-अलग मुकदमा चलाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई है।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि वेई को रिश्वत लेने का दोषी पाया गया जबकि ली को रिश्वत लेने और रिश्वत देने का प्रयास करने का दोषी पाया गया है। दोनों के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं और उनकी सारी संपत्ति भी जब्त होगी। वेई 2018 से 2023 तक चीन के रक्षा मंत्री रहे जबकि ली ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में कुछ महीने ही कार्य किया। दोनों को शक के आधार पर पदों से बर्खास्त कर दिया गया था। दोनों ही राष्ट्रपति चिनफिंग की अध्यक्षता वाले चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य भी थे। रक्षा मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद उन्हें आयोग से भी हटा दिया गया।

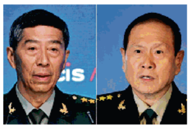

ली शांग्फू और वेई फेंग।

जनरल वेई और जनरल ली चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई राकेट (मिसाइल) फोर्स के प्रमुख रहे। यह फोर्स 2015 में राष्ट्रपति चिनफिंग ने सेना के ढांचे में बदलाव के दौरान स्थापित की थी। वेई इस फोर्स की स्थापना से लेकर 2017 तक इसके प्रमुख रहे और उसके बाद रक्षा मंत्री बन गए। रक्षा मंत्री रहते हुए वेई अचानक लापता हो गए थे, बाद में उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी का पता चला था। हिरासत में ही उन पर भ्रष्टाचार मामले में सैन्य अदालत में मुकदमा चला। जबकि ली को राष्ट्रपति शी ने स्वयं रक्षा मंत्री नियुक्त किया था। ली की बर्खास्तगी के बाद पीएलए के कई शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया और उनमें से कई पर भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया गया।

2012 में शी चिनफिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार निरोधी अभियान चला था। इस अभियान में 10 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को दंडित किया गया। दंडित होने वालों में सेना के कई जनरल भी शामिल हैं।

जयशंकर ने सूरीनाम को विकास यात्रा में सहयोग का दिया आश्वासन

- कहा, भारत डिजिटल क्षमताओं में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार

पारामारिबो, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत सूरीनाम की विकास क्षमता को देखता है और दक्षिण अमेरिकी देश को आश्वासन दिया कि नई दिल्ली उसके विकास के सफर में उसका सहयात्री और साझेदार रहेगा। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर नौ दिवसीय तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में सूरीनाम पहुंचे हैं।

संयुक्त आयोग की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और सूरीनाम व्यापार, पर्यटन, डिजिटल क्षमताओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए। भारत द्वारा समर्थित विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने हाल ही में पूर्ण हुई एक पैशन फ्रूट प्रसंस्करण इकाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक चेतावनी सेवा वितरण परियोजना का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियन क्षेत्र के बीच व्यापार वर्तमान में लगभग 40 से 45 अरब अमेरिकी डालर प्रति वर्ष है। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग पर उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल प्रक्रियाओं और क्षमताओं में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है क्योंकि देश एआइ युग में प्रवेश कर रहे हैं।

एस जयशंकर।

पर्वतारोहियों के हौसले को कम नहीं कर पा रहा विशाल हिमखंड

काठमांडू, एपी : माउंट एवरेस्ट पर प्रमुख पर्वतारोहण मार्ग पर खतरनाक रूप से लटके एक विशाल अस्थिर हिमखंड पर्वतारोहियों का दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के हौसले को कम नहीं कर पा रहा है। लगभग 410 पर्वतारोही और लगभग उतने ही नेपाली गाइड इस महीने 8,850 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ाई के लिए आधार शिविर में तैयारी कर रहे हैं। पर्वतारोही पिछले महीने 5,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आधार शिविर में इकट्ठा होना शुरू हुए थे। लेकिन दो सप्ताह से अधिक समय से विशाल अस्थिर हिमखंड ने उन्हें शिखर पर आगे बढ़ने से रोक रखा है। सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीम ने आइसफाल मार्ग को 29 अप्रैल को खोला। हालांकि चेतावनी भी जारी की, "सेराक में कई दरारें हैं और यह किसी भी समय ढह सकता है। समिति अभियान संचालकों और पर्वतारोहियों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह करता है।

बांग्लादेश के मदरसों में मासूमियत पर प्रहार, बढ़ रहे हैं यौन हिंसा के मामले

- मासूमों के खिलाफ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर मानवाधिकार संगठनों ने जताई गंभीर चिंता
- कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सभी मदरसों में यौन उत्पीड़न समितियों के तत्काल गठन की मांग की

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश के मदरसों में मासूमों के साथ हो रही यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने देश के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है। प्रमुख मानवाधिकार संस्था 'मानुषेर जोन्नो फाउंडेशन' (एमजेएफ) ने इन घटनाओं पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। संस्था का कहना है कि शिक्षा के इन केंद्रों में मासूमों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो बेहद चिंताजनक है। ढाका स्थित इस संस्था ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप, देश भर के सभी मदरसों में यौन उत्पीड़न समितियों के तत्काल गठन की मांग की है।

दहला देने वाली घटनाएं और न्याय की मांग : हाल ही में नेतोकोना जिले के मदन उपजिला में एक 11 वर्षीय छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने रूह कंपा दी है। आरोप है कि एक मदरसा शिक्षक पिछले अक्टूबर से मासूम का शोषण कर रहा था, जिसका पर्दाफाश तब हुआ जब चिकित्सीय जांच में वह गर्भवती पाई गई। इसी तरह पटुआखली जिले में भी एक 10 वर्षीय छात्र के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 'बांग्लादेश महिला परिषद' के आंकड़े बताते हैं कि इस साल के शुरुआती चार महीनों में ही कुल 1028 महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा सहित विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ा है। ये आंकड़े लड़कियों से जुड़े एक चिंताजनक पैटर्न को उजागर करते हैं, जिसमें जनवरी से अप्रैल के बीच 479 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है।

सिस्टम की विफलता व जवाबदेही का सवाल : एमजेएफ की कार्यकारी निदेशक शाहीन अनम का कहना है कि मदरसे भी शैक्षणिक संस्थान हैं, इसलिए उन्हें हाईकोर्ट के 2023 के उन निर्देशों से बाहर नहीं रखा जा सकता, जिनमें यौन उत्पीड़न रोकथाम समितियां बनाना अनिवार्य है। अक्सर रसूख और सामाजिक प्रभाव के कारण इन अपराधों को दबा दिया जाता है। संस्था ने मांग की है कि 'महिला एवं बाल दमन निवारण अधिनियम, 2000' को पूरी सख्ती से लागू किया जाए और संसद में लंबित 'यौन उत्पीड़न कानून' को जल्द से जल्द पारित किया जाए। समाज और सरकार दोनों को अपनी विफलता स्वीकार करते हुए मासूमों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा, ताकि आस्था के केंद्रों में मासूमियत का कत्ल न हो सके।

हंटावायरस से पहली मौत के बाद क्रूज से उतर गए थे दर्जनों यात्री

- दर्जनों यात्रियों के 24 अप्रैल को बिना संपर्क ट्रेसिंग के उतरने की सूचना दी गई है
- अधिकारी जहाज से उतरे यात्रियों के संपर्कों का पता लगाने की कोशिश कर रहे

द हेग, एपी : जहाज संचालक और डच अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि घातक हंटावायरस के प्रकोप से प्रभावित एक क्रूज से दर्जनों यात्री 24 अप्रैल को बिना संपर्क ट्रेसिंग के जहाज छोड़ गए थे। यह घटना जहाज पर पहले यात्री की मौत के लगभग दो सप्ताह बाद हुई थी। कंपनी ने पहले कहा था कि 11 अप्रैल को मृत डच व्यक्ति का शव सुदूर दक्षिण अटलांटिक द्वीप सेंट हेलेना पर जहाज से उतारा गया था, जहां उनकी पत्नी भी उतरी थीं। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुईं और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।

कंपनी ने कहा कि 29 यात्रियों ने जहाज छोड़ा, जबकि डच विदेश मंत्रालय ने यह संख्या लगभग 40 बताई है। कंपनी ने पहले यह स्वीकार नहीं किया था कि उस समय दर्जनों और लोग जहाज से उतरे थे। ओशनवाइड एक्सपेडिशन्स ने कहा कि अपने-अपने देशों में लौटने वाले लोग 12 अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के थे। दो ऐसे लोग भी थे, जिनकी राष्ट्रीयता अज्ञात थी।

प्रतीकात्मक

दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के अधिकारी जहाज से उतरे सभी यात्रियों के संपर्कों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को यह जानकारी सामने आई कि सेंट हेलेना में जहाज से उतरने और वापस घर जाने के बाद स्विट्जरलैंड में एक व्यक्ति में हंटावायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, हालांकि उसके सटीक संपर्क विवरण स्पष्ट नहीं हैं।

'लेखिका को हर्जाना देने वाले अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगाएं'

न्यूयार्क, एपी : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने न्यूयार्क की एक संघीय अपील अदालत से अपने उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का अनुरोध किया है, जिसमें लेखिका ई. जीन कैरोल को 8.3 करोड़ अमेरिकी डालर का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया था। वकील ने याचिका में अमेरिकी सर्किट कोर्ट आफ अपील्स से अनुरोध किया कि वह मुआवजे के समर्थन में दिए गए अपने फैसले पर रोक लगाए, ताकि ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान लेखिका ई. जीन कैरोल को भुगतान न करना पड़े।

मैनहट्टन की एक जूरी ने जनवरी 2024 में कैरोल को मुआवजा देने का आदेश दिया था। मई 2023 में एक अन्य जूरी ने कैरोल को 50 लाख डालर का मुआवजे का फैसला सुनाया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि ट्रंप ने 1996 में मैनहट्टन के एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनका यौन उत्पीड़न किया था।

वेटिकन से ट्रंप के तनाव के बीच पोप से मिले रूबियो

न्यूयार्क टाइम्स से

रोम: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को वेटिकन में पोप लियो से निजी मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप के बीच तनाव बढ़ गया है।

विदेश विभाग के प्रवक्ता टामी पिगाट के अनुसार, उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात और पश्चिमी गोलार्ध में आपसी हितों के विषयों पर चर्चा की। यह बैठक पोप की निजी लाइब्रेरी में हुई, जो सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने एक महल में स्थित है। पोप और रूबियो ने वेटिकन और वाशिंगटन के बीच संबंधों को बेहतर करने की बात कही है। वेटिकन ने कहा कि पोप और रूबियो ने अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐसे समय वेटिकन का दौरा किया, जब ट्रंप ईरान युद्ध की आलोचना करने को लेकर पोप पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ट्रंप ने पोप को कमजोर कहने के साथ उन पर वामपंथी होने का आरोप लगाया है।

पोखरा हवाई अड्डे के भ्रष्टाचार में पूर्व मंत्री और चीनी कंपनी शामिल

- भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया चौथा मामला

काठमांडू, आइएएनएस : नेपाल की भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में एक पूर्व मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, एक चीनी कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया है। यह भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा पिछले डेढ़ वर्षों में विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया चौथा मामला है, जो चीन द्वारा वित्त पोषित करोड़ों डालर की परियोजना में भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह हवाई अड्डा एक दिखावटी परियोजना साबित हुआ क्योंकि यहां से कोई निर्धारित उड़ानें संचालित नहीं होती हैं।

यह परियोजना चीन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक से 215.96 मिलियन डालर की वित्तीय सहायता से बनाई गई थी और इसे चीन सीएएमसी इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने कार्यान्वित किया था। सीआइएए का कहना है कि उसने पूर्व वित्त मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की, कई पूर्व सचिवों, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इसमें कुल 11 अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। कार्की पोखरा हवाई अड्डे के भ्रष्टाचार मामले में आरोपित होने वाले छठे पूर्व मंत्री हैं।

पूर्व मंत्रियों भीम आचार्य, राम कुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, राम शरण महत व बहादुर बोगाटी को भी आरोपित किया गया था। चीनी ठेकेदार और उसके अधिकारी "अध्यक्ष वांग बो और परियोजना प्रबंधक यांग झीगांग" पर भी अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने में सहायता देने का आरोप है।

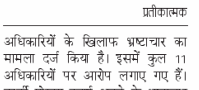

प्रतीकात्मक

दक्षिण कोरियाई अदालत ने मार्शल ला मामले में पूर्व पीएम की सजा की कम

सियोल, एपी : दक्षिण कोरिया की अपील अदालत ने मार्शल ला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की सजा कम कर दी है। उन्हें इसके लिए विद्रोह का दोषी ठहराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री हान डक-सू, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक येओल ने नियुक्त किया था, को जनवरी में सियोल की एक अदालत ने 23 साल की सजा सुनाई थी। वहीं, यून को विद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सियोल हाई कोर्ट ने गुरुवार को हान के अधिकांश दोषों को बरकरार रखा, लेकिन सजा को घटाकर 15 साल कर दिया। अदालत ने उन आरोपों को बरकरार रखा जिनमें यह भी शामिल गया था कि हान ने यून के अवैध फरमान को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिलाकर उसे वैध करार देने की कोशिश की थी। सियोल हाई कोर्ट ने कहा कि हान के आपराधिक दायित्व बहुत गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने यून प्रशासन में दूसरे नंबर के अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का त्याग किया और विद्रोह में भाग लिया।

बेरूत हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, आतंकी कहीं सुरक्षित नहीं

- बेरूत के दक्षिणी इलाकों में इजरायली हमले में हिजबुल्ला कमांडर की मौत
- इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान में बुधवार को 11 लोग मारे गए

यरुशलम, रायटर: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि दुश्मनों को कहीं भी कोई छूट नहीं मिलेगी। उनका यह बयान बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल के ताजा हवाई हमले के एक दिन बाद आया है। यह पिछले महीने घोषित युद्धविराम के बाद बेरूत क्षेत्र पर पहला बड़ा इजरायली हमला था। चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी आतंकी इजरायल की पहुंच से बाहर नहीं है।

इजरायली सेना ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान समर्थित हिजबुल्ला के विशेष रदवान बल के एक कमांडर की मौत हुई है। सेना ने उसकी पहचान अहमद अली बलूत के रूप में की है। हालांकि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर नियंत्रण रखने वाले हिजबुल्ला ने अब तक हमले या कमांडर की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने बुधवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों के खिलाफ 17 अभियान चलाए, जबकि इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने उसी दिन दक्षिण में 15 से अधिक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। बुधवार को दक्षिणी लेबनान के तीन अलग-अलग इलाकों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई।

बेंजामिन नेतन्याहू। फाइल

इजरायली हमले में हमास के शीर्ष वार्ताकार का बेटा मारा गया

गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही वार्ता के बीच इजरायली हवाई हमले में हमास के प्रमुख वार्ताकार खलील अल-हय्या के बेटे की मौत हो गई। हमास के वरिष्ठ अधिकारी बासिम नईम ने कहा कि खलील अल-हय्या के बेटे अज्जाम अल-हय्या बुधवार रात हुए हमले में घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। अज्जाम अल-हय्या, खलील अल-हय्या के चौथे बेटे हैं, जो इजरायली हमलों में मारे गए हैं। खलील अल-हय्या हमास के निर्वासित गाजा प्रमुख हैं और अमेरिका समर्थित वार्ताओं में संगठन की ओर से प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना ने इस हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

आइपीएल में गर्लफ्रेंड संस्कृति' और डगआउट में अनधिकृत लोगों पर बीसीसीआइ लेगा एक्शन

जागरण प्रभाव

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

नई दिल्ली: बीसीसीआइ की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (एसीएसयू) ने आइपीएल में गर्लफ्रेंड संस्कृति और मैचों के दौरान टीम डगआउट, टीम बस, होटल और प्लेयर्स एंड मैच आफिशियल्स एरिया (पीएमओए) में अनधिकृत लोगों की मौजूदगी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इसके बाद बीसीसीआइ ने सभी फ्रेंचाइजियों को सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को और कड़ा करने का फैसला किया है। दैनिक जागरण ने चार मई के अंक में प्रकाशित खबर में बताया था कि बीसीसीआइ 'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआइ भविष्य में खड़े होने वाले बड़े संकट से पहले ही कदम उठाना चाहता है। दरअसल, आइपीएल में हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल समेत कई खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के कारण चर्चा में हैं। इनके टीम बस या टीम होटल तक में जाने पर कोई रोक नहीं है। यही नहीं कई जूनियर खिलाड़ी कई ऐसी महिला मित्रों के साथ देखे गए हैं जो बेटिंग ऐप को प्रमोट करती हैं।

आइपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार को पुष्टि की कि एसीएसयू ने बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टीम बसों, डगआउट और टीम होटलों में बिना अनुमति देखे गए हैं,

बीसीसीआइ ने सभी फ्रेंचाइजियों के लिए जारी की एडवाइजरी, इस सप्ताह होगी अहम बैठक

जिसे बोर्ड ने बेहद गंभीरता से लिया है। बीसीसीआइ सभी फ्रेंचाइजियों को एसओपी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहेगा ताकि टूर्नामेंट की पवित्रता बनी रहे। वहीं, बीसीसीआइ सचिव देवजीत सैकिया ने भी साफ किया कि 2008 से लागू नियमों का कई लोग अब लापरवाही से पालन कर रहे हैं। टीम बसों और होटलों में अनधिकृत लोगों की मौजूदगी के अलावा कुछ लोग ऐसे क्षेत्रों में भी देखे गए जहां उनका

'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर सख्ती की तैयारी

चार मई को दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर

प्रवेश प्रतिबंधित है। हम किसी भी उल्लंघन पर नरमी नहीं बरतेंगे। शनिवार तक सभी फ्रेंचाइजियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे ताकि सभी को प्रोटोकाल की गंभीरता समझाई जा सके।

सूत्रों के अनुसार एसीएसयू ने विशेष रूप से कुछ युवा खिलाड़ियों के व्यवहार पर नजर रखी है। कुछ खिलाड़ी 'पत्नी और गर्लफ्रेंड्स श्रेणी का गलत फायदा उठाकर अज्ञात महिलाओं को टीम होटल और बसों तक पहुंच दिला रहे थे। एक फ्रेंचाइजी सूत्र ने दावा किया कि कई बार ऐसी महिलाएं खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड बताकर परिवारों के लिए आरक्षित टीम बसों में यात्रा करती देखी गईं। एसीयू को आशंका है कि अनुभवहीन खिलाड़ी 'हनी ट्रैप' का शिकार हो सकते हैं। इसी कारण नए एसओपी में खास तौर पर गर्लफ्रेंड्स की एंट्री को लेकर सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। बीसीसीआइ अधिकारी टीमों के आसपास इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर्स की बढ़ती मौजूदगी से भी नाराज बताए जा रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि एक पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज की पत्नी ने टीम होटल से इंटरनेट मीडिया पोस्ट डालकर पहले भी विवाद खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद सबक नहीं लिया गया। इस सीजन आइपीएल में कई विवाद सामने आ चुके हैं। राजस्थान रायल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के कारण एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वहीं कप्तान रियान पराग पर ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा युजवेंद्रा सिंह चहल का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह फ्लाइट में वेप इस्तेमाल करते दिखे थे। भारत में इलेक्ट्रानिक सिगरेट एक्ट के तहत वेपिंग गैरकानूनी है। बीसीसीआइ ने साफ कर दिया है कि अब एंटी करप्शन नियमों को लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी। बोर्ड को डर है कि टीमों के आसपास बढ़ती अनधिकृत पहुंच भविष्य में खेल की साख और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकती है।

केएससीए ने मांगी थी 10,000 अतिरिक्त टिकट: सैकिया

नई दिल्ली: बीसीसीआइ के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि आइपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु से बाहर ले जाने का फैसला कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) की तरफ से 10,000 से ज्यादा मुफ्त टिकटों की मांग के कारण लेना पड़ा। सैकिया ने गुरुवार को कहा कि सभी राज्य संघों को उनकी कुल क्षमता का 15 प्रतिशत हिस्सा कंप्लीमेंट्री टिकटों के रूप में मिलता है, लेकिन हमें पता चला है कि कर्नाटक राज्य संघ 15 प्रतिशत से कहीं ज्यादा कंप्लीमेंट्री टिकट ले रहा है। इसलिए, हमने उन्हें एक ई-मेल भेजा। उन्होंने कहा कि दो मई को हमें केएससीए की तरफ से एक ई-मेल मिला, जिसे देखकर हम हैरानी हुई। ई-मेल में कहा गया था कि 15 प्रतिशत टिकट और उस कोटे के तहत मिलने वाले कंप्लीमेंट्री टिकटों के अलावा उन्हें बड़ी संख्या में टिकट चाहिए। इसके बाद उनके लाइफ मेंबर्स के लिए भी टिकट मांगे गए। हैरानी की बात यह थी कि हमें उनके विधायकों और एमएलसी के लिए 900 टिकट और सरकार के लिए भी 700 टिकट देने थे। इसके अलावा क्रिकेट संघ को कुछ अतिरिक्त कंप्लीमेंट्री टिकट देने की मांग की गई, ताकि वे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार लोगों में बांट सकें। यानी 15 प्रतिशत कोटे के अलावा वे करीब 10,000 अतिरिक्त टिकट मांग रहे थे।

मार्श के आगे पस्त हुए आरसीबी के गेंदबाज

एलएसजी ने आरसीबी को दिया 210 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिशेल ने 56 गेंदों पर बनाए 111 रन

विकास मिश्र ● जागरण

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरी बार 200 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही है। वैसे तो एलएसजी प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू के विरुद्ध मिशेल मार्श (111) की तूफानी पारी ने स्थानीय दर्शकों को पहली बार झूमने का अवसर दिया। मार्श की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ ने बारिश से बाधित मैच में 19 ओवर में तीन विकेट खोकर 209 रन बनाए, पर डकवर्थ लुईस नियम के तहत आरसीबी को जीत के लिए 19 ओवर में 213 रन बनाने होंगे।

इसके पहले आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टास जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन एलएसजी के बल्लेबाजों खासकर मार्श ने इस निर्णय को गलत साबित किया। लखनऊ ने सीजन में दूसरी बार पावरप्ले में 10 रन प्रति ओवर से अधिक के औसत से रन बनाए। इसके पहले टीम ने मुंबई के विरुद्ध छह ओवर में 90 रन जोड़े थे। इस मुकाबले में मार्श के साथ साथ युवा बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी (17) बतौर ओपनर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसी बीच, मार्श ने सिर्फ 20 गेंदों पर तीन चौके व पांच छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया।

शाट लगाते मिशेल मार्श ● एपी

कुलकर्णी और मार्श ने पहले विकेट के लिए 9.2 ओवर में 95 रन जोड़े। पिछले मैच में 21 गेंदों पर 63 रन बनाने वाले निकोलस पूरन ने यहां भी अपनी लय बरकरार रखी और 23 गेंदों पर चार चौके व एक छक्के की मदद से शानदार 38 रन बनाए। मिचेल ने दूसरे विकेट के लिए भी महत्वपूर्ण 70 रनों की साझेदारी।

मार्श ने लगातार दूसरे सीजन जड़ा शतक: क्रीज पर जम चुके मिशेल मार्श ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के अलावा किसी भी बल्लेबाज को नहीं बख्शा। जोश हेजलवुड के एक ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर यह संदेश दिया कि वह इस मुकाबले में कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरें हैं। मिचेल ने पहले अर्धशतक और उसके बाद महज 50 गेंदों पर नौ चौके व आठ छक्कों के सहारे लगातार दूसरे साल अपना शतक भी पूरा किया। दूसरी ओर, कप्तान रिषभ पंत ने भी शानदार पारी खेली। हालांकि, उन्हें सिर्फ 10 गेंदें खेलने को मिलीं, लेकिन इस दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखे। उन्होंने 32 रनों की नाबाद पारी में चार चौके व दो छक्के जड़े।

बारिश से एक घंटा 25 मिनट का खेल बाधित: बारिश के चलते तीन बार मैच को रोकना पड़ा। पहली बार एलएसजी की पारी के दूसरे ओवर में 10 मिनट का मैच बाधित हुआ, जबकि दूसरी बार नौवें ओवर में वर्षा शुरू हुई, जिससे 38 मिनट तक खेल रुका रहा। आखिरी बार 14 ओवर के बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार मैच शुरू होने में 37 मिनट का समय लगा। इस तरह से एलएसजी की पारी के दौरान कुल एक घंटा 25 मिनट तक मैच बाधित रहा। बार-बार बारिश के चलते मैच में एक ओवर घटाना पड़ा।

200 आइपीएल मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवी: इस मैच में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू के तेज गेंदबाज और स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। भुवी आइपीएल में सर्वाधिक 200 मैच खेलने पहले तेज गेंदबाज बने। 200 मुकाबलों में उन्होंने कुल 215 विकेट हासिल किए। पहले स्थान पर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 186 मैच में 229 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर यूपी की ओर से आइपीएल में 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सुरेश रैना ने लीग में सर्वाधिक 205 मैच खेले हैं। लखनऊ विरुद्ध भुवी ने चार ओवर में 34 रन दिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

स्कोर बोर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्सर: 209/3(19 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
मार्श का. बेथेल बो. हेजलवुड	111	56	9/9
अर्शिन का. रजत बो. कुणाल	17	24	1/0
पूरन का. कुणाल बो. रसिख	38	23	4/1
पंत अविजित	32	10	4/2
मार्करैम अविजित	1	1	0/0

अतिरिक्त: 10 (लेबा: 5, वा: 5)

विकेटपतन: 1-95 (अर्शिन, 9.2), 2-165 (मार्श, 16.1), 3-194 (पूरन, 18.2)

गेंदबाजी: भुवनेश्वर 4-0-34-0, हेजलवुड 4-0-49-1, कुणाल 4-0-31-1, रसिख 4-0-53-1, सुयश 2-0-21-0, शेफर्ड 1-0-16-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	हैदराबाद	11	7	4	0	+0.737	14
2	पंजाब	10	6	3	1	+0.571	13
3	आरसीबी	9	6	3	0	+1.420	12
4	राजस्थान	10	6	4	0	+0.510	12
5	गुजरात	10	6	4	0	-0.147	12
6	चेन्नई	10	5	5	0	+0.151	10
7	दिल्ली	10	4	6	0	-0.949	8
8	कोलकाता	9	3	5	1	-0.539	7
9	मुंबई	10	3	7	0	-0.649	6
10	लखनऊ	9	2	7	0	-1.076	4

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला आज

दिल्ली के लिए चुनौती बनी अस्थिर बल्लेबाजी

लोकेश शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। प्लेआफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली को अपने बचे हुए चारों मुकाबले जीतने होंगे। ऐसे में टीम की सबसे बड़ी चिंता उसकी अस्थिर बल्लेबाजी बन गई है।

केएल राहुल को छोड़ दें तो दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। टीम प्रबंधन द्वारा बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। समीर रिजवी को पूरे सत्र में तीसरे नंबर पर खिलाने की योजना थी, लेकिन लगातार क्रम बदलने से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। शुरुआती दो मैचों में अच्छी पारियां खेलने के बाद वह लय बरकरार नहीं रख सके। वहीं नीतीश राणा और करुण नायर भी टीम को जीत दिलाने में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी में दिल्ली की स्थिति इस मुकाबले में मजबूत नजर आ रही है। दूसरी ओर कोलकाता की बल्लेबाजी भी संतुलित नहीं दिख रही। रहाणे और फिन एलन टीम को मजबूत शुरुआत देने में संघर्ष कर रहे हैं।

दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। यदि अक्षर पटेल की टीम बल्लेबाजी में सुधार नहीं कर पाती, तो प्लेआफ की राह और कठिन हो सकती है। वहीं कोलकाता के नौ मैच में सात अंक है यदि उन्हें अंक तालिका में टाप चार में आना है तो उन्हें पांच की पांच मुकाबले जीतने होंगे।

राहुल पर निर्भर दिल्ली टीम: दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी इस सीजन में काफी हद तक केएल राहुल पर निर्भर रही है। राहुल 10 पारियों में 445 रन बना चुके हैं। राहुल ने टीम के कुल रन के 26 प्रतिशत अकेले बनाए हैं।

टीम एक जुट होकर प्लेआफ में वापसी की कोशिश: मिलर

जासं, नई दिल्ली: डेविड मिलर ने प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूदा मुश्किल दौर में किसी एक खिलाड़ी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है और पूरी टीम एकजुट होकर प्लेआफ की दौड़ में वापसी करने की कोशिश कर रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध मुकाबले से पहले मिलर ने कहा कि टीम के अंदर साफ संदेश है कि जीत और हार दोनों में सभी खिलाड़ी साथ हैं। मिलर ने कहा कि दिल्ली ने इस सत्र में पूरी तरह खराब क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन कई मौकों पर टीम ने अहम समय पर गलतियां कीं। उन्होंने माना कि बल्लेबाजी के दौरान लगातार विकेट गिरना टीम के लिए बड़ी समस्या बना। कई मैचों में दो-तीन विकेट एक साथ गिरने से टीम दबाव में आ गई। उन्होंने फील्डिंग को भी चिंता का विषय बताया।

अक्षर पटेल | अजिंक्य रहाणे

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विपराज निगम, मिशेल स्टार्क, डेविड मिलर, आकिब नबी डार, पथुम निसंका, लुंगी नगिदी, साहिल पारख, पृथ्वी शा, काइल जैमीसन, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, अजय जादव मंडल, करुण नायर, टी नटराजन।

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पावेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल राय, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, टिम साइफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजराबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, फिन एलन, दक्ष कामरा, कार्तिक त्यागी, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे।

खेल डायरी

विनेश की वापसी में नियम बन सकते हैं रोड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र: पहलवान विनेश फोगाट की प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी की पात्रता पर गोंडा में होने वाले राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि संन्यास के बाद वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के अनिवार्य छह महीने के नोटिस के नियम का पालन करने को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। विनेश ने 2024 पेरिस ओलिंपिक में मिली निराशा के बाद खेल से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में उन्होंने फिर से प्रतिस्पर्धी कुश्ती में लौटने की इच्छा जताई थी। विनेश ने 10-12 मई तक होने वाले ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में 57 किग्रा वर्ग में हिस्सा लेने के लिए प्रविष्टि दी है। हालांकि यह अब भी साफ नहीं है कि विश्व चैंपियनशिप की पूर्व पदक विजेता विनेश ने वाडा के नियम 5.6.1 के तहत तय की गई शर्तों को पूरा किया है या नहीं। यह नियम संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में वापसी को नियंत्रित करता है। इस नियम के अनुसार पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में शामिल कोई भी खिलाड़ी अगर संन्यास लेने के बाद फिर से सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहता है तो उसे संबंधित अंतरराष्ट्रीय महासंघ और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को छह महीने पहले लिखित नोटिस देकर खुद को परीक्षण के लिए उपलब्ध कराना होगा।

डीपी गोल्फ टूर में खिलाड़ियों को मिले 14 करोड़

डीपी वर्ल्ड प्लेयर चैंपियनशिप के विजेता अक्षय शर्मा (मध्य में) व अन्य ● आयोजक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर आफ इंडिया (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआइ) ने 2026 सीजन की अपनी सबसे मजबूत शुरुआतों में से एक दर्ज की। जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान इस टूर में 12 इवेंट आयोजित किए। जिनमें कुल पुरस्कार राशि 14 करोड़ रही। इसमें डीपी वर्ल्ड पीजीटीआइ नेक्सजेन शामिल है। सीजन के शुरुआती हिस्से में तीन टूर्नामेंट में 1.5 करोड़ और एक करोड़ की पुरस्कार राशि रही, जबकि दो प्रमुख इवेंट में लगभग 2.76 करोड़ की पुरस्कार राशि दी गई। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआइ के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि का विस्तार भारतीय पेशेवर खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर पैदा कर रहा है। सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा कि हमारा फोकस टूर खिलाड़ियों को वैश्विक मंच देना है।

कुछ फैसले दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में नहीं गए: इरफान

खेल संवाददाता, नई दिल्ली: प्लेआफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब हर 'मैच करो या मरो' की स्थिति है। टीम 10 में से छह मैच हारकर सातवें स्थान पर है और अगर उसे प्लेआफ में पहुंचना है तो बाकी चारों मैच जीतने होंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का मानना है कि कुलदीप यादव की खराब फार्म और मिशेल स्टार्क की शुरुआती मुकाबलों में गैरमौजूदगी टीम को भारी पड़ी है।

इरफान पठान

इरफान ने गुरुवार को जियोहाटस्टर के वर्चुअल राउंड टेबल में कहा, अगर मुकाबले की बात करें, तो टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करना और यह सोचना कि बाद में कंडीशन बेहतर हो जाएगी, एक दिक्कत थी। आरसीबी के विरुद्ध मैच हुआ था उसी मैदान पर वह पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और 75 रन पर आउट हो गए थे। उस दिन भी मौसम की दिक्कत थी और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में भी बारिश हुई और मौसम खराब होने की आशंका थी। आप वहां चेज करना चाहते हैं और आपने टास भी जीता था। मुझे लगता है कि सही फैसले लेने में भी चूक हुई। स्टार्क की शुरुआती मुकाबलों में गैरमौजूदगी भारी पड़ी। दूसरा कुलदीप का फार्म में नहीं होना, यह दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है।

सीरीज के बावजूद आइपीएल में बने रहेंगे आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

मेलबर्न, प्रेट्र: कप्तान पैट कमिंस सहित उसके अन्य खिलाड़ियों को आइपीएल 2026 में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने की स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में 30 मई से आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के बावजूद आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आइपीएल में खेलने के लिए रुके रहेंगे।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि की है। आइपीएल का लीग चरण 24 मई को संपन्न होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। इस समय तक आइपीएल का अंतिम चरण शुरु हो जाएगा होगा।

महिला टीम ने विश्व कप में पदक पक्का किया

तीरंदाजी विश्व कप

शंघाई, प्रेट्र: भारत का तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में गुरुवार को प्रदर्शन मिला जुला रहा जब महिला रिकर्व टीम ने रिकार्ड दस बार की ओलिंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में हराकर पहला पदक पक्का किया लेकिन पुरुष टीम पहले दौर में बांग्लादेश से हार गई।

भारतीय महिला रिकर्व टीम ● आइएएनएस

महिला टीम की सदस्यों दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से मात दी। अब उसका सामना स्वर्ण पदक के मुकाबले में रविवार को चीन से होगा। पुरुष रिकर्व टीम में तरूणदीप राय, धीरज बोम्मादेवरा और यशदीप भोगे थे जिन्हें बांग्लादेश ने 6-2 से मात दी। भारतीय महिला टीम ने लगातार तीन मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने छह तीरों में से चार पर 10 स्कोर किया और सिर्फ दो अंक गंवाकर पहला सेट 58-55 से जीता। दूसरे सेट में मुकाबला 56-56 से बराबर रहा लेकिन भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली। मैच जीतने के लिए अब सिर्फ दो अंक की जरूरत थी और अगला सेट भारत ने 58-56 से अपने नाम किया। लेकिन कोरिया ने यहां अनुभवहीन टीम भेजी है क्योंकि उसका फोकस चार महीने बाद जापान में होने वाले एशियाई खेलों पर है। कोरियाई टीम में दो नए चेहरे ली युंजी और ओ येजिन थे जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन कांग चाएयंग एकमात्र अनुभवी तीरंदाज थी। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने उजबेकिस्तान को पहले दौर में 6-2 (53-56, 57-54, 55-54, 55-51) से हराया।

डेंबेले ने पीएसजी को दिलाया फाइनल का टिकट, बायर्न हुआ बाहर

म्यूनिख, एपी: गत चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने बुधवार रात ओस्मान डेंबेले के गोल की बदौलत बायर्न म्यूनिख से 1-1 से ड्रा खेलकर चैपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। अब फाइनल में 30 मई को पीएसजी का सामना आर्सेनल से होगा, जिसने मंगलवार रात एटलेटिको मैड्रिड को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। आर्सेनल 2006 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है, हालांकि वह अभी तक यह खिताब नहीं जीत सका है, जबकि पीएसजी पिछले साल इंटर मिलान को हराकर चैंपियन बना था।

पीएसजी और बायर्न के मुकाबले में ओस्मान डेंबेले ने तीसरे ही मिनट में गोल दाग दिया। मिडफील्ड में फेबियन रुइज के साथ एक आसान पास खेलने के बाद ख्विचा क्वारात्सखेलिया तेजी से आगे बढ़े और बिना किसी रोक-टोक के डेंबेले को गेंद पास की, इसे डेंबेले ने गोल में बदल दिया। हैरी केन ने स्टापेज टाइम में बायर्न के लिए गोल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केन का इस सीजन में यह 55वां गोल रहा। मुकाबले में बायर्न ने गेंद पर ज्यादा कब्जा बनाए रखा, वहीं पीएसजी ज्यादा असरदार साबित हुआ। हाफ टाइम के बाद डोए और क्वारात्सखेलिया ने बायर्न के गोलकीपर मैनुअल न्यूयर को लगातार चौकन्ना रहने पर मजबूर किया। इस मुकाबले में पीएसजी ने बायर्न की बेहद आक्रमक पंक्ति- केन, लुइस डियाज और माइकल ओलिसे को काफी हद तक रोके रखा। हालांकि इस पंक्ति ने ही पीएसजी के डिफेंस को पिछले हफ्ते पेरिस में चार बार भेदा था, लेकिन खुद भी पांच गोल खाए थे। इस हार के साथ बायर्न का एक ही सत्र में बुंडेसलीगा, जर्मन कप और चैंपियंस लीग जीतने का सपना टूट गया। पीएसजी के अध्यक्ष नासिर अल-खेलाइफी ने कहा कि यह शानदार है। मैंने खिलाड़ियों से कहा है कि हम योद्धा हैं। गत चैंपियन पीएसजी ने बायर्न के विरुद्ध औसत के आधार पर 6-5 से यह जीत दर्ज की है। उसने पेरिस में पिछले सप्ताह बायर्न के विरुद्ध पहले चरण का मुकाबला 5-4 से जीता था। अब 30 मई को हंगरी के बुडापेस्ट में आर्सेनल और फ्रेंच लीग में भी सबसे आगे चल रहे पीएसजी के बीच इस टूर्नामेंट की खिताबी भिड़ंत होगी। आर्सेनल एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर और कुल मिलाकर 2-1 से जीत के साथ फाइनल में पहुंचा है।

सेमीफाइनल के दूसरे लेग में पीएसजी ने म्यूनिख से 1-1 से ड्रा खेलकर फाइनल में बनाई जगह

चैंपियंस लीग के हाल के विजेता

वर्ष	क्लब
2025	पीएसजी
2024	रीयल मैड्रिड
2023	मैनचेस्टर सिटी
2022	रीयल मैड्रिड
2021	चेल्सी

मुकाबले में बायर्न म्यूनिख के विरुद्ध गोल करते पीएसजी के डेंबेले (दाएं) ● एपी

सुपर रैपिड में गुकेश ने वेसले सो से खेला ड्रा

वारसा, प्रेट्र: डी गुकेश ने विश्व चैंपियनशिप मुकाबले की तैयारियां पुख्ता करते हुए सुपर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में अपने चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव को पांचवें दौर में हराया और अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेसले सो को ड्रा पर रोका।

उजबेकिस्तान के सिंदारोव को हराने के बाद गुकेश ने वेसले सो को ड्रा पर रोका। अब उनके छह अंक हो गए हैं जबकि रैपिड वर्ग में तीन राउंड बाकी हैं। सिंदारोव के विरुद्ध जीत से उन्हें दो अंक मिले जबकि ड्रा से एक अंक हासिल हुआ। सो नौ अंक लेकर अमेरिका के ही हैंस नीमैन के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद ब्लादीमिर फेडोसीव हैं जो एक अंक पीछे हैं।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 8 मई, 2026

दिल से

सबको पता है अपनी सच्चाई

आज प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज 'लुक्खे' में श्रेय न लेने की बात कहती नजर आ रहीं पलक तिवारी वास्तविक जीवन में भी मानती है यह बात। मां श्वेता तिवारी जैसा बनने की इच्छुक पलक ने प्रियंका सिंह के साथ साझा किए जज्बात...

जिस क्षेत्र में माता-पिता स्थापित होते हैं, उसी क्षेत्र में आने वाले बच्चों पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव बना रहता है। हालांकि अभिनेत्री पलक तिवारी पर अपनी मां व अभिनेत्री श्वेता तिवारी का ऐसा कोई दबाव नहीं है। मदर्स डे के मौके पर पलक कहती हैं, 'मुझे कभी नहीं लगा कि मम्मी के अभिनय की विरासत को मैं आगे लेकर जाऊंगी। ना मैं वो बोझ लेकर चली हूं, ना उन्होंने मुझ पर कभी वो बोझ डाला है। मेरी मां की असली विरासत ये नहीं है कि वो एक कलाकार हैं, उनकी विरासत वह स्वयं है। कलाकार के तौर पर मुझको अपने दम पर जैसा मैं चाहती हूं, वैसी अभिनेत्री बनना है। मैंने काम कैसा किया है, मैं सही जा रही हूं या नहीं, इसके लिए आज भी मुझे अपने जीवन में केवल तीन लोगों से ही मान्यता चाहिए, उसमें सबसे पहले मेरी मां हैं, बाकी दो मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूं। अगर वह तीनों कहते हैं कि मैं फलां जगह गलत हूं, तो मुझे फिर टेंशन हो जाती है कि सब कुछ सही कैसे करूं।'

'लुक्खे' का पोस्टर

पलक आज (आठ मई) अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज 'लुक्खे' में अहम रोल में नजर आएंगी। इस सीरीज के एक सीन में पलक का पात्र कहता है- 'मुझे क्रेडिट (श्रेय) मत दिया करो, अजीब लगता है।' वास्तविक जीवन में अपने काम का श्रेय लेना पलक को कितना अहम लगता है? इस पर वह कहती हैं, 'मुझे तो लगता है कि इस इंडस्ट्री में हर कोई अपने काम का श्रेय पाने के लिए भाग रहा है। हालांकि मैं श्रेय नहीं मांगती हूं, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर वह मिलना होगा, तो मिल जाएगा। अपना सच हर किसी को पता होता है कि कितनी मेहनत की है। जरूरी यह है कि मैं खुद को अपनी मेहनत का श्रेय दे रही हूं या नहीं।'

@palaktiwarii (इंस्टा)

सिनेमा के पास मां है

मदर्स डे (10 मई) विशेष

हिंदी सिनेमा ने मां के किरदार को हमेशा सजाया-सराहा है। एक समय था जब मां नायक या नायिका को इस काबिल बनाती थी कि वह कहानी की दिशा मोड़ देता था, आज स्वयं मां ही मुख्य किरदार है। इस किरदार को निभाने वाली नायिकाओं के सामने आने वाली चुनौती और अनुभव पर स्मिता श्रीवास्तव का आलेख...

पिछले कुछ वर्षों से सिनेमा में मां की छवि केवल त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अधिकार और अस्तित्व के लिए लड़ने वाली सशक्त स्त्री के रूप में सामने आती है। 'निल बटे सन्नाटा' में एक मां अपनी बेटी के भविष्य के लिए खुद पढ़ाई करती है वहीं 'पा', 'मिमी', 'पंगा', 'तरला' जैसी फिल्में मां के संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल बनकर उभरती हैं। इन फिल्मों में समानता यह है कि मां ही कहानी का केंद्र बनकर उभरती है।

'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' में रानी मुखर्जी

'निल बटे सन्नाटा' का दृश्य

मां ने दी ताकत

सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे' में रानी मुखर्जी एक ऐसी मां की भूमिका में दिखीं, जो अपने बच्चों को वापस पाने के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। रानी के मुताबिक, 'यह फिल्म मेरे पास उस समय आई थी जब मिसकैरिज के कारण मैंने अपना दूसरा बच्चा खो दिया था। उस वक्त मेरे भीतर अपनी संतान को खोने का एहसास बहुत गहरा था। जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी, तो मैं उससे इतनी जुड़ गई कि मुझे लगा यह कहानी मुझे लोगों तक पहुंचानी है। इस भूमिका को निभाने को लेकर मैंने प्रेरणा अपनी मां से ली। चाहे हमें अपने हाथों से खाना खिलाना हो या हमारे माथे पर टीका लगाना, मैंने अपनी मां से ही ताकत और प्रेरणा ली।'

मजबूत बनी मां बनकर

अभिनेत्री कृति सैनन ने फिल्म 'मिमी' में एक सरोगेट मां का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, लेकिन इस फिल्म को स्वीकार करने से पहले उन्हें कई तरह की सलाहें मिली थीं। कृति के मुताबिक, 'जब 'मिमी' मेरे पास आई, तो बहुत से लोगों ने सलाह दी कि इतनी कम उम्र में स्क्रीन पर मां का रोल क्यों कर रही हो। यह सरोगेसी पर आधारित फिल्म है। अभी करियर की शुरुआत में आर्ट फिल्में मत करो। तुम 15 किलोग्राम वजन बढ़ा रही हो, यह अच्छा नहीं लगेगा। आगे दूसरे काम कैसे करोगी? इसके बावजूद मैंने जोखिम लिया और साबित किया कि मजबूत कहानियां कलाकारों को नई पहचान देती हैं। मुझे लगता है कि ऐसा मौका बहुत बार नहीं मिलता।'

'पा' के दृश्य में विद्या बालन व अमिताभ बच्चन

'मिमी' का पोस्टर

सुनी तो बस दिल की

इसी तरह विद्या बालन ने फिल्म 'पा' में हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई, जो शुरुआत में उन्हें बेहद आसामान्य लगा। विद्या ने बताया भी था कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि इतनी कम उम्र में अपने से बड़े अभिनेता की मां का किरदार निभाने से उनका करियर प्रभावित हो सकता है। हालांकि इस फिल्म के निर्देशक आर. बाल्की से स्क्रिप्ट सुनने के बाद विद्या ने सिर्फ अपने दिल की सुनी और इस फिल्म को करने का जोखिम उठाया। विद्या मानती हैं कि एक कलाकार के लिए अपने भीतर की आवाज सुनना जरूरी है, न कि केवल बाहरी सलाहों पर निर्भर रहना। इस फिल्म के लिए सराहना बटोरने के साथ उन्हें कई अवार्ड मिले।

'पंगा' के दृश्य में कंगना रनौत

इसी तरह कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'पंगा' दर्शाती है कि मां बनने के बाद भी महिला के सपने खत्म नहीं होते। मां होना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पहचानने और उसे जीने की यात्रा भी है।

सही मायने में मां की असली ताकत उसकी संवेदनशीलता के साथ अटूट साहस में भी निहित है। यही परिवर्तन इन भूमिकाओं को खास बनाता है और मां के अदम्य साहस को सलाम करता है।

चलते-चलते

घर बैठे नहीं मिलता काम

सही समय पर सही जगह पहुंचने के साथ अपने करियर की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं अभिनेता विजयंत कोहली। आज भी आडिशन और रिजेक्शन को अपने ही अंदाज में स्वीकारते हैं विजयंत...

अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, जब तक अच्छे मौके न मिल जाएं। 'बैड्स आफ बालीवुड', 'मामला लीगल है' समेत कई वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता विजयंत कोहली का कहना है कि घर बैठे कलाकार को काम नहीं मिलता है, उसे काम की जगह पर मौजूद रहना होता है। वे बताते हैं, 'मैं आज भी आडिशन देने से हिचकिचाता नहीं हूं। कई आडिशन अपने दोस्तों-यारों के लिए करता हूं। कई बार आडिशन वो काम दिला देता है, जिसके बारे में सोचा नहीं होता है। अब जैसे एक विज्ञापन में 32 साल के पिता का रोल था। मुझे आडिशन देने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि मैं 45 साल का हूं, क्यों आडिशन मांग रहे हैं, लेकिन उनको भी तो बताना होता है कि हमारे पास इतने कमाल के एक्टर हैं, जो हमारे कहने पर आडिशन देते हैं। जब मेरा आडिशन भेजा गया, तो वह उन्हें इतना पसंद आया कि क्रिएटिव बदलकर 45 साल के पिता का कर दिया गया। आडिशन देने का वही मजा है। एक बार एक छोटे से रोल का आडिशन भी किया, मैं वैसे करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया कि दूसरे कलाकारों को दिखाएंगे कि ऐसे आडिशन देना है। जब वह आडिशन निर्देशक के पास पहुंचा, तो उन्होंने सीधे मुझे लीड निगेटिव रोल दे दिया।' इन दिनों विजयंत के सितारे बुलंदी पर हैं। वह कई बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इसे लेकर विजयंत कहते हैं, 'माता-पिता का आशीर्वाद है, सही जगह पर सही समय पर पहुंच गया था। मुझे इस इंडस्ट्री में संघर्ष और रिजेक्शन कम झेलने पड़े हैं। आज रोल और फिल्में दोनों बड़ी मिल रही हैं। जहां तक रिजेक्शन की बात है, तो जब सुनता था कि मेरा नहीं हुआ, तो बुरा लगता था। मैं एक फिल्म भी करना चाह रहा था, वह नहीं मिली तो बुरा लगा था। जब मैंने उसे फाइनली देखा, तो समझ आया कि निर्देशक का विजन कुछ और था, जो कद-काठी चाहिए थी, वह मेरी नहीं थी।'

@vijayantkohli (इंस्टा)

प्रियंका सिंह

मनोरंजन के हर अपडेट और अधिक खबरों के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।

सीधी बात

सबसे जरूरी है जुनून

सपनों को पूरा करते हुए वास्तविकता के धरातल पर बने रहने वाले वरुण बडोला अपनी मजबूती के लिए मां को देते हैं श्रेय...

हर सफर की शुरुआत सपनों से होती है, लेकिन उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनुशासन, समर्पण और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। खासकर उस दौर में, जब आकर्षण और भटकाव बार-बार सामने आते हैं। अपने करियर की शुरुआत से अभिनेता वरुण बडोला ने इसका ध्यान रखा। वह हाल ही में रिलीज हुई 'अनदेखी' सीरीज के चौथे सीजन 'अनदेखी: द फाइनल बैटल' में नजर आए हैं। अपने करियर में किन चीजों की अनदेखी नहीं की? के जवाब में वरुण कहते हैं, 'सबसे पहले अपने कमिटमेंट और जुनून का जिक्र जरूरी है। मुझे हमेशा से लगता था कि जितना आना चाहिए, जितना तैयार होना चाहिए, मैं उतना नहीं हूं। मैं दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाता था। मुझे डर रहता था कि कहीं मैं सिर्फ पार्टी करता रह जाऊं और कोई बहुत जरूरी चीज मेरे सामने से निकल जाए। जब मैं नया-नया आया था, तब मेरे अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं और आकर्षण थे, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मैं अपने कमिटमेंट और अपने पैशन (जुनून) के साथ कोई कोताही नहीं करूंगा।'

@badolavarun (इंस्टा)

मदर्स डे को लेकर वरुण कहते हैं, 'घर में हम सबको संभालकर रखना, अनुशासन में रखना यह काम मां का ही था। आपके व्यक्तित्व को आकार देना, धैर्य रखना और जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी मैंने मां से सीखा। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत हूं तो वह सारी चीजें मां की वजह से हैं। मेरी माता जी आज एक बेहतरीन रिटायर लाइफ जी रही है। फिलहाल मुंबई में हैं। दिल्ली में भी हमारा घर है जब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती है, तो वो वहां वक्त बिताती हैं। हमारी साल की एक छुट्टी होती है तब हमारा पूरा परिवार साथ होता है।'

स्मिता श्रीवास्तव

आज का भविष्यफल- 8 मई, 2026 शुक्रवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी। **राहुकाल:** प्रात: 10:30 बजे से 12 बजे तक। **दिशाशूल:** पश्चिम **भद्रा:** दोपहर 12:23 बजे से रात्रि 01:13 बजे तक। **विशेष:** शुक्र मंगल के नक्षत्र मृगसिरा में।

कल 9 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल: पूर्व
विशेष: महापंचक (रात्रि 11:25 बजे से प्रारंभ 14 मई को रात्रि 10:34 बजे पर समाप्त)
विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी 14 घंटे 04 मिनट तक, तत्पश्चात अष्टमी श्रवण नक्षत्र 23 घंटे 25 मिनट तक, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र शुक्ल योग 26 घंटे 36 मिनट तक, तत्पश्चात ब्रह्म योग, मकर में चंद्रमा।

मेष: शासनसत्ता का सहयोग रहेगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।

वृष: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सत्ता से सहयोग मिलेगा।

मिथुन: बजट बिगड़ सकता है। उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। मातृ पक्ष से कष्ट मिलेगा।

कर्क: रिश्तों में निकटता रहेगी। साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।

सिंह: अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कन्या: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होगा। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।

तुला: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।

वृश्चिक: दूसरे का सहयोग लेने से सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्यों में संतुष्टि होगी।

धनु: आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मकर: बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में सफल होंगे।

कुंभ: धन व्यय पर नियंत्रण रखें। अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। सेहत के प्रति सचेत रहें।

मीन: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वर्ग पहेली-3328

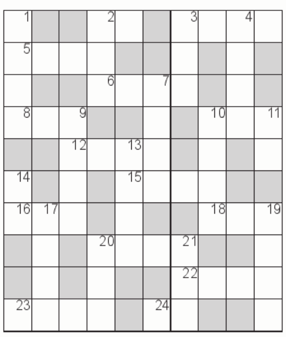

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं:-
2. सिद्धांत, मत (2)। 3. संतोष की बात (4)।
5. देवता-ऋषि आदि से प्राप्त वर (4)। 6. वाल्मिकी मुनि का पहला नाम (4)। 8. अदब, कायदा (3)।
10. परिहास, विनोद (3)।
12. इन्कार करना, मना कर देना (4)। 15. पुलकित (4)। 16. सभा, समाज (3)। 18. मन से उत्पन्न, कामना (3)। 20. हठात, एकाएक (4)। 22. भेंट, साक्षात्कार (4)।
23. जल्दी-जल्दी, तेजी से (4)।
24. इज्जत, सम्मान (2)।

ऊपर से नीचे:-
1. स्थिर, ठहरा हुआ (4)।
2. बंदर, मर्कट, कपि (3)। 3. बगावत, विद्रोह (3)।
4. अनुभव, आत्मसात (4)।
7. मधुर ध्वनि, कलहंस (4)।
9. किंवदंती (4)। 10. हमेशा, सर्वदा, नित (4)।
11. कलाबाजी दिखाने वाली एक जाति (2)। 13. घिसना, पीसना (4)।
14. निकट, नजदीक (2)।
17. पलकों का झपकना (4)।
19. मर्म, प्रकृति, सारांश (4)।
20. ज्ञान शून्य, अविवेक (3)।
21. समंदर, सागर (3)।

कल का हल

आ	च	र	ण		उ	प	यो	गि	ता
धा		हि			त				ना
र		त	मां	ह	र		त	मा	शा
स्तं			ह		न	जा	रा		ह
भ	ठि	या	रा				श		
		ता				अ	ना	चा	र
का		या	त	ना		क			फू
द	डि	त		प	क	ड़	ना		च
बि				तौ			गि		क्क
नी	ल	क	म	ल		बु	न	क	र

सुडोकू-3328

		6		8			7	
	3			7			5	
2		7			5			1
		3		2		9		
1	4			3			6	2
			7					
9				4	3	1		8
	2	8	1		7		9	6
	1	4		9			3	

कल का हल

9	5	1	6	3	4	2	8	7
3	2	6	5	8	7	4	9	1
4	7	8	9	2	1	3	6	5
8	1	3	7	6	2	9	5	4
2	4	7	8	9	5	1	3	6
5	6	9	4	1	3	8	7	2
7	3	4	1	5	8	6	2	9
6	8	5	2	4	9	7	1	3
1	9	2	3	7	6	5	4	8

राष्ट्रीय फलक

वापस मंगवानी पड़ी किन्नौर को ट्रांसजेंडर और मंडी को मार्केट लिखी किताबें

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

- शिक्षा सचिव ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड को दिया आदेश
- इस साल छपी सभी किताबों की जांच करेगी विशेष समिति

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग को छठी कक्षा की लोक संस्कृति और योग पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में हुई त्रुटियों के चलते हजारों किताबें वापस मंगवानी पड़ी हैं। इन पुस्तकों में अनुवाद संबंधी घोर लापरवाही सामने आई है। हिमाचल के किन्नौर जिले का अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसजेंडर और मंडी को मार्केट लिखा गया है।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन पुस्तकों को वापस मंगवाने के निर्देश दिए। अब बोर्ड को नए सिरे से इस पुस्तक की प्रिंटिंग करवानी होगी। सचिव ने यह भी आदेश दिया है कि इस वर्ष जितनी भी किताबों की छपाई की गई है, उन सभी की जांच की जाए। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। छठी कक्षा की किताब में प्रदेश में जिलों के गठन से संबंधित प्रश्न में किन्नौर जिले का गलत अनुवाद ट्रांसजेंडर किया गया है, जबकि इसी पुस्तक के हिंदी संस्करण में किन्नौर शब्द सही लिखा है। इसी तरह, मंडी जिले का अनुवाद मार्केट के रूप में किया गया है। इसको लेकर काफी विवाद सामने आया है। शिक्षा सचिव ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। प्रारंभिक जांच में गलती का कारण मशीनी अनुवाद माना जा रहा है। शिक्षा बोर्ड ने कक्षा छह के लिए ऐसी करीब 65 हजार किताबें छपवाई हैं।

बोर्ड ने किताबों को दोबारा से छपवाने का निर्णय लिया है। सभी स्कूलों से ये किताबें वापस मंगवा ली गई हैं।
- विशाल शर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

केदारनाथ धाम में वर्षा व बर्फबारी के चलते पांच हजार यात्री पड़ावों पर रोके

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

- दोपहर बाद हेली सेवा का भी नहीं हुआ संचालन, गौरीकुंड व सोनप्रयाग समेत पैदल मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर रोके गए हैं यात्री क्रासर
- मौसम अनुकूल होने पर दी जाएगी यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति
- गुरुवार को किए 17 हजार से अधिक यात्रियों ने बाबा के दर्शन

केदारनाथ धाम में बर्फबारी। फाइल

भारी वर्षा व बर्फबारी केदारनाथ यात्रा की राह में चुनौती बनती जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने गुरुवार दोपहर बाद केदारनाथ जाने वाले और वहां से लौट रहे पांच हजार से अधिक यात्रियों को गौरीकुंड व सोनप्रयाग समेत पैदल मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया। इसके अलावा दोपहर बाद धाम के लिए हेली सेवा का संचालन भी नहीं हुआ। हालांकि, गुरुवार को 17 हजार से अधिक यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारु है।

प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा मार्ग से जुड़े सभी सेक्टर प्रभारियों, नोडल अधिकारियों व पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यात्रियों को संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आगे न बढ़ने दिया जाए। उन्हें निकटतम सुरक्षित स्थानों और होल्डिंग एरिया में ठहराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मौसम सामान्य होने पर ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाए। केदारनाथ पैदल मार्ग में वर्षा के कारण फिसलन बढ़ गई है। मार्ग कई स्थानों पर खतरनाक हो गया है। इसके चलते यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी रखने, यात्रियों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक करने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपदा परिचालन केंद्र को देने के लिए कहा गया है।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है वे मौसम संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें। उत्तराखंड में छह दिन से बर्फबारी, वर्षा व ओलावृष्टि का क्रम जारी है।

नानी को भी नाबालिग के गुजारे भत्ते के लिए याचिका दायर करने का अधिकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- हाई कोर्ट का निर्णय, संरक्षक बच्चे के लिए मांग सकता है रखरखाव भत्ता

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि नाबालिग बच्चा अपनी नानी की वास्तविक देखरेख में है, तो नानी भी उसकी ओर से गुजारे भत्ते के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने कहा कि बच्चे के वैधानिक अधिकार को केवल इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि याचिका उसकी मां द्वारा दाखिल नहीं की गई। वास्तविक देखभाल करने वाला संरक्षक बच्चे के लिए रखरखाव भत्ता मांग सकता है। जस्टिस नीरजा के काल्सन ने अपने निर्णय में कहा कि जब वैवाहिक संबंध टूट चुके हों और नानी वास्तव में बच्ची की परवरिश, देखभाल और खर्चा उठा रही हो, तो उसे नाबालिग के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने दो टूक कहा कि यह अधिकार नानी के व्यक्तिगत दावे पर आधारित नहीं, बल्कि बच्चे के वैधानिक अधिकार की सुरक्षा पर आधारित है। हाई कोर्ट ने पिता की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिका केवल मां ही दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रविधान का उद्देश्य परित्याग और अभाव से सुरक्षा देना है, इसलिए इसे संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।

मामले में पिता ने यह भी तर्क दिया था कि तलाक के समय एकमुश्त समझौते के तहत मां को दी गई राशि में बच्चे के लिए भी हिस्सा शामिल था, इसलिए बाद में अलग से गुजारा भत्ते का दावा नहीं बनता। अदालत ने कहा कि बच्चे का गुजारा भत्ते का अधिकार स्वतंत्र, सतत और गतिशील है, जिसे माता-पिता के निजी समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार, 08 मई, 2026
आजकल
14
www.jagran.com

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन की घोषणा की

1980 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि दुनिया चेचक (स्माल पाक्स) से मुक्त हो गई है। यह मानव इतिहास में पहली और एकमात्र संक्रामक बीमारी है जिसे पूरी तरह से समाप्त किया गया है। इसने दुनियाभर में करोड़ों लोगों की जान ली थी।

रेनहोल्ड व हाबेलर ने बिना पूरक आक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई की

1978 में आज ही इतालवी और आस्ट्रियाई पर्वतारोहियों रेन्होल्ड मेसनर और पीटर हाबेलर ने आक्सीजन की आपूर्ति के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई से पहले, पूरक आक्सीजन के बिना एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना असंभव माना जाता था।

उत्कल मणि के नाम से जाने जाते थे स्वतंत्रता सेनानी गोपबंधु चौधरी

गोपबंधु चौधरी का जन्म 1895 में आज ही ओडिशा में हुआ था। 1921 में उप मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देकर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया व ओडिशा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और कई बार जेल गए। 1935 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1934 में जगतसिंहपुर में सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित करने के लिए 'अलाका आश्रम' की स्थापना की। गांधीजी के सुझाव पर बारी में ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए एक केंद्र बनाया। स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन से जुड़ गए।

साइलेंट संकेतों को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

विश्व ओवेरियन कैंसर डे ▸ पेट फूलना, पीरियड्स दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के संकेत

अनूप कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली : महिलाओं का पेट फूलना, गैस, जल्दी पेट भर जाना, भूख कम लगना, लगातार थकान या पीरियड्स दर्द को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। क्योंकि यह ओवेरियन (अंडाशय) कैंसर के आरंभिक लक्षण हो सकते हैं। पर, अधिकतर महिलाएं इन्हें सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, यही वजह है कि देश में बड़ी संख्या में महिलाओं में यह कैंसर महिलाओं में बीमारी एडवांस स्टेज में पकड़ में आती है।

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं क्लिनिकल हेड आंकोलाजी नेटवर्क डा. हरित चतुर्वेदी ने बताया कि ओवेरियन कैंसर को 'साइलेंट किलर' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आरंभिक संकेत बेहद सामान्य दिखाई देते हैं। उन्होंने कहाकि महिलाओं को लगातार बने रहने वाले पेट संबंधी लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और समय रहते जांच करानी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती जीवनशैली, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और नियमित स्वास्थ्य जांच की कमी इसके बढ़ते मामलों की बड़ी वजह बन रही है। उनके अनुसार भारत में हर साल ओवेरियन कैंसर के लगभग 47 हजार नए मामले सामने आते हैं, जबकि दिल्ली में 2200 महिलाएं हर वर्ष इससे प्रभावित होती हैं।

प्रतीकात्मक

शारदा केयर हेल्थसिटी के सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल आंकोलाजी : डा. अनिंद्य मुखर्जी ने बताया कि आरंभिक स्तर पर पहचान न होना इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती है। पेट दर्द, गैस, सूजन या भूख कम लगने जैसे लक्षण अक्सर सामान्य पाचन समस्या या पीरियड्स से जोड़ दिए जाते हैं, जिससे मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं और उपचार जटिल हो जाता है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि यदि पेट फूलना, लगातार दर्द, जल्दी पेट भरना या असामान्य थकान जैसे लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। क्योंकि जागरूकता और समय पर जांच ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

क्या होता है ओवेरियन कैंसर : यह महिलाओं के अंडाशय में होने वाली गंभीर बीमारी है। अंडाशय शरीर में अंडाणु बनाने का काम करते हैं। जब यहां की कोशिकाएं असामान्य तरीके से तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो यह कैंसर बन जाता है। यह बीमारी बढ़ती उम्र, पारिवारिक इतिहास, हार्मोनल बदलाव, मोटापा और खराब जीवनशैली जैसी वजहों से हो सकती है। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य लगते हैं, इसलिए अक्सर लोग इसे देर से पहचान पाते हैं।

इधर-उधर

एआइ से लिखी गई राष्ट्रीय एआइ नीति करनी पड़ी रद

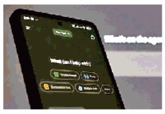

नीति में काल्पनिक संदर्भों का किया गया था इस्तेमाल • सांकेतिक फोटो

केपटाउन, एजेंसी: पिछले महीने, दक्षिण अफ्रीका के संचार मंत्री साली मलात्सी ने घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रीय एआइ नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि नीति की कुछ सामग्री एआइ द्वारा लिखी गई थी, जिसमें ऐसे लेखों का उल्लेख था जिनका अस्तित्व नहीं था। मलात्सी ने कहा कि एआइ द्वारा तैयार संदर्भों को उचित सत्यापन के बिना शामिल किया गया। इसने नीति के मसौदे की अखंडता व विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।

पेट पर कम चर्बी मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की धीमी प्रक्रिया की निशानी

अनुसंधान

शोध से पता चला कि मध्य आयु में पेट पर कम चर्बी मस्तिष्क के टिश्यू के सिकुड़ने (एट्रोफी) की गति में कमी की निशानी है। यह मस्तिष्क की प्रमुख संरचनाओं के संरक्षण और मध्य आयु के उत्तरार्ध में बेहतर बौद्धिक क्षमता से जुड़ा है। इस उम्र की 533 महिलाओं और पुरुषों के मस्तिष्क और पेट के एमआरआइ स्कैन का विश्लेषण किया गया, जिन पर 16 वर्षों तक नजर रखी गई।

इस अवधि के दौरान बौद्धिक क्षमता के मूल्यांकन के साथ-साथ आंतरिक वसा और मस्तिष्क संरचनाओं के बार-बार एमआरआइ माप किए गए। इसका निष्कर्ष नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया। निष्कर्ष बताते हैं कि पेट की चर्बी और मस्तिष्क की उम्र बढ़ने के बीच का संबंध मुख्य रूप से ग्लूकोज नियंत्रण और इंसुलिन संवेदनशीलता के माध्यम से होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह अध्ययन पेट पर जमी चर्बी (आंतरिक फैट) के बार-बार एमआरआइ-आधारित मापों को मस्तिष्क की उम्र बढ़ने और बौद्धिक क्षमता के ट्रैजेक्टरी से जोड़ने वाला पहला अध्ययन है। प्रमुख शोधकर्ता आइरिस शाई ने कहा, "निष्कर्ष बताते हैं कि ग्लूकोज नियंत्रण और पेट की आंतरिक चर्बी को कम करना मध्य आयु में मापने योग्य, परिवर्तनीय और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं, जिनमें मस्तिष्क के क्षरण को धीमा करने और बौद्धिक गिरावट के जोखिम को कम करने की वास्तविक क्षमता है। (प्रेट्र)

वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर विशेष

थैलेसीमिया मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद हाफ-मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : थैलेसीमिया जैसे गंभीर रक्त रोग से जूझ रहे बच्चों के लिए हाफ-मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर मरीजों के लिए यह उपचार बीमारी से स्थायी राहत देने वाला विकल्प साबित हो रहा है। हाफ-मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट ने उन मरीजों की उम्मीद बढ़ाई है, जिन्हें पूरी तरह मैच करने वाला डोनर नहीं मिल पाता। हाफ-मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 50 प्रतिशत एचएलए-मैच वाले परिजन से स्टेम सेल देकर मरीज का इलाज किया जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में छह हजार से अधिक थैलेसीमिया के मरीज हैं, वर्ष 2025 में थैलेसीमिया के पंजीकृत मरीजों की संख्या 4,361 थी। जिनमें 2,579 बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। राजधानी में चार हजार के करीब मरीज नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर हैं। इंडियन सोसायटी फार ब्लड एंड मैरो ट्रांसप्लांटेशन (आइएसबीएमटी) के अनुसार देशभर में हर साल करीब 40 हजार मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। दिल्ली में करीब 3,200 मरीजों को प्रतिवर्ष इसकी आवश्यकता होती है।

फिल्म रिव्यू

पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)

मुख्य कलाकार: सिद्धार्थ गुप्ता, जैकी श्राफ, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट्ट, निवाशिनी कृष्णन
निर्देशक: हार्दिक गज्जर
अवधि: दो घंटे 29 मिनट

श्रीकृष्ण के कोमल हृदय और विराट स्वरूप की कहानी

कृष्ण किसी के नहीं, जो पुकारे उसी के हैं... द्वापर युग में जन्मे भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण का जन्म करुणा, प्रेम और कर्मयोग का प्रतीक है। उनकी लीलाओं व जीवनयात्रा को इस फिल्म में समेटने का सफल प्रयास निर्देशक ने किया है।

फिल्म की कहानी शुरू होती है भालका तीर्थ से, जहां श्रीकृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। वहां से कहानी वर्ष 2026 के जगन्नाथ पुरी मंदिर में आती है। माना जाता है कि वहां श्रीकृष्ण की मूर्ति में उनका दिल धड़कता है। स्वामी जी (जैकी श्राफ) जब यह कथा सुनाते हैं तो आज के दौर का एक लड़का इस पर सवाल उठाता है तो स्वामी जी उसे पूरी कथा सुनाते हैं। फिर कहानी द्वापर युग में जाती है, जहां श्रीकृष्ण (सिद्धार्थ गुप्ता) गोकुल से निकलकर वृंदावन बसाते हैं, द्वारका जाकर द्वाराकाधीश बनते हैं, बरसाना में राधा (सुष्मिता भट्ट) से प्रेम तथा रुक्मिणि (निवाशिनी कृष्णन) और सत्यभामा (संस्कृति जयना) से विवाह करते हैं और फिर अधर्म के विरुद्ध आरंभ हुई महाभारत का हिस्सा बनते हैं।

तीन भाग में बनने वाली इस फिल्म के लेखकों प्रकाश कपाड़िया, राम मोरी और हार्दिक गज्जर ने श्रीकृष्ण के जीवन को पटकथा में खूबसूरती से ढाला है। हर युग में विष्णु अवतार के पुराने वचनों को निभाना, धर्म की स्थापना के लिए बंसी छोड़कर शस्त्र उठाना, सखी द्रौपदी के साथ उनका सखा प्रेम जैसे कई दृश्य हैं। निर्देशक श्रीकृष्ण की जिंदगी को खूबसूरत रंगों से सराबोर पेंटिंग की तरह प्रस्तुत करते हैं। इसमें उन्हें सिनेमैटोग्राफर अयानंका बोस और कास्ट्यूम डिजाइनर निधि यशा का साथ मिला है।

कृष्णलीला के अनेक प्रश्नों के उत्तर देती है फिल्म चित्र सौ. : फिल्म टीम

भामा का नाम सत्यभामा क्यों पड़ा, श्रीकृष्ण को देखे बिना रुक्मिणी को प्रेम कैसे हो गया, राधा का नाम श्रीकृष्ण से पहले क्यों लिया जाता है, उनकी सोलह हजार रानियां होने के पीछे क्या कारण हैं, कृष्ण अपना हृदय दुनिया को क्यों दे गए, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर फिल्म देती है। ग्राफिक्स के जरिये कृष्ण जन्म, कारावास से गोकुल का सफर, गोवर्धन धारण, कालिया दमन, माखन चोरी समेत कई बाललीलाओं को दर्शाने का आइडिया काम करता है। श्रीकृष्ण जब द्रौपदी को उनके मांगे हुए वरदान पर तथास्तु कहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

फिल्म मध्यांतर से पहले धीमी है, कुछ लंबे-लंबे दृश्यों और गानों को एडिट किए जाने की संभावना थी। मन में कुछ प्रश्न भी उठेंगे, लेकिन उनके उत्तर हो सकता है कि आगे के दो पार्ट में हों, क्योंकि यह ट्रायोलाजी फिल्म है।

इरशाद कामिल के बोल, प्रसाद एस का संगीत व बैकग्राउंड स्कोर कर्णप्रिय है। कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी..., प्रेम की लीला..., कुंजबिहारी नैनों तो सोहे... गीत याद रह जाते हैं। अभिनय की बात करें तो सिद्धार्थ गुप्ता, श्रीकृष्ण के नटखट, निश्छल, प्रेमी, युद्धनीतिज्ञ जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाने में सफल रहे हैं। सत्यभामा के रोल में संस्कृति जयना को कई भावनाओं को जीने का अवसर मिला है। राधा की भूमिका में सुष्मिता भट्ट मन मोहती हैं। रुक्मिणी के दृढ़निश्चयी व्यक्तित्व में निवाशिनी कृष्णन जंचती हैं।

प्रियंका सिंह

उत्कृष्ट बहुत अच्छी अच्छी औसत औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं: feature@jagran.com

स्क्रीन शाट

एक और हालीवुड फिल्म रीसेट करेंगी प्रियंका चोपड़ा

फिल्म वाराणसी से भारतीय सिनेमा में लंबे समय बाद दिखेंगी प्रियंका। फाइल

हिंदी सिनेमा की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ वर्षों से लगातार हालीवुड में भी अपने काम का लोहा मनवा रही हैं। करीब सात साल बाद वह एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म वाराणसी से भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही है। कुछ और हिंदी फिल्मों को लेकर उनकी बातचीत चल रही है। इस बीच खबरें हैं कि वह एक और हालीवुड फिल्म करने जा रही हैं। हाल ही में हालीवुड फिल्म द ब्लफ में नजर आई प्रियंका की अगली हालीवुड फिल्म का नाम होगा रीसेट। इस फिल्म में वह पाइरेट्स आफ कैरिबियन और लार्ड आफ रिंग्स फिल्मों के अभिनेता ओर्लान्डो ब्लूम के साथ मुख्य नायिका की भूमिका में होंगी। इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ प्रियंका इससे बतौर को प्रोड्यूसर भी जुड़ेंगी। जबकि फिल्म का निर्देशन मैट स्मक्लर करेंगे। जार्डन रोलिंस द्वारा लिखी इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला पर केंद्रित है, जिसकी आंख खुलती है तो वह स्वयं को जंगल के बीच पाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि वह जंगल में कैसे पहुंची। प्रियंका इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू करेंगी। उनकी इस नई परियोजना से न केवल उनके प्रशंसकों में उत्साह है, बल्कि यह भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के बीच की दूरी को भी कम करने में मदद करेगी।

मलाइका अरोड़ा ने कहा, खुद पर हंसना अच्छा होता है

सितारों की ट्रोलिंग कई बार उन्हें परेशान कर देती है। हालांकि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर ट्रोलिंग का शिकार होने वाली मलाइका अरोड़ा अब इसे गंभीरता से नहीं लेती हैं। वह कहती हैं कि पहले फर्क पड़ता है, लेकिन अब मैंने इसे संभालना सीख लिया है। खुद को बुलेट प्रूफ रखने का मेरा अपना तरीका है। हालांकि मैं झूठ कहूंगी कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कई बार गुस्सा आता है, रोती भी हूं, लेकिन इस पेशे में पिछले 25 वर्षों का अनुभव मदद करता है कि मैं इन बेकार की बातों से खुद को दूर कर लूं। जो चीज मेरी ऊर्जा में खलल डालती है, उसे मैं हटा देती हूं। अब जैसे मेरे चलने के तरीके को बतख की चाल जैसा कहा जाता है। उसको लेकर लेकर ट्रोल किया जाता है। मैं उस ट्रोलिंग पर हंसती हूं। खुद पर हंसना अच्छा होता है। अगर आप अपनी अच्छी बुरी चीजों पर हंसेंगे, तो यह अच्छा होगा, फिर आपको देखकर सामने वाला भी सोचेगा कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वह भी फिर कुछ समय बाद इन चीजों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा।

ट्रोलिंग को अब गंभीरता से नहीं लेती हैं मलाइका। फाइल

जब निर्देशक ने सैफ अली को कहा था कि पुलिस का रोल फिर कभी मत करना

वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा चुके अभिनेता सैफ अली खान अब 15 मई से नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हो रही फिल्म कर्तव्य में एक बार फिर ऐसी ही भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि, एक बार निर्देशक ने उन्हें पुलिस की वर्दी में देख, पुलिस का रोल कभी न करने का सुझाव भी दे दिया था। गुरुवार को फिल्म के ट्रेलर लांच के दौरान सैफ ने इस बारे में बताया, 'ऐसी भूमिकाएं निभाते समय मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं किसी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहा हूं, बल्कि मैं सोचता हूं कि मैं एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहा हूं। हालांकि, वर्दी पहनकर एक अच्छा अहसास होता है, एक जिम्मेदारी आती है। इस फिल्म के लिए हमने काफी सोच समझकर तय किया कि वर्दी किस तरह की होगी। मैंने पहली बार फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में वर्दी पहनी थी। तब मेरे निर्देशक ने कहा था कि प्लीज पुलिस का रोल फिर कभी मत करना, आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि आप बच्चे हो। अगर उसके बाद सेक्रेड गेम्स और इस फिल्म में मेरे निर्देशकों ने कहा कि आपने अच्छा काम किया है, (मुस्कुराते हुए) इसका मतलब अब मैं वहां से थोड़ा बड़ा हो चुका हूं।' इस फिल्म का निर्माण अभिनेता शाह रुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज के अंतर्गत हुआ है। इस दौरान सैफ ने यह भी बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान शाह रुख सेट पर कभी नहीं आए।

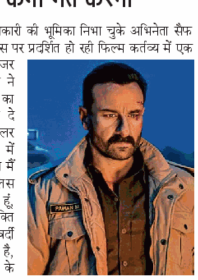

कर्तव्य में पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखेंगे सैफ। (@netflix_in)

डेब्यू से पहले साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुभान को दूसरी फिल्म

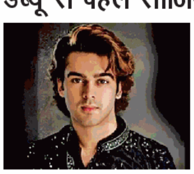

फिल्म ऐसी दीवानगी से पदार्पण करने वाले हैं सुभान। फाइल

हे बेबी, हाउसफुल तथा किक फिल्मों के निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुभान नाडियाडवाला फिल्म ऐसी दीवानगी से हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता पदार्पण करने के लिए तैयार हैं। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुभान के साथ अभिनेत्री कियारा बोस राय मुख्य भूमिका में हैं। सुभान की पहली फिल्म की रिलीज तिथि भी अभी तक सामने नहीं आई हैं, इससे पहले ही उन्हें उनके करियर की दूसरी फिल्म मिल चुकी है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, सुभान दूसरी फिल्म निल बटे सन्नाटा और बरेली की बर्फी फिल्मों की निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ करने जा रहे हैं। इस फिल्म को सुभान के पिता नहीं, बल्कि निर्माता तनुज गर्ग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं इस फिल्म से नितेश तिवारी और मोहित सूरी जैसे दो और स्थापित नाम भी जुड़े हैं। दोनों ने मिलकर इस फिल्म की पटकथा लिखी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले अश्विनी सुभान के साथ कुछ एक्टिंग वर्कशाप करेंगी। उसके बाद उनकी योजना दिसंबर से इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की है।

हर फिल्म को सौ करोड़ कमाने की जरूरत नहीं : रितेश देशमुख

सात सवाल

मराठी सिनेमा में इन दिनों फिल्म राजा शिवाजी का डंका बज रहा है। हिंदी में भी इसे पसंद किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्यगाथा को बड़े पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता-निर्देशक रितेश देशमुख अपनी इस फिल्म की सफलता से उत्साहित हैं। इसकी सफलता और मदर्स डे (10 मई) के खास मौके पर रितेश ने अपनी मां से मिले संस्कारों, छत्रपती शिवाजी महाराज से मिली सीख, फिल्म के दस साल लंबे सफर और सलमान खान संग अपनी दोस्ती पर खुलकर बातचीत की।

@riteishd

@beingsalmankhan

• सलमान खान आपकी फिल्मों में हमेशा मेहमान भूमिका की मांग कर करते हैं। उनसे दोस्ती कैसे शुरू हुई थी?

-सलमान तो मेरे भाई हैं। उनसे अलग ही जुड़ाव है। उनका बड़प्पन है कि वह ऐसा कहते हैं। दरअसल, वह हमेशा मेरे फायदे की ही सोचते हैं, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए सोचता है। मेरी भी आस्था, प्रेम उनकी तरफ छोटे भाई की तरह है। यह रिश्ते सोचकर नहीं बनाए जाते हैं। यह धीरे-धीरे बन जाते हैं, चाहे वह सलमान भाई हों या अभिषेक बच्चन।

• आपको इन दिनों मराठी सिनेमा का धुरंधर कहा जा रहा है...

-मैंने बस छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा पर फिल्म बनाई है। मुझे लगता है कि हम सभी फिल्मकार अपनी ओर से ऐसा सिनेमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जहां तक फिल्मों के कलेक्शन और इन दिनों चल रहे करोड़ों के क्लब्स की बात है, तो हर फिल्म का गणित अलग होता है। बजट के अनुसार उसकी रिकवरी होती है। डिजिटल, सेटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से कुछ रिकवरी हो जाती है, बाकी थिएटर से होती है। यह सब नया नहीं है। मुझे लगता है कि हर फिल्म को हिट होने के लिए सौ करोड़ कमाने की जरूरत नहीं है, उसके बजट पर सब निर्भर करता है।

• आपकी मां ने जब फिल्म देखी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही?

-उन्हें गर्व हुआ कि मैंने यह फिल्म बनाई है। उन्हें फिल्म पसंद आई। उनसे यह मान्यता मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

• मां के कौन से गुण आप खुद में लाने का प्रयास कर रहे हैं?

-उनमें कई गुण हैं। वो कभी हार नहीं मानती हैं। हमेशा सकारात्मक रहती हैं। जब कोई समस्या आती है, तो वह उसे एक मौका मानते हुए सोचती हैं कि कैसे उस समस्या से निकलकर और ऊंचाई तक पहुंचा जाय।

• इस फिल्म को बनाने में दस साल लगे, कभी हिम्मत नहीं टूटी? छत्रपति शिवाजी महाराज से क्या सीखा?

-हां, ऐसा कई बार लगा कि नियति नहीं चाहती ही यह फिल्म बने। फिर साल 2023 में फिर से प्रयास किया। कहानी नए तरीके से लिखी। अच्छा हुआ साल 2016 में यह फिल्म नहीं बनीं, शायद इतनी बड़ी नहीं होती। उस वक्त अलग कहानी थी, अलग तरीके से बनाने वाले थे। जब 2023 में लिखना शुरू किया, तो अपने तरीके से बनाने की कोशिश की। बाकी जहां तक बात सीखने की है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज आस्था हैं। जीवन का पाठ उनसे सीखा जा सकता है। वह सिखाते हैं कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है, तो उसे छोड़ें मत। शिवाजी महाराज जब युद्ध पर जाते थे, तो पहले भांप लेते थे कि वहां की स्थिति क्या है।

• ऐतिहासिक या बायोपिक फिल्में अक्सर विवादों में घिर जाती हैं...

-जब आप ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बनाते हैं, जो भगवान समान है, तो पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ बनाते हैं, ताकि किसी को ठेस न पहुंचे। उनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वह उसी तरीके से उन्हें पर्दे पर देखना चाहते हैं। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कहानी को पिरोया था। इस कहानी को लिखते हुए रिश्तों में सादगी, आस्था, प्रेम भाव होना जरूरी था।

• फिल्म को फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाने का सोचा है? क्या इतना दमदार रोल करने के बाद दूसरे रोल को करने में हिचकिचाहट होगी?

-नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिल्म खत्म होने के बाद उसको नमस्ते करके हम आगे बढ़ जाते हैं। हां, ऐसा हो सकता है कि यह फिल्म करने के बाद कुछ और भी करना चाहूं लेकिन ऐसा नही है कि इसके कारण आगे जाकर कामेडी नहीं करूंगा। जहां तक फ्रेंचाइज की बात है, तो फिलहाल, सोचा नहीं है। दर्शकों की आगे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। फिर उस पर विचार करेंगे। (**स्मिता श्रीवास्तव**)

अब गुल्लक 5 में दिखेंगे नए अन्नू मिश्रा

@anantvjoshi

लोकप्रिय शो 'गुल्लक' के सीजन 5 में अन्नू मिश्रा का किरदार अब वैभव राज गुप्ता की जगह अनंत जोशी निभाएंगे

साल 2019 में प्रदर्शित हुई वेब सीरीज गुल्लक की कहानी लखनऊ के मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। शो में एक आम परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाई गई उससे जुड़ी समस्याएं लोगों को खूब पसंद आई। उसके बाद अलग अलग वर्षों में शो के अगले तीन सीजन भी लोगों को खूब पसंद आए। शो में अभिनेता जमील खान ने संतोष मिश्रा, वैभव राज गुप्ता ने आनंद मिश्रा 'अन्नू', हर्ष मायर ने अमन मिश्रा तथा अभिनेत्री गीतांजलि कुलकर्णी ने शांति मिश्रा की भूमिका निभाई। अब श्रेयांश पांडे निर्देशित इस शो का पांचवा सीजन जल्द ही प्रदर्शित होने वाला है जिसमें कुछ नए पात्रों के साथ पुराने में भी बदलाव दिखेगा। पांचवें सीजन में अन्नू की भूमिका में वैभव राज गुप्ता नहीं होंगे। उनकी जगह अन्नू की भूमिका फिल्म अजेय तथा वेब सीरीज मामला लीगल है के अभिनेता अनंत जोशी निभाएंगे। इस भूमिका को लेकर उत्साहित अनंत का कहना है, 'गुल्लक हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है क्योंकि मिश्रा परिवार मुझे हमारे अपने परिवार, उनके प्यार और उस सादगी की याद दिलाता है। मैं लंबे समय से इस शो का फैन रहा हूं, इसलिए अब इसका हिस्सा बनना सच में खास लग रहा है। अन्नू भैया के सफर में कदम रखना मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव रहा है, क्योंकि यह सीजन उनकी जिंदगी के बदलते पहलू को दिखाता है।'